

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj )**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

33071

# केन्द्रीय विक्री-कर अधिनियम १९५४

( CENTRAL SALES TAX ACT 1956 )

( As Amended up to date )

लेखक

प्रो० एम० एल० अग्रवाल

एम० कॉम्प०, बी० ए० कॉम्प०

अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग,

अग्रवाल कॉलेज, जयपुर

सदस्य, फैंकल्टी ऑफ कॉमर्स,

राजस्थान विद्वद्विद्यालय, जयपुर

१९६२



साहित्य भवन

शिक्षा सम्बन्धी साहित्य के प्रकाशक

आगरा

## प्राक्कथन

=====

‘केन्द्रीय द्विकी-त्र अभिनियम’ नामक यह पुस्तक विश्वविद्यालयों के बी० कॉम० के छात्रों की सुविधा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यापारी वर्ग के लिये लिखी गई है। इस विषय पर हिन्दी भाषा में अभी तक कोई पुस्तक नहीं लिखी गई है तथा अंग्रेजी भाषा में भी ऐसी कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है जो कि बी० कॉम० के विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरी कर सके। अतः इस कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से यह पुस्तक प्रस्तुत की जा रही है।

पुस्तक में त्रुटियों का होना स्वाभाविक है। पाठकों से नम्र निवेदन है कि वे पुस्तक की त्रुटियों के सम्बन्ध में लेखक का ध्यान आकर्षित करते रहे।

लेखक

# विषय-सूची

=====

अध्याय १.	अधिनियम का परिचय तथा उसके उद्देश्य	१-५
	संक्षिप्त शीर्षक तथा सर्व अधिनियम के लागू होने की तिथि, संक्षिप्त इतिहास, अधिनियम के उद्देश्य ।	
अध्याय २.	परिभाषाएँ	६-१३
	उपयुक्त राज्य, व्यापारी, घोषित माल, माल, व्यवसाय का स्थान, बिक्री-मूल्य, बिक्री-कर कानून, विक्रय राशि, वर्ष ।	
अध्याय ३.	बिक्री व खरीद के स्थान-निर्धारण के सिद्धान्त	१४-२०
	अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत माल की बिक्री व खरीद, राज्य के बाहर माल की बिक्री व खरीद, आयात अथवा निर्यात के अन्तर्गत बिक्री या खरीद ।	
अध्याय ४.	अन्तर्राज्यीय बिक्री-कर	२१-२८
	अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर देने का दायित्व, केन्द्रीय बिक्री कर की दर ।	
अध्याय ५.	व्यापारियों का पंजीयन	२९-३३
अध्याय ६.	कर-आरोपण, कर-वसूली तथा अर्थ-दण्ड	३४-३६
	कर-आरोपण व कर-वसूली, केवल पंजीयत व्यापारियों द्वारा कर की वसूली, अर्थ-दण्ड, अभियोग चलाने के अर्थ-दण्ड लगाना, हस्तक्षेप अपराध, हानि-रक्षा ।	
अध्याय ७.	नियम	४०-५४
	नियम बनाने की शक्ति, केन्द्रीय बिक्री-कर (पंजीयन एवं विक्रय-राशि) नियम १९५७, केन्द्रीय बिक्री-कर (राजस्थान) नियम १९५७ ।	
अध्याय ८.	अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य में विशेष महत्व का माल	५५-५८
	धारा १४—विशेष महत्व के माल की सूची ।	
	धारा १५—एक राज्य के अन्दर घोषित माल की बिक्री व खरीद पर कर से सम्बन्धित प्रतिबन्ध व शर्तें ।	

## अधिनियम का परिचय तथा उसके उद्देश्य (Introduction of the Act and its Objects)

**संक्षिप्त शीर्षक तथा क्षेत्र (Short Title and Extent)**—यह अधिनियम केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम १९५६ कहलाता है तथा समस्त भारत में लागू होता है। सन् १९५६ में, जब यह अधिनियम प्रथम बार भारत में लागू किया गया था, उस समय यह जम्मू तथा काश्मीर राज्य व छोड़ कर समस्त भारत में लागू होता था परन्तु सन् १९५८ के संशोधन अधिनियम द्वारा इस अधिनियम के क्षेत्र में जम्मू व काश्मीर राज्य भी सम्मिलित कर लिया गया है।

**अधिनियम के लागू होने की तिथि (Date of Commencement of the Act)**—अधिनियम की धारा ६ व धारा १५ को छोड़कर शेष अधिनियम सामान्य रूप से ५ जनवरी १९५७ से लागू किया गया। धारा ६-१ जुलाई १९५७ से तथा धारा १५-१ अक्टूबर १९५७ से लागू की गयी।

### बिक्री कर का संक्षिप्त इतिहास (Brief History of Sales Tax Act)

प्रथम विश्व-युद्ध द्वारा उत्पन्न अर्थ-संकट को दूर करने के लिये, सर्वप्रथम यूरोपियन देशों बिक्री कर लगाया जिनमें फ्रांस प्रथम था। भारत में 'भारत सरकार अधिनियम १९३५' के अन्तर्गत सर्व प्रथम मद्रास प्रांत की सरकार ने यह कर सन् १९३६ में लागू किया। इसके पश्चात् यह कर अन्य प्रान्तों में भी धीरे-धीरे अपनाया गया।

'भारत सरकार अधिनियम १९३५' के अन्तर्गत जब विभिन्न प्रान्तों की सरकारों ने अलग-अलग बिक्री कर अधिनियम बना लिये थे तब अन्तराज्यीय व्यापार (Inter-state trade) प्रयुक्त होने वाले एक ही साल की बिक्री पर अलग-अलग प्रान्तों द्वारा जो भी किसी न किसी उस बिक्री से सम्बन्धित थे, बिक्री कर लगाया जाने लगा। इसका फल यह हुआ कि उत्पादित माल लागत बहुत बढ़ने लग गयी। उदाहरण के लिये, भारत सरकार टाटा नगर से रेलवे के लिये रेल पटरियाँ खरीदती थी। उसे बिहार सरकार को इसलिये कर देना पड़ता था कि पटरियाँ उस प्रांत बनती थी, बंगाल सरकार को इसलिये कर देना पड़ता था कि कम्पनी का मुख्य कार्यालय कलकत्ते में था और इसलिये वह बिक्री कलकत्ते में हुई मानी जाती थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रान्त की सरकार को इसलिये कर देना पड़ता था कि उन पटरियों की सुपुर्दगी उस प्रान्त में हुई। अतः एक ही वस्तु पर कई प्रान्तों द्वारा अपने-अपने अधिनियम के अनुसार बिक्री कर वसूल किया जाता था।

जब भारत का संविधान बना जो कि २६ जनवरी १९५० को लागू हुआ तब उसके अनुच्छेद २८६ द्वारा उपरोक्त कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया गया। परन्तु अन्तर्नियम २८६ में दी गयी बातें कुछ सीमा तक एक दूसरे के विपरीत पड़ती थी। अतः सन् १९५६ में संविधान के इस अनुच्छेद में

८६ में सशोधन करना पड़ा। उस सशोधन के फलस्वरूप केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम का बनाना आवश्यक हो गया। इस कारण सन् १९५६ में संसद ने केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम पास किया।

सन् १९५६ के सशोधन से पूर्व अन्तर्नियम २८६ की स्थिति

सन् १९५६ के सशोधन से पूर्व अन्तर्नियम २८६ की स्थिति निम्न प्रकार थी\* :—

२८६ (१)—एक राज्य का कोई भी कानून माल की बिक्री पर कर नहीं लगायेगा और न रखाना अधिकृत ही करेगा यदि ऐसी बिक्री या खरीद :—

(घ) राज्य के बाहर होती हो, या

(ङ) भारतीय सीमा में माल के आवात के अन्तर्गत अथवा भारतीय सीमा से माल के निर्यात के अन्तर्गत होती हो।

स्पष्टीकरण (घ) उप-वाक्य के प्रयोजनार्थ, बिक्री या खरीद उस राज्य में हुई मानी गयेगी जिस राज्य में ऐसी बिक्री या खरीद के प्रत्यक्ष फलस्वरूप माल की सुपुर्दगी उसी राज्य में प्रयोग के लिये की गयी हो, चाहे माल को बिक्री से सम्बन्धित सामान्य कानून के अन्तर्गत, ऐसी बिक्री या खरीद के कारण माल का स्वामित्व दूसरे राज्य में पहुँच गया हो।

(२) सिवाय उन सीमाओं के जिनको संसद कानून के द्वारा नियत करे, एक राज्य का कोई भी कानून माल की बिक्री व खरीद पर कर नहीं लगायेगा और न कर लगाना अधिकृत करेगा यदि सी बिक्री या खरीद अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के अन्तर्गत होती हो।

286 (1) No law of a State shall impose or authorise the imposition of a tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place —

(a) outside the State, or

(b) in the course of import of the goods into, or export of the goods out of the territory of India.

**Explanation** For the purposes of sub-clause (a) a sale or purchase shall be deemed to have taken place in the State in which the goods have actually been delivered as a direct result of such sale or purchase for the purpose of consumption in that State, notwithstanding the fact that under the general law relating to sale of goods, the property in the goods has by reason of such sale or purchase passed in another State.

(2) Except in so far as Parliament by law otherwise provide, no law of State shall impose or authorise the imposition of a tax on the sale or purchase of any goods where such sale or purchase takes place in the course of inter State trade or commerce. Provided that the President may by order direct that any tax on the sale or purchase of goods which was being lawfully levied by the Government of any State immediately before the commencement of the constitution shall, notwithstanding that the imposition of such tax is contrary to the provisions of this clause, continue to be levied until 31-3-1951.

(3) No law made by the legislature of a State imposing, or authorising the imposition of, a tax on the sale or purchase of any such goods as have been declared by parliament by law to be essential for the life of the community shall have effect unless it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent.

परन्तु राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा निर्देश कर सकता है कि माल की बिक्री या खरीद व कोई भी कर जो कि इस सविधान के आरम्भ होने के तत्काल पूर्व किसी राज्य की सरकार द्वारा वैधानिक रूप से लगाया जा रहा था, ३१ मार्च १९५१ तक लगाया जाना जारी रखा जायेगा चाहे कर का लगाया जाना इस वाक्य के प्रावधानों के विपरीत ही पड़ता हो ।

(३) एक राज्य की विधान सभा द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो कि किसी ऐसे की बिक्री व खरीद पर कर लगाता हो अथवा कर लगाना अधिकृत करता हो, जिसे सदन ने कानून समाज के जीवन के लिये आवश्यक घोषित कर दिया हो, प्रभावशाली नहीं होगा जब तक कि कानून राष्ट्रपति के विचार के लिये सुरक्षित न रखा गया हो तथा उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति ले ली गयी हो ।

इस अन्तर्नियम २८६ की जो बातें एक दूसरे के विपरीत पड़ती थी वे वाक्य (२) तथा वाक्य (१) के स्पष्टीकरण से सम्बन्धित थी । वाक्य (२) के अनुसार एक राज्य के लिये, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत माल की बिक्री व खरीद पर, कर लगाना निषेध था, परन्तु वाक्य १ स्पष्टीकरण इस प्रकार की बिक्री व खरीद पर कर लगाने का अवसर प्रदान करता था क्योंकि स्पष्टीकरण के अनुसार वह राज्य कर लगा सकता था जहाँ उस माल के उपभोग के लिये सुपुर्गई गई हो ।

बम्बई राज्य Vs. सी यूनाइटेड मोटर्स (इंडिया) लिमिटेड, १९५३ के मामले में सुप्रीम ने यह निर्णय दिया कि वाक्य १ के उपवाक्य (अ) तथा वाक्य १ के स्पष्टीकरण के अनुसार केवल वही एक राज्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत माल की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार रखना जिस राज्य में वह माल उसी के उपभोग के लिये सुपुर्ग किया गया हो, तथा वाक्य (२) ऐसे पूर्व का राज्य पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बिक्री पर कर लगाने के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता, चाहे कि उस राज्य को इस प्रकार का कर लगाने की अनुमति नहीं दी हो ।

परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह निर्णय 'बंगाल इन्ड्युनिटी कम्पनी लिमिटेड Vs. बिहार राज १९५५' के मामले में बदल दिया ।

इस मामले में यह निर्णय दिया गया कि अन्तर्नियम २८६ का वास्तविक उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत माल की बिक्री व खरीद के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा कर लगाने प्रतिबन्ध लगाने से है । राज्यों पर वह प्रतिबन्ध उस समय तक है जब तक कि वह प्रतिबन्ध सख्त वाक्य (२) के अनुसार हटा न दिया जाय । जहाँ तक आयात व निर्यात के अन्तर्गत माल की बिक्री खरीद का सम्बन्ध है, कोई भी राज्य उस बिक्री व खरीद पर कर नहीं लगा सकता । निर्णय में यह कहा गया कि जो स्पष्टीकरण है, वह वाक्य (२) पर प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि यह तो वाक्य (१) स्पष्टीकरण है । परन्तु जब वाक्य (२) के अन्तर्गत सदन किसी राज्य पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लगाने वाले प्रतिबन्ध को हटा लेती है तब वह स्पष्टीकरण यह निश्चित करने में काम आता है कि कौनसा राज्य उस दशा में कर लगाने का अधिकारी होगा ।

उपरोक्त निर्णय से परिस्थिति बहुत बदल गयी । राज्यों ने सामने यह समस्या उपस्थित की कि जो कर उनके द्वारा लगाये व वसूल किये जा चुके थे, उन्हें निरस्त व वापिस किया जाय । दूसरे जो बजट राज्यों द्वारा पास किये जा चुके थे, उनमें हेर-फेर किया जाय । इनके अतिरिक्त कुछ वैधानिक नठिनाइयाँ भी उपस्थित हुई ।

राज्य सरकारों की इन कठिनाइयों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने संसद द्वारा बिक्री कर नूतन मान्यता अधिनियम १९५६ (Sales Tax Laws Validation Act, 1956) पास कराया। इस अधिनियम के अनुसार १ अप्रैल १९५१ से ६ सितम्बर १९५६ तक राज्यों ने अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत माल की बिक्री पर जो कर लगाये थे और वसूल किये थे, वे वैधानिक रूप से ठीक न लिये गये।

### शोधन के पश्चात् अन्तर्नियम २८६ की स्थिति

भविष्य की वैधानिक कठिनाइयों को दूर करने के हेतु सन् १९५६ में संविधान के अन्तर्नियम २६ में संशोधन किया गया। संशोधन के फलस्वरूप\*

(१) वाक्य का स्पष्टीकरण लोप (delete) कर दिया गया,

(२) वाक्य २ इस प्रकार प्रतिस्थापित किया गया —

‘संसद यह निर्णय करने के लिये कानून द्वारा सिद्धांत निर्धारित कर सकती है कि वाक्य (१) में लिखित किसी भी रूप में माल की बिक्री व खरीद हुई वच समझी जाय।

(३) वाक्य ३ निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया गया —

“एक राज्य का कोई भी कानून, जहाँ तक कि वह ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाता है अथवा कर लगाना अधिकृत करता है जो कि संसद द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य में विशेष महत्व के घोषित किये गये हों, कर-रोपण, कर की दर तथा कर की अन्य बातों के सम्बन्ध में ऐसे प्रतिबन्धों व शर्तों के आधीन होगा जो कि संसद कानून के द्वारा निर्धारित करे।”

इस संशोधन के द्वारा संसद को निम्नलिखित बातों से सम्बन्धित कानून बनाने को कहा गया—

(१) सिद्धान्त निर्धारित करने के लिये कि वाक्य १ की दोनों अवस्थाओं में माल की बिक्री या खरीद कब हुई मानी जायगी,

(२) अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत विशेष महत्व वाले माल को घोषित करने के लिये, तथा

(३) ऐसे विशेष महत्व वाले माल के सम्बन्ध में यह निर्दिष्ट करने के लिये कि एक राज्य द्वारा लगाया गया कर किन प्रतिबन्धों व शर्तों के आधीन होगा।

286 (1) No law of a State shall impose, or authorise the imposition of a tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place —

(a) outside the State, or

(b) in the course of the import of the goods into, or export of the goods out of the territory of India.†

(2) Parliament may by law formulate principles for determining when a sale or purchase of goods takes place in any of the ways mentioned in clause (1) \*

(3) Any law of a State shall, in so far as it imposes or authorises the imposition of a tax on the sale or purchase of goods declared by Parliament by law to be of special importance in inter-State trade or commerce, be subject to such restrictions and conditions in regard to the system of levy, rates and other incidents of the tax as Parliament may by law specify.\*

† Explanation to cl (1) omitted by the Constitution (Sixth Amendment) Act 1956, S 4

\* Subs., Ibid. for the original cls. (2) and (3).



## केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम के उद्देश्य (Objects of the Central Sales Tax Act, 1956)

केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम १९५६ के बनाने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(१) निम्नलिखित बातों के निर्धारण के लिये सिद्धान्त निश्चित करना —

(अ) अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत माल की बिक्री व खरीद कब और किन अवस्थाओं में मानी जाये।

(आ) राज्य के बाहर माल की बिक्री व खरीद कब और किन अवस्थाओं में हुई समझी जाय।

(इ) भारत में आयात व भारत से निर्यात के अन्तर्गत माल की बिक्री व खरीद कब और किन अवस्थाओं में हुई मानी जाय।

उपरोक्त तीनों बातों के सम्बन्ध में सिद्धान्तों का निर्धारण करना इसलिये आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार को केवल अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य में प्रयोग होने वाले माल पर बिक्री-कर लगाने का अधिकार है जबकि राज्यों की सरकारों को उपरोक्त तीन बातों में से किसी एक पर भी बिक्री-कर लगाने का अधिकार नहीं है। एक राज्य को उस माल की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार है जिसकी बिक्री उसी राज्य के अन्तर्गत हुई हो। अतः यह जानना आवश्यक हो जाता है कि माल का क्रय विक्रय राज्य के बाहर होना कब समझा जायेगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक राज्य उसी माल की बिक्री पर कर लगा सकता है जो कि निम्नलिखित अवस्थाओं में नहीं हुई हो।—

(१) चूंकि अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत, (२) राज्य के बाहर तथा (३) भारत में आयात व भारत से निर्यात के अन्तर्गत।

(२) चूंकि अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत माल की बिक्री व खरीद पर बिक्री-कर लगाना केन्द्रीय सरकार के अधिकार में है, इसलिये इस अधिनियम द्वारा उस सम्बन्ध में कर लगाने, कर वसूल करने व कर का वितरण करने के विषय में नियम बनाना।

(३) अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य में प्रयोग होने वाले कुछ प्रकार के माल को 'विशेष महत्व' का घोषित करना तथा उन विशेष महत्व वाले माल के सम्बन्ध में वे शर्तें तथा प्रतिबन्ध निर्धारित करना जिनके अनुसार एक राज्य ऐसे माल की बिक्री व खरीद पर कर लगाने के लिये अपने नियम बना सके।

उपरोक्त तीन उद्देश्य केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम १९५६ के आमुख (Preamble) में दिये गये हैं।

## परिभाषाएँ (Definitions)

अधिनियम का धारा २ में जो महत्वपूर्ण परिभाषाएँ दी हुई हैं उनका विवेचन निम्नलिखित है —

### (१) उपयुक्त राज्य (Appropriate State)

(अ) यदि किसी व्यापार के व्यवसाय के एक या अधिक स्थान एक ही राज्य में स्थित हैं तो उस व्यापारी के लिए उपयुक्त राज्य वही होगा जहाँ पर उसके व्यवसाय के स्थान स्थित हैं।

(आ) यदि किसी व्यापारी के व्यवसाय के स्थान विभिन्न राज्यों में स्थित हैं तो प्रत्येक व्यवसाय के स्थान के लिए उपयुक्त राज्य वह होगा जिसमें उसका व्यवसाय का स्थान स्थित है। इस प्रकार उसके भिन्न भिन्न व्यवसाय के स्थान के हिसाब से उसका उपयुक्त राज्य भिन्न भिन्न होगा।

उदाहरण — (१) यदि श्री मुकुन्दलाल जी का व्यवसाय जयपुर, जोधपुर व उदयपुर में स्थित है, तो उनका उपयुक्त राज्य राजस्थान होगा।

(२) यदि उनके व्यवसाय के स्थान कानपुर, जयपुर व पटना में स्थित हैं तो कानपुर के व्यवसाय के लिए उपयुक्त राज्य उत्तर प्रदेश जयपुर के व्यवसाय के लिए राजस्थान तथा पटना के व्यवसाय के लिए बिहार राज्य होंगे।

उपयुक्त राज्य का महत्व—(१) धारा ७ के अनुसार प्रत्येक व्यापारी के लिए जो कि केन्द्राय विक्री कर अदा करता है, यह आवश्यक है कि वह 'उपयुक्त राज्य' में अपना पंजीयन (Registration) कराये।

(२) धारा ६ व अनुसार केन्द्राय विक्री-कर के लगाने व वसूल करने के अधिकार केन्द्राय सरकार का धोर से उपयुक्त राज्य का हाँ सौंप दिया जाता है। यद्यपि अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य में उपयोग होने वाले मान पर विज्ञा कर लगाने का अधिकार केन्द्राय सरकार का हाँ होता है, परन्तु उस कर का वसूल करने का काम केन्द्राय सरकार की धोर से उपयुक्त राज्य के अधिकारी ही करते हैं।

### (Dealer)

धारा २ के अनुसार व्यापार का अर्थ ऐसे व्यक्ति में है जो कि मान के वस्तु विक्रय का व्यवसाय करता है। व्यापार शब्द में वह सरकार या एमई करता है, सम्मिलित है।

'व्यापार' शब्द बड़े महत्व का शब्द है क्योंकि जो बिना कर लगाया जाता है वह व्यापार पर ही लगाया जाता है। अतः ना व्यक्ति व्यापार नहीं है, उस पर विज्ञा कर नहीं लगाया जा सकता है।

किसी को व्यापारी घोषित करने के लिए तीन शर्तों का पूरा होना आवश्यक होता है .—

- (अ) वह व्यक्ति (Person) हो,
- (ब) माल का क्रय विक्रय करता हो, तथा
- (स) ऐसा क्रय-विक्रय अपने व्यवसाय के रूप में करता हो ।

### व्यक्ति (Person)

इस अधिनियम में व्यक्ति शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है परन्तु आयरलैंड अधिनियम १९६१ की धारा २ (११) के अनुसार व्यक्ति (Person) शब्द में निम्नलिखित सम्मिलित किये जाते हैं —

- (i) अकेला व्यक्ति (Individual),
- (ii) एक हिन्दू अविभाजित परिवार,
- (iii) एक कम्पनी,
- (iv) एक फर्म,
- (v) व्यक्तियों की परिषद् ( Association of persons ) या अकेले व्यक्तियों की संस्था ( A body of individuals ) चाहे सम्मिलित हो अथवा न हो,
- (vi) एक स्थानीय सरकार ( A local authority ),
- (vii) प्रत्येक कृत्रिम व न्यायिक व्यक्ति ( Every artificial juridical person ) जो कि उपरोक्त उपाधियों में सम्मिलित न किया गया हो ।

व्यापारी होने के लिए यह आवश्यक है कि उसने माल का क्रय तथा विक्रय किया हो और उस माल का क्रय-विक्रय करना उसका व्यवसाय हो । यदि कोई वकील देहली से अपने मित्र के लिए घड़ी खरीदता है और जयपुर में उस घड़ी को अपने मित्र को बेच देता है तो वह व्यापारी नहीं है क्योंकि घड़ी खरीदना और बेचना उसका व्यवसाय नहीं है ।

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो क्रय विक्रय का व्यवसाय किया जाय, वह लाभ कमाने के उद्देश्य से ही होना चाहिए । यदि क्रय तथा विक्रय के पीछे लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है तो वह क्रेता तथा विक्रेता व्यापारी नहीं है । कैनन डकरले एण्ड कम्पनी<sup>१</sup> के मामले में, इजीनियरो को एक-एक फर्म अपने अधिकारी को लाभ रहित मूल्य पर अनाज दिया करती थी और उस अनाज का मूल्य अधिकारी की मजदूरी में से काट लेती थी । यह तय किया गया कि फर्म व्यापारी नहीं है ।

श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड<sup>२</sup> के मामले में, करदाता कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए लाभहीन उद्देश्य से कैंटीन चलाता था । उसे व्यापारी नहीं ठहराया गया ।

‘व्यवसाय’ शब्द की इस अधिनियम में कोई परिभाषा नहीं दी गई है परन्तु सामान्यतया व्यवसाय (Business) शब्द व्यापार (Trade) शब्द से बहुत अधिक व्यापक है । ‘व्यापार’ का अर्थ लाभ कमाने के उद्देश्य से क्रय-विक्रय करना है जबकि व्यवसाय शब्द में वाणिज्य व उद्योग दोनों सम्मिलित हैं । व्यापार वाणिज्य का एक अंग है । वाणिज्य के अन्तर्गत व्यापार के अतिरिक्त यातायात, गोदाम व अर्थ पूर्ति करने वाली संस्थाओं की क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं । वाणिज्य व्यवसाय का एक अंग है, परन्तु इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारी की परिभाषा में जो ‘व्यवसाय’ शब्द प्रयोग किया गया है वह माल के क्रय तथा विक्रय तक ही सीमित रखा गया है । अतः व्यापारी कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि वह लाभ कमाने के उद्देश्य से क्रय व विक्रय का व्यवसाय करता हो ।

1. Cannon Dunkerley & Co (Madras) Ltd Vs The State of Madras (1954)  
 -2 Sree Meenakshi Mills Ltd. Vs The State of Madras (1954)

## क्या निम्नलिखित व्यक्ति व्यापारी हैं ?

(i) कपड़ा रगने वाला—यदि एक कपड़ा रगने वाला ग्राहक द्वारा साये हुये कपड़े को रग कर देता है और उसके बदले में अपनी मजदूरी लेता है, तो वह व्यापारी नहीं है।<sup>१</sup> परन्तु यदि वह रगरेज स्वयं कपड़ा खरीद कर तथा रग कर ग्राहक को बेचता है तो वह व्यापारी कहलायेगा।

(ii) मुद्रक (Printer)—एक मुद्रक जो ग्राहक द्वारा दिये गये कामजो पर छपाई करता है, व्यापारी नहीं है।<sup>२</sup> यदि वह स्वयं कामजो खरीदकर छपाई कर ग्राहक को बेचता है तो वह व्यापारी कहलायेगा।

(iii) ऋण देने वाला साहूकार—ऋण देने वाला साहूकार व्यापारी नहीं है।<sup>३</sup>

(iv) दलाल (Broker)—एक दलाल जो कि दलाली के बदले में क्रेता और विक्रेता को मिलाता है, व्यापारी नहीं है क्योंकि वह स्वयं क्रय-विक्रय नहीं करता है।<sup>४</sup>

(v) कमीशन एजेंट—एक व्यक्ति जो कमीशन के बदले में तथा एजेंट के रूप में माल के क्रय विक्रय का व्यवसाय करता है, व्यापारी है। एक कमीशन एजेंट जो माल को अपने या दूसरे के नाम में बेचता है, व्यापारी है बशर्तें माल उसके कब्जे में हो तथा उस माल को बेचने का उसको अधिकार प्राप्त हो।<sup>५</sup>

एक दलाल कभी भी माल पर कब्जा व आधिपत्य नहीं रखता, इसलिए वह व्यापारी नहीं है।<sup>६</sup>

पक्का आदतिया सर्वदा व्यापारी होता है। परन्तु कच्चे आदतियों के सम्बन्ध में कुछ राज्यों के अधिनियमों ने उसे बिक्री कर से छूट दी हुई है बशर्तें कि वे इस सम्बन्ध में शुल्क देकर साइसेस प्राप्त करले। कच्चा आदतिया एक दलाल की तरह ही होता है, वह माल के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं करता है क्योंकि माल पर उसका कोई आधिपत्य नहीं होता। वह तो केवल क्रेता व विक्रेता को मिलाता है और उसकी बशर्तें में कमीशन लेता है। परन्तु वे आदतिये जो अपने नियोक्ता (Principal) की ओर से बेचने व रुपया वसूल करने का अधिकार रखते हैं व्यापारी कहलाते हैं।

(vi) डाक्टर—एक डाक्टर जो रोगियों का निरीक्षण करके दवा देता है, व्यापारी नहीं है क्योंकि वह विक्रेता नहीं है।<sup>७</sup> परन्तु यदि कोई डाक्टर रोगियों का इलाज करने के साथ-साथ दवाइयाँ भी बेचता है, अर्थात् विक्रय के लिये दवाइयों का स्टॉक रखता है, तो ऐसी दवाइयों के विक्रय के लिये व्यापारी कहलायेगा।

(vii) कृषक (Agriculturist)—एक कृषक जो अपने खेत में अनाज पैदा करता है और अपनी आवश्यकता पूरी करने के पश्चात् अधिक अनाज को बाजार में बेचता है, तो वह व्यापारी नहीं है क्योंकि अनाज का क्रय-विक्रय करता उसका व्यवसाय नहीं है।<sup>८</sup>

(viii) मीलामकर्ता (Auctioneer)—मीलामकर्ता 'व्यापारी' होता है क्योंकि वह माल का विक्रय करता है। मीलाम किये जाने वाले माल उससे आधिपत्य में रहता है और उसे माल को बेचने का अधिकार प्राप्त रहता है।

1. Chauthmal Champalal of Nagpur Vs The State (19०2)
2. Rajasthan Printing and Litho Works Ltd In Re (19०2)
3. The State of Madras Vs N R K Gounder & Sons (19०4)
4. C. P. Coal Trading & Distributing Co Vs Comm of Sales Tax (1954)
5. Kandula Radhakrishna Rao & Others Vs The Province of Madras (1932)
6. Dinanath Mahadev Dalal of Nagpur Vs The State (19०2)
7. J. P. Dixit Vs The State (19०2)
8. Raja Visheshwar Vs Province of Bihar (1951)

(ix) कलाकार (Artist)—यदि एक चित्रकार तथा फोटोग्राफर किसी ग्राहक के लिये चित्र बनाते हैं तो वे व्यापारी नहीं हैं। यदि एक फोटोग्राफर आयात किये गये सामान को बेचता है तो उस पर उसे बिक्री कर देना पड़ेगा।<sup>1</sup>

(x) ठेकेदार (Contractor)—एक ठेकेदार जो किसी बाँध की मरम्मत के लिये श्रमिक प्रदान करता है, व्यापारी नहीं है चूँकि उसने कोई माल नहीं बेचा।<sup>2</sup>

(xi) दर्जी (Tailor)—एक दर्जी जो ग्राहक को द्वारा दिये गये कपड़े को सिलाई करता है, व्यापारी नहीं है। परन्तु यदि वह स्वयं कपड़ा खरीद कर सिलाई करके वस्त्र बनाता है और उनको बेचता रहता है तो वह व्यापारी कहलायेगा।

(xii) आकस्मिक विक्रेता (Casual Seller)—आकस्मिक विक्रेता व्यापारी नहीं होता। क्योंकि विक्रय करना उसका व्यवसाय नहीं होता।

Mistry Dayabhai Kesurbhai Vs. The State of Bombay के मामले में निर्णय किया गया कि यदि कर्नोचर का निर्माता आकस्मिक रूप से चीनी के बर्तन (Crochery) बेचता है तो चीनी के बर्तनों की बिक्री पर उसे कर नहीं देना पड़ेगा।

इसी प्रकार Deputy Commissioner of Commercial Taxes, Coimbatore Division Vs. Sri Lakshmi Saraswati Motor Service, Gudiyattam (1954) के मामले में यह निर्णय किया गया कि यदि एक मोटर ट्रान्सपोर्ट सर्विस कम्पनी अपनी अयोग्य बसों को बेचती है तो वह कम्पनी उस बिक्री के लिये व्यापारी नहीं है।

### ‘घोषित माल’ (Declared Goods) 1964

घोषित माल का अर्थ उस माल से है जो कि धारा १४ के अन्तर्गत विशेष महत्व के घोषित किये गये हैं तथा जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य में प्रयोग होते हैं।

विधान अन्तर्नियम २८६ के वाक्य (३) के अनुसार संसद को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य में प्रयोग होने वाली विशेष महत्व की वस्तुओं की घोषित करने का अधिकार दिया गया है तथा उन वस्तुओं के सम्बन्ध में ऐसे प्रतिबन्ध व शर्तें लगाने का अधिकार दिया गया है जिनके अनुसार ही विभिन्न राज्य उन पर कर लगा सकें। अतः इस अधिकार का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम में धारा १४ के अन्तर्गत घोषित माल की सूची दी हुई है तथा धारा १५ के अन्तर्गत वे प्रतिबन्ध व शर्तें दी हुई हैं जिनके अनुसार प्रत्येक राज्य उस माल पर कर लगा सकता है।

### (४) माल (Goods)

माल शब्द में सभी प्रकार की सामग्री, वस्तुएँ जिस पदार्थ (Commodities) तथा अन्य सभी प्रकार की चल सम्पत्ति सम्मिलित की जाती है परन्तु इसमें समाचार-पत्र, अभियोग के योग्य दावे (Actionable claims), स्कन्ध (Stocks), पूँजी अथवा प्रतिभूतियाँ सम्मिलित नहीं की जाती हैं।

बिक्री कर के सम्बन्ध में ‘माल’ का अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी ऐसी वस्तु के क्रय विज्ञय पर जो कि ‘माल’ नहीं है, बिक्री कर नहीं लग सकता है।

भारत के संविधान के अन्तर्नियम ३६६ (१२) के अनुसार माल की परिभाषा निम्नलिखित है :—

“माल शब्द में सभी सामग्री, जिस पदार्थ तथा वस्तुएँ सम्मिलित की जाती हैं।” माल की बिक्री अधिनियम १९३० के अनुसार माल की परिभाषा निम्नलिखित है :—

1 D Masanda & Co. Vs Com of Sales Tax (1937).

2 Krishna Chandra Acharya Vs the Board of Revenue, Orissa (1935)

“माल का अर्थ अभियोग के योग्य दावे तथा मुद्रा को छोड़कर, प्रत्येक प्रकार की चल सम्पत्ति है और इसमें स्वयं व पूर्ण अथ, जमीन की फसलें, घास एवं अन्य वस्तुएँ जो भूमि से संलग्न हो या भूमि का अंग हो और जिनको विजय के पूर्व अथवा विक्रय अनुबन्ध के अधीन अलग करने का उद्देश्य र लिया हो, सम्मिलित हैं।”

अतः केन्द्रीय विक्री-कर अधिनियम में जो परिभाषा ‘माल’ की दी गयी है, वह अन्य उपरोक्त परिभाषाओं से भिन्न है।

चल सम्पत्ति का अर्थ उस सब सम्पत्ति से है जो कि अचल नहीं है। अचल सम्पत्ति के अन्तर्गत भूमि, भूमि से संलग्न वस्तुएँ या वे वस्तुएँ जो कि स्थायी रूप पृथ्वी से बांधकर जोड़ दी गई हो, सम्मिलित होती हैं। परन्तु ऐसी वस्तुएँ जो भूमि से जुड़ी हुई हैं परन्तु विक्री के पूर्व जिनको भूमि से अलग कर लिया जाता है तो उन वस्तुओं को जो कि अलग की जा चुकी हैं, माल कहा जाता है क्योंकि अब वे चल सम्पत्ति में गिनी जाते हैं।

अभियोग योग्य दावे वे होते हैं जिनको सम्पन्न कराने के लिये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धानिक दृष्टि से वाध्य कर सकता है जैसे ऋण।

माल की विक्री अधिनियम १९३० के अनुसार मुद्रा माल नहीं है परन्तु विक्री कर अधिनियम के अनुसार मुद्रा भी माल की श्रेणी में गिनी जाती है।

#### ५) व्यवसाय का स्थान (Place of Business)

व्यवसाय के स्थान में निम्नलिखित सम्मिलित हैं —

- (१) यदि एक व्यापारी एक एजेंट द्वारा व्यवसाय करता है, तो उस एजेंट के व्यवसाय का स्थान,
- (२) एक सप्ताहागर या गोदाम या कोई अन्य स्थान जहाँ एक व्यापारी अपने माल का सप्लाई करता हो, तथा
- (३) एक स्थान जहाँ व्यापारी अपनी हिसाब-किताब की पुस्तकें रखता हो।

#### ६) विक्री (Sale)

विक्री का अर्थ रोकट अथवा स्वयं अदायगी या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले कि वस्तु से दूसरे व्यक्ति को माल के स्वामित्व के हस्तान्तरण से है। विक्री शब्द के अन्तर्गत ‘भाड़े पर क्रय’ पद्धति या अन्य प्रभाग भुगतान पद्धति पर माल का हस्तान्तरण सम्मिलित होता है परन्तु इसमें माल की गिरवी, बन्धक अथवा रहन सम्मिलित नहीं होती।

विक्री के लिये निम्नलिखित ३ तत्व आवश्यक हैं —

- (अ) माल के स्वामित्व का हस्तान्तरण होना चाहिये,
- (ब) हस्तान्तरण व्यापार व व्यवसाय के बीच में होना चाहिये, तथा
- (स) यह किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले में होना चाहिये।

(अ) माल के स्वामित्व का हस्तान्तरण होना चाहिये—विक्री के लिये यह आवश्यक है कि विक्रेता से ख़रीदा को माल की सम्पत्ति का हस्तान्तरण हो। जहाँ माल के बेचने के लिये प्रसविदा तो कर लिया गया है, माल का आदेश भी दे दिया गया है परन्तु माल की मुपुर्दगी नहीं दी गई है और उनका स्वामित्व हस्तान्तरित नहीं हुआ है तो वहाँ वह विक्री नहीं कहा जायेगी। रहन, गिरवी या बन्धक की दशा में ऋण प्राप्त करने के लिये कुछ समय के लिये माल के समस्त हित का हस्तान्तरण कर दिया जाता है परन्तु, फिर भी रहन, गिरवी या बन्धक विक्री से भिन्न है क्योंकि विक्री में स्वामित्व का हस्तान्तरण

हो जाता है जबकि रहन आदि में केवल थोड़े समय के लिये ही माल के समस्त हित का हस्तान्तरण होता है।

बिक्री की परिभाषा में, 'भाड़े पर क्रय' पद्धति के अन्तर्गत किया गया सौदा भी सम्मिलित है। इस पद्धति के अनुसार क्रेता को माल के स्वामित्व का हस्तान्तरण उस समय तक नहीं होता तक कि क्रेता अन्तिम किस्त न अदा करदे। अन्तिम किस्त का भुगतान कर देने पर ही अनुबन्ध 'बिक्री' हो जाता है, उससे पूर्व नहीं। लेकिन बिक्री की उपरोक्त परिभाषा के अन्तर्गत 'भाड़े पर क्रय' के सौ को भी बिक्री मान लिया गया है तथा इसके सम्बन्ध में 'माल का हस्तान्तरण' शब्द प्रयोग किय गये हैं कि 'माल के स्वामित्व का हस्तान्तरण'।

(ब) हस्तान्तरण व्यापार व व्यवसाय के बीच में होना चाहिये—कोई भी माल के स्वामी का हस्तान्तरण अधिनियम के अनुसार 'बिक्री' नहीं समझा जायेगा जब तक कि वह कर-दाता के द्वारा व व्यवसाय से सम्बन्धित न हो अथवा उनके अन्तर्गत न हो क्योंकि अन्यथा वह बिक्री आकस्मिक बिक्री हो जायेगी जिस पर यह बिक्री-कर नहीं लग सकता।

(स) यह किसी मूल्यवान् प्रतिफल के बदले में होना चाहिये—माल की बिक्री अधिनियम १९३० के अनुसार माल की बिक्री का प्रतिफल केवल मुद्रा ही हो सकता है जब कि केन्द्रीय बिक्री अधिनियम के अनुसार मुद्रा के अतिरिक्त अन्य कोई भी मूल्यवान् प्रतिफल हो सकता है। अतः उपरोक्त परिभाषा के अनुसार वस्तु विनिमय (Barter) के आधार पर किये गये सौदे भी 'बिक्री' कहलायेंगे।

यथा निम्नलिखित बिक्री हैं ?

(i) अपनी ब्रांच को माल भेजना—प्रमुख कार्यालय से अपनी ब्रांच को माल की बिक्री नहीं है बल्कि माल का केवल एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरण है।<sup>१</sup> चाहे ब्रांच उसी राज्य में स्थित हो जिसमें प्रमुख कार्यालय स्थित है अथवा किसी दूसरे राज्य में।<sup>२</sup>

(ii) पक्के आडतिया को माल भेजना—यदि कोई व्यापारी उसी राज्य में अथवा किसी राज्य में स्थित किसी पक्के आडतिया को माल भेजता है तो यह बिक्री नहीं है क्योंकि माल का स्वामी आडतिया को हस्तांतरित नहीं होता बल्कि नियोक्ता के पास ही रहता है। उस माल की बिक्री उस ही हुई मानी जाती है जब कि वह आडतिया उस माल को किसी क्रेता को बेच देता है। इस अवस्था में यह बिक्री उसी राज्य में हुई मानी जाती है जहाँ कि पक्का आडतिया अपना व्यवसाय करता है और राज्य उस पर बिक्री कर लगा सकता है।<sup>३</sup>

(iii) मार्ग में खोये हुए माल का रेलवे से हर्जाना वसूल करना—यदि रेलवे कम्पनी के मार्ग में खो जाने के कारण हर्जाना देता है तो वह बिक्री नहीं है। क्योंकि रेलवे कम्पनी को माल के स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया जाता और इस प्रकार वह क्रेता नहीं बन सकती है।<sup>४</sup>

(iv) अपनी दुकान से अपने उपयोग के लिये सामान लेना—यदि एक व्यापारी अपने व्यवसाय के लिये अपनी दुकान से अथवा गोदाम से कुछ सामान लेता है तो वह बिक्री नहीं कहलायेगी क्योंकि वह स्वयं अपने आप को माल नहीं बेच सकता।<sup>५</sup> परन्तु यदि एक सामीदार अपनी फर्म से कुछ सामान लेता है तो वह बिक्री कहलायेगी क्योंकि एक सामीदार और उसकी फर्म एक ही नहीं है बल्कि वे अलग-अलग दो पक्ष हैं।

1. Babubhai Jivabhai Patel Vs the State
2. Sri Ram Gulab Das Vs. Board of Revenue M. P. (1952)
3. Harji Govindji in Re. 1902 S. 1 G.
4. Newton Chukli Collieries Ltd. Vs. the State (1902)
5. Behubar Company Ltd. Vs. Commissioner of Taxes A. I. R. (1957) Assam.

## —(७) विन्नी-मूल्य (Sale Price)

“किसी माल की विन्नी के लिये प्रतिफल के रूप में किसी एक व्यापारी को दिया जाने वाला है। यह धन विन्नी-मूल कहलाता है जो कि व्यापार की सामान्य प्रथा के अनुसार नगद छूट कम करके परन्तु निम्नलिखित को छोड़कर उन सब व्ययों को जोड़कर जो कि सुपुर्दगी के समय अथवा उससे पूर्व व्यापारी माल के सम्बन्ध में किये हों, ज्ञात किया जाता है —

(अ) किराया भाडा (ब) सुपुर्दगी के व्यय तथा (स) सस्थापन की लागत (Cost of installation) जहां ये व्यय अलहदा चार्ज किये गये हों।”

उपरोक्त परिभाषा के अनुसार विन्नी-मूल्य निम्नलिखित प्रकार से निकाला जाता है :—  
विक्रय की धन राशि जो कि बेची गई वस्तुओं पर प्रति वस्तु की दर से निकाली जाय—नकद छूट + माल के सम्बन्ध में किये गये अन्य व्यय, रेल आदि का किराया, सुपुर्दगी के व्यय तथा सस्थापन की लागत को छोड़कर।

**नकद छूट (Cash Discount)**—वेचे हुए माल का जो बिल या बीजक बनाया जाता है, जिसमें नकद छूट को घटाकर दिखाया जाना चाहिये चाहे बिल का भुगतान तुरत या अवधि के अन्दर दिया गया हो अथवा नहीं। नकद छूट को घटाकर दिखाना उसी अवस्था में मान्य रहता है जबकि ऐसी छूट व्यापार की सामान्य प्रथा के अनुसार हो। यदि किसी बाजार में नकद छूट को काटने का नियम नहीं तो वहां बिल में से नकद छूट काटना विन्नी-कर के लिये मान्य नहीं सम्झा जायेगा।

**(५)** माल के सम्बन्ध में किये गये अन्य व्यय—यदि एक व्यापारी के द्वारा कुछ ऐसे व्यय किये गये हैं जो कि माल को सुपुर्दगी योग्य बनाने के लिये किये जाते हैं जैसे कि पैकिंग व्यय, तुलाई के व्यय आदि तो उन व्ययों को विक्रय की धन राशि में सम्मिलित करके विक्रय-मूल्य ज्ञात किया जाता है।

परिभाषा के अन्तर्गत इन अन्य व्ययों में (१) किराया भाडा (२) सुपुर्दगी की लागत तथा (३) सस्थापन की लागत सम्मिलित नहीं है। परन्तु ये तीन व्यय उसी दशा में सम्मिलित नहीं किये जाते हैं। जबकि इनको विन्नी के अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार बिल में अलहदा चार्ज किया गया हो। यदि (६) बिलों के अनुबन्ध की शर्तों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनको अलहदा चार्ज किया जाय तो उस दशा में ये व्यय भी विन्नी मूल्य का भाग ही समझे जायेंगे।

उपरोक्त अर्थवाद वाले ३ व्ययों में से एक व्यय सुपुर्दगी की लागत भी है। यहां सुपुर्दगी की लागत का अर्थ उस व्यय में है जिसे माल को सुपुर्दगी के योग्य बनाने के पश्चात् किया गया हो जैसे कि भाडा भाडा, कुली व्यय आदि, क्योंकि सुपुर्दगी के योग्य बनाने में अथवा उससे पूर्व जो व्यय किये जाते हैं, वे तो विक्रय मूल्य में सम्मिलित किये ही जाते हैं।

बीजक बनाने में कुछ ऐसे भी व्यय सम्मिलित कर दिये जाते हैं जिनका सम्बन्ध माल को सुपुर्दगी के योग्य बनाने से नहीं होता। जैसे कि गोशाला का खन्दा व अन्य धर्मादा आदि। इस प्रकार ये व्यय विन्नी-मूल्य का भाग नहीं बन पाते। इसी कारण विन्नी-कर का व्यय भी विन्नी-मूल्य का भाग नहीं होता।

## (८) विन्नी-कर कानून (Sales Tax Law)

“विन्नी कर कानून का” अर्थ उस कानून से है जो कि एक समय में किसी राज्य अथवा राज्य के एक भाग में लागू होता हो तथा इस सम्बन्ध में स्पष्टतया वर्णित विशिष्ट माल पर अथवा सामान्य तौर पर माल के क्रय व विक्रय पर कर के लगाने का प्रावधान करता हो।



‘सामान्य बिक्री-कर कानून’ का अर्थ ऐसे कानून से है जो कि एक समय में किसी राज्य अथवा राज्य के एक भाग में लागू होता है तथा जो सामान्य तौर से माल के क्रय व विक्रय पर कर लगाने का प्रावधान करता हो।”

‘बिक्री कर कानून’ व ‘सामान्य बिक्री-कर कानून’ का आशय विभिन्न राज्यों में प्रचलित बिक्री कर कानून से ही है।

## (६) विक्रय राशि (Turn Over) ✓ *only*

ऐसे व्यापारी के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कर देने का दायी है, विक्रय राशि का अर्थ उन समस्त विक्रय मूल्यों के योग से है जो उसने एक निर्धारित समय में तथा निर्धारित ७ के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत विभिन्न माल की बिक्री पर प्राप्त कर लि हो अथवा प्राप्य हो।

उपरोक्त परिभाषा से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं, —

(१) विक्रय राशि का अर्थ एक व्यापारी के उन विक्रय मूल्यों के योग से है जो कि उसने निर्धारित समय में या तो प्राप्त कर लिये हो अथवा जिनका प्राप्त करना अभी शेष रह गया हो ६ प्रकार उधार बिक्री भी विक्रय-राशि में सम्मिलित होती है।

(२) विक्रय राशि का अर्थ उसी व्यापारी के सम्बन्ध में ही प्रयुक्त है जो कि इस अधिनियम अन्तर्गत कर देने का दायी हो।

(३) विक्रय राशि का अर्थ ऐसे माल की बिक्री से ही सम्बन्धित है जो कि व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत की गई हो।

(४) ‘निर्धारित समय’ का अर्थ उस काल से है जिसके लिये एक व्यापारी अपनी ‘बिक्री व विवरण’ कर निर्धारण के हेतु प्रस्तुत करता है।

## (१०) वर्ष (Year)

एक व्यापारी के सम्बन्ध में, इसका अर्थ उस वर्ष से है जो कि उपयुक्त राज्य के सामान्य बिक्री कर कानून के अन्तर्गत प्रयोज्य हो, तथा जहाँ कहीं ऐसा वर्ष प्रयोज्य नहीं है, वहाँ वर्ष का अर्थ वही वर्ष होगा।

इस परिभाषा के अनुसार केन्द्रीय बिक्री-कर के लिये वर्ष वही होगा जो कि राज्य के बिक्री के लिये लागू होगा। परन्तु जहाँ किसी राज्य के बिक्री कर अधिनियम में कर निर्धारण वर्ष नहीं किया हुआ है, वहाँ इसका अर्थ वित्तीय वर्ष से होता है। वित्तीय वर्ष वह है जो कि १ अप्रैल प्रारम्भ होकर ३१ मार्च को समाप्त होता है।

यद्यपि इस परिभाषा में ‘गत वर्ष’ (Previous year) अथवा ‘कर-निर्धारण वर्ष’ (Assessment year) का उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु फिर भी राज्य के अधिनियमों के अनुसार यह स्पष्ट ही है कि ‘गत वर्ष’ की बिक्री राशि पर कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है। एक वर्ष के लिये ‘गत वर्ष’ उसका एकाउन्टिंग वर्ष (Accounting year) होता है जो कि ३१ दिसम्बर, दीवाली व दशहरा या ३१ मार्च को अथवा ३१ मार्च से पूर्व किसी अन्य तिथि को समाप्त होता है ‘कर निर्धारण वर्ष’ सर्वदा वित्तीय वर्ष ही होता है जो कि ३१ मार्च को समाप्त होता है।

उपरोक्त परिभाषा में वर्ष का अर्थ ‘कर निर्धारण वर्ष’ से ही है जिसमें गत वर्ष की बिक्री कर लगाया जाता है।

परन्तु कुछ राज्यों में गत वर्ष व कर निर्धारण वर्ष एक ही होते हैं।

## विक्री व खरीद के स्थान-निर्धारण के सिद्धान्त

(Principles for Determining the Situs of Sale or Purchase)

प्रथम अध्याय में हम देख चुके हैं कि जब भारतीय संविधान के अन्तर्नियम २८६ के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालय एक मत नहीं रहे तो सन् १९५६ में उस अन्तर्नियम में संशोधन किया गया। इस संशोधन के फलस्वरूप धारा २ के अनुसार संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह कानून के द्वारा शब्द १ में दिए गये विक्री व खरीद का निर्णय करने के लिए सिद्धान्त निर्धारित करे।

इन सिद्धान्तों के निर्धारण के लिए संसद ने सन् १९५६ में केन्द्रीय विक्री-कर अधिनियम पास किया। यह सिद्धान्त इस अधिनियम के अध्याय २ में तथा धारा ३, ४ व ५ के अन्तर्गत दिए गए हैं।

जो सिद्धान्त अधिनियम में दिये गये हैं, वे निम्नलिखित ३ बातों का निर्णय करने के लिये हैं —

- (१) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत माल की विक्री व खरीद कब समझी जायगी (धारा ३)।
- (२) माल की विक्री व खरीद राज्य के बाहर हुई कब मानी जायगी (धारा ४)।
- (३) माल की विक्री व खरीद आयात व निर्यात के अन्तर्गत हुई कब मानी जायेगी (धारा ५)।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दो बातें समझनी आवश्यक हैं —

- (अ) अधिनियम की धारा ६ के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत माल की विक्री व खरीद पर केन्द्रीय विक्री कर लगाया जाता है। परन्तु इस केन्द्रीय विक्री-कर के लगाने व वसूल करने का काम धारा ६ के अनुसार उपयुक्त राज्यों के विक्री-कर प्राधिकारी ही करते हैं।
- (ब) यदि माल का विक्री व खरीद (१) राज्य के बाहर, अथवा (२) आयात व निर्यात के अन्तर्गत होती है तो उस पर किसी प्रकार का विक्री-कर नहीं लगता है, अर्थात् न तो केन्द्रीय विक्री-कर ही लगता है और न राज्य विक्री-कर।

### १) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत माल की विक्री व खरीद

धारा ३ के अनुसार माल की विक्री व खरीद अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत मानी जायेगी, यदि विक्री या खरीद—

- (अ) एक राज्य से दूसरे राज्य को माल का गमनागमन उत्पन्न करती हो, अथवा

( ब ) एक राज्य से दूसरे राज्य को माल के गमनागमन के बीच माल के अधिकार सम्बन्धी विपत्रों ( Documents of Title to the Goods ) के हस्तांतरण करने से हुई हो ।

उपरोक्त दोनों शर्तों में माल के गमनागमन का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली शर्त के अनुसार क्रय-विक्रय हो चुकने के पश्चात् गमनागमन उत्पन्न होता है जबकि दूसरी शर्त के अनुसार माल का गमनागमन पहिले प्रारम्भ हो जाता है तथा उस गमनागमन के बीच में ही क्रय-विक्रय होता है ।

इन दोनों शर्तों के अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यदि किसी माल के एक राज्य से दूसरे राज्य को पहुँच जाने के पश्चात् ही कोई बिक्री या खरीद का सौदा होता है तो वह सौदा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत नहीं माना जायेगा अर्थात् उस पर केन्द्रीय बिक्री कर नहीं लगेगा वरन् उस सौदे पर राज्य का ही बिक्री कर लगेगा ।

**माल का गमनागमन उत्पन्न होना**—पहली शर्त के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत माल की बिक्री व खरीद उसी अवस्था में मानी जाती है जबकि उस बिक्री व खरीद के फलस्वरूप माल का गमनागमन एक राज्य से दूसरे राज्य को उत्पन्न होता हो ।

संयुक्त राष्ट्र अमरीका के संविधान के विषय में लिखते हुए श्री विलोबी ( Willoughby ) ने कहा :—

“A mere making of contracts between persons in different States does not constitute inter-State commerce” अर्थात्

विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों के बीच अनुबन्ध कर देने से ही अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य नहीं बन जाता ।

अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य के लिए अनुबन्ध के अतिरिक्त माल का गमनागमन उत्पन्न होना आवश्यक है । The Bengal Immunity Co. 1955 के मामले में न्यायाधीश श्री वेकन्टा-रामा अय्यर ने ठीक ही कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत बिक्री तभी कही जा सकती है जबकि २ शर्तें साथ-साथ पूरी होती हों—( १ ) माल की बिक्री तथा ( २ ) विक्रय के अनुबन्ध के आधीन एक राज्य से दूसरे राज्य को उस माल का यातायात ।

एक राज्य से दूसरे राज्य को माल के गमनागमन के सम्बन्ध में धारा ३ के स्पष्टीकरण नम्बर दो में यह स्पष्ट किया गया है “जहाँ माल के गमनागमन का प्रारम्भ व उसकी समाप्ति एक ही राज्य में होती है तो वह एक राज्य से दूसरे राज्य को माल का गमनागमन नहीं समझा जायेगा चाहे वह माल ऐसे गमनागमन के बीच किसी दूसरे राज्य की सीमा में होकर गुजरा हो ।” उदाहरण के लिए यदि कोई माल राजस्थान से चलकर पंजाब होता हुआ पुनः राजस्थान में अपनी यात्रा समाप्त करता है तो ऐसा गमनागमन दो राज्यों के बीच हुआ नहीं माना जायेगा ।

माल के गमनागमन उत्पन्न होने का अर्थ यह है कि जब बिक्री की शर्तों के अनुसार कोई एक विक्रेता उस माल को निक्षेप गृहीता अथवा सार्वजनिक वाहक ( Carrier ) को सौंप दे तो यह समझा जायेगा कि गमनागमन उत्पन्न हो गया चाहे वह माल अभी उस राज्य से न चला हो । माल की बिक्री अधिनियम १९३० के अनुसार भी यदि विक्रेता बिक्री की शर्तों के अनुसार माल को सार्वजनिक वाहक को सौंप देता है तो यही समझा जाता है कि वह जेता को सौंप दिया गया क्योंकि वह वाहक जेता का एजेंट समझा जाता है ।

( ब ) मार्ग में माल के अधिकार सम्बन्धी विपत्रों के हस्तांतरण द्वारा बिक्री व खरीद—यदि माल के गमनागमन के पश्चात् जबकि माल मार्ग में ही हो, माल के अधिकार सम्बन्धी विपत्रों के

हस्तांतरण द्वारा बिक्री व खरीद होती है तो वह सौदा भी अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत समझा जाता है ।

माल के अधिकार सम्बन्धी विपत्रो ( Documents of title to the goods ) के अन्तर्गत सामान्यतया निम्नलिखित विपत्र सम्मिलित किये जाते हैं —

बीजक, रेलवे रसीद, सुपुर्दगी चालान जहाजी-बिल्टी तथा अन्य वे पत्र जो कि ठेका को माल की सुपुर्दगी लेने के हेतु आवश्यक होते हों ।

इस नियम के सम्बन्ध में २ बातें पूरी होनी आवश्यक हैं —

( १ ) माल मार्ग में ही हो, तथा

( २ ) अधिकार सम्बन्धी विपत्रो के हस्तांतरण द्वारा बिक्री व खरीद हो ।

उदाहरण १—लीवर ब्रदर्स ने बम्बई से १ अप्रैल १९६२ को १०० सनलाइट साबुन की एक पट्टी जयपुर को भेजी परन्तु जयपुर पहुँचने के पूर्व जयपुर के सौदागर ने ५ अप्रैल १९६२ को यह पट्टी देहली वाले सौदागर को अधिकार सम्बन्धी विपत्रो का हस्तांतरण करके बेच दी । इस दशा में यह बिक्री अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत हुई मानी जायेगी ।

उदाहरण २—कलकत्ते से मोहन ब्रदर्स ने १ जुलाई १९६१ को २०० फाउन्टेनपैन देहली में 'ब' को भेजे जो कि देहली १० जुलाई, १९६१ को आकर पहुँचे । उसी दिन 'ब' की ओर से 'स' ने देहली में माल छुड़ा लिया । ११ जुलाई को 'ब' ने अधिकार सम्बन्धी विपत्रो का हस्तांतरण करके उदयपुर माल बेच दिया । यह सौदा अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत हुमा नहीं माना जायेगा ।

धारा ३ के स्पष्टीकरण सस्या १ में यह स्पष्ट किया गया है —

“जहाँ माल किसी वाहक को अथवा अन्य निक्षेपगृहीता ( Bailor ) को प्रेषण के लिये सुपुर्द कर दिया जाता है तो ( ब ) वाक्य के प्रयोजनार्थ माल का गमनागमन इस सुपुर्दगी के समय प्रारम्भ हुमा मान लिया जायेगा तथा वह गमनागमन ऐसे समय अन्त हुमा माना जायेगा जबकि ऐसे वाहक व निक्षेपगृहीता से सुपुर्दगी ले ली गयी हो ।”

यहाँ ( ब ) वाक्य का अर्थ दूसरी शर्त से है ।

इस दूसरी शर्त के अनुसार अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत सीधे ऐसे दो व्यापारियों के बीच भी हो सकते हैं जो कि एक ही राज्य के निवासी हों ।

उदाहरण ३—बोई माल बम्बई से जयपुर भेजा गया । उस माल के जयपुर पहुँचने से पूर्व जयपुर के सौदागर 'अ' ने वह माल विपत्रो का हस्तांतरण करके जयपुर के सौदागर 'ब' को बेच दिया । यह सौदा अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत हो हुमा हो समझा जायेगा और इस पर केन्द्रीय बिक्री कर लगेगा ।

## (२) राज्य के बाहर माल की बिक्री व खरीद

। इस सम्बन्ध में धारा ४ निम्नलिखित है —

(१) धारा ३ में दिये गये प्रावधानों के अधीन जब माल की बिक्री व खरीद उपधारा २ के अनुसार एक राज्य के अन्दर हुई निर्णय की जाती है तो ऐसी बिक्री व खरीद अन्य सब राज्यों से बाहर हुई मानी जाती है

(२) माल की एक बिक्री व खरीद एक राज्य के अन्दर हुई मानी जायेगी यदि माल राज्य के अन्दर है :—

(अ) विशिष्ट (Specific) अथवा निश्चित (Ascertained) माल के सम्बन्ध में, उस समय जबकि बिक्री वा अनुबन्ध किया गया, तथा

(ब) अनिश्चित (Unascertained) अथवा भावी (future) माल के सम्बन्ध में, उस समय जबकि विक्रेता अथवा क्रेता के द्वारा उस माल को बिक्री के अनुबन्ध के अनुरूप बनाया गया हो चाहे दूसरे पक्ष की सहमति ऐसे अनुरूप बनाने से पूर्व अथवा बाद में ली गयी हो ।

**स्पष्टीकरण—**जहाँ माल एक स्थान से अधिक स्थानों पर स्थित है और उन सब माल की बिक्री व खरीद के लिये जहाँ एक ही अनुबन्ध हो, तो इस उपधारा के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्येक ऐसे स्थानों पर माल के सम्बन्ध में अलग-अलग अनुबन्ध किये गये हों ।

उपरोक्त धारा ४ में 'समय' तथा 'स्थान' दो ऐसे महत्वपूर्ण तत्त्व हैं जिनका समझना आवश्यक है ।

उपधारा २ यह बतलाती है कि माल की बिक्री व खरीद एक राज्य के अन्दर हुई कब समझी जाती है और उपधारा १ के अनुसार, यदि कोई बिक्री या खरीद किसी राज्य के अन्दर होती है तो वह अन्य सब राज्यों से बाहर हुई मानी जाती है । इस प्रकार उपधारा १ के अन्तर्गत वह बिक्री या खरीद सम्मिलित की गयी बतलाई हुई है जो कि उपधारा २ में नहीं आती । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जो बिक्री या खरीद किसी राज्य के अन्दर नहीं हो और न वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत की गयी हो तो वह बिक्री राज्य के बाहर हुई मानी जायेगी ।

उपधारा १ में 'धारा ३ में दिये गये प्रावधानों के आधीन' शब्द जुड़े हुए हैं । इन शब्दों का अर्थ यह है कि चाहे बिक्री या खरीद राज्य के अन्दर ही हुई हो अथवा राज्य के बाहर हुई हो परन्तु फिर भी उस पर केन्द्रीय बिक्री-कर लगेगा यदि धारा ३ के अनुसार उस बिक्री या खरीद के फलस्वरूप एक राज्य से दूसरे राज्य को माल का गमनागमन उत्पन्न हुआ हो, अथवा गमनागमन के पश्चात् मार्ग में बिपन्नो के हस्तान्तरण से क्रय व विक्रय हुआ हो ।

उदाहरण सख्या ३ में माल की बिक्री जयपुर में ही हुई है, 'अ' तथा 'ब' दोनों ही जयपुर के निवासी हैं परन्तु यह सौदा एक ही राज्य के अन्दर हुआ नहीं माना गया है वरन् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत हुआ माना गया है । इस प्रकार इस उदाहरण सख्या ३ द्वारा 'धारा ३ में दिये गये प्रावधानों के आधीन' शब्द स्पष्ट हो जाते हैं ।

**राज्य के बाहर बिक्री व खरीद के उदाहरण**

**उदाहरण १—**कानपुर निवासी 'अ' जोधपुर में अपने पक्के आदतिया 'ब' को माल भेजता है । 'ब' उस माल की बिक्री 'स' को करता है । यहाँ 'अ' के लिये यह बिक्री राज्य के बाहर समझी जायेगी । 'अ' के लिये यह बिक्री अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत भी नहीं समझी जायेगी क्योंकि उसने अपने पक्के आदतिये को माल भेजा था, बेचा नहीं था । इस प्रकार 'अ' पर न तो उत्तर प्रदेश का राज्य कर ही लगेगा और न केन्द्रीय-कर ही । जो बिक्री-कर उस माल पर लगेगा, वह राजस्थान में पक्के आदतिया पर उस समय लगेगा जबकि कि उसने उस माल को 'स' को बेच दिया है ।

**उदाहरण २—**जब कोई प्रमुख कार्यालय अपना माल किसी दूसरे राज्य में स्थित अपनी शाखा को भेजता है, तो वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत बिक्री नहीं मानी जाती है और जब वह शाखा उस माल को बेचती है तो वह बिक्री प्रमुख कार्यालय के लिये राज्य से बाहर हुई समझी जाती है ।

## एक राज्य के अन्दर बिक्री व खरीद

हस  
जा  
सा  
मा

उपधारा २ के (अ) वाक्य के अनुसार, विशिष्ट अथवा निश्चित माल के सम्बन्ध में बिक्री के अनुबन्ध के समय यदि माल राज्य के अन्दर हो तो वह बिक्री या खरीद उसी राज्य के अन्दर हुई मानी जायेगी।

‘विशिष्ट माल’ का अर्थ उस माल से है जो कि बिक्री के अनुबन्ध के समय वास्तविक रूप से पहिचाना जा चुका हो और दोनों पक्षों की सहमति प्राप्त कर चुका हो। विशिष्ट माल की यह परिभाषा ‘माल की बिक्री अधिनियम १९३०’ की धारा २ (१४) में दी हुई है।

निश्चित माल का अर्थ विशिष्ट माल से मिलता जुलता ही है। ‘माल की बिक्री अधिनियम’ में इसकी कोई परिभाषा भी नहीं दी गई है लेकिन *Thames Sack and Bag. Co Vs Knowles* (1919) के मामले में यह कहा गया था कि निश्चित माल का अर्थ उस माल से है जो कि बिक्री के अनुबन्ध के समय के पश्चात् ठहराव के अनुसार पहिचाना गया हो। उदाहरण के लिये, अगर कुछ माल एक ढरी में से बेचा जाता है तो वह माल निश्चित किया हुआ उस समय तक नहीं माना जायेगा जब तक कि वह माल उस ढरी में से अलग न कर लिया हो चाहे सारी ढरी एक ही प्रकार के बिस्म व मूल्य वाले माल की बनी न हो—*Wallace Vs. Breeds* (1811) तथा *Buswell Vs. Kilborn* (1862)।

परन्तु उपधारा २ के (अ) वाक्य में ‘बिक्री के अनुबन्ध के समय’ शब्द ‘विशिष्ट’ और ‘निश्चित,’ दोनों ही प्रकार के माल को लागू होते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दोनों का अर्थ लगभग समान ही है तथा निश्चित माल का अर्थ केवल माल का अलग करके पहिचानने से है।

उपधारा २ के (ब) वाक्य के अनुसार, अनिश्चित अथवा भावी माल के सम्बन्ध में, यदि माल राज्य के अन्दर उस समय हो जबकि विक्रेता व क्रेता ने उस माल की बिक्री के अनुबन्ध के अनुरूप बनाया हो तो वह बिक्री या खरीद उसी राज्य के अन्दर हुई मानी जायेगी। परन्तु जहाँ तक अनुरूप बनाने के लिये दूसरे पक्ष की सहमति का प्रश्न है, वह तो अनुरूप बनाने से पूर्व अथवा उसके पश्चात् कभी भी ला जा सकती है।

सु  
प्र  
ध

भावी माल (Future Goods) का अर्थ ऐसे माल से है जो कि अनुबन्ध करते समय तैयार अवस्था में नहीं हैं बल्कि जो अनुबन्ध होने के बाद ही प्राप्त किया जायेगा अथवा निर्मित किया जायेगा।

अनिश्चित (Unascertained) माल का अर्थ, जैसा कि स्पष्ट है, उस माल से है जो कि निश्चित नहीं हो। निश्चित माल के विषय में ऊपर बतलाया जा चुका है।

क

‘माल की बिक्री अधिनियम’ की धारा २३ (२) के अनुसार, जहाँ अनुबन्ध को पूरा करने में, एक विक्रेता किसी क्रेता को माल मुपुर्द कर देता है अथवा वह किसी वाहक व निक्षेप गृहीता को क्रेता तक पहुँचाने के लिये माल मुपुर्द कर देता है तथा वह विक्रेता अपने पास उम माल को बेचने का कोई अधिकार सुरक्षित नहीं रखता है तो यह समझा जाता है कि उसने माल की बिक्री के अनुबन्ध के अनुरूप शर्त रहित बंट से बना दिया है।

१)

परन्तु जहाँ विक्रेता माल को बेचने का अधिकार किसी शर्त के अधीन अपने पास सुरक्षित रखता है तो उस माल का स्वामित्व क्रेता को उम समय तक नहीं मिल पाता जब तक कि वह शर्त पूरी नहीं हो जाती है इस बात को समझने के लिये निम्नलिखित निर्णय महत्वपूर्ण है —

The State of Madras (Now Andhra Pradesh) Vs V. P. Venkata Rama-  
devarat & Sons 1958 (9) के मामले में यह निर्णय हुआ कि :—

जहाँ माल की सुपुर्दगी के हेतु रेलवे रसीद विक्रेता के नाम में बनवाई गयी हो तथा एक बैंक पर लिखे गये विनियम-पत्र (B/E) की स्वीकृति की शर्त पर वह बिल्टो क्रेता को भेजी गयी हो तो वहाँ यह माना जायेगा कि विक्रेता ने माल को पुनः बेचने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रख लिया है। ऐसे माल का स्वामित्व क्रेता को तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वह विनियम-पत्र पर स्वीकृति न दे दे और बैंक से बिल्टी न छुडा ले। अतः शर्त पूरी करने की दशा में बिक्री क्रेता के स्थान पर ही हुई मानी जायेगी और यदि क्रेता किसी दूसरे राज्य का निवासी है तो यह बिक्री राज्य के बाहर हुई मानी जायेगी।

उपरोक्त उदाहरण में बिक्री राज्य के बाहर हुई मानी गयी है क्योंकि माल उस समय विक्रेता के राज्य में नहीं था।

### (३) आयात अथवा निर्यात के अन्तर्गत बिक्री या खरीद

धारा ५ की उपधारा १ के अनुसार माल की बिक्री या खरीद, भारत की सीमा के बाहर निर्यात के अन्तर्गत केवल तभी मानी जायेगी जब कि वह बिक्री या खरीद माल का ऐसा निर्यात उत्पन्न करती हो अथवा वह माल के अधिकार सम्बन्धी विषयों के उस समय हस्तान्तरित करने से हुई हो जबकि माल भारत की आगम शुल्क सीमाओं (Customs frontiers) को पार कर गया हो।

धारा ५ की उपधारा २ के अनुसार माल की बिक्री व खरीद, भारत की सीमा के अन्दर आयात के अन्तर्गत केवल तभी मानी जायेगी जबकि वह बिक्री या खरीद माल का ऐसा आयात उत्पन्न करती हो अथवा वह माल के अधिकार सम्बन्धी विषयों के उस समय हस्तान्तरित करने से हुई हो जब कि माल भारत की आगम शुल्क सीमाओं को पार न कर पाया हो।

भारतीय सविधान के अन्तर्नियम २८६ (१) के अनुसार निर्यात अथवा आयात के अन्तर्गत हुई बिक्री या खरीद पर कोई राज्य बिक्री कर नहीं लगा सकता है। इसी कारण से यह जानना आवश्यक हो जाता है कि बिक्री व खरीद निर्यात अथवा आयात के अन्तर्गत कब समझी जायेगी।

धारा ५ के प्रावधान धारा ३ के प्रावधानों के समान ही हैं। इन दोनों में केवल यह अन्तर है कि धारा ३ में माल का गमनागमन विभिन्न राज्यों के बीच होता है जबकि धारा ५ के अन्तर्गत माल का गमनागमन निर्यात व आयात के अन्तर्गत आगम शुल्क सीमाओं के पार होता है।

माल की बिक्री या खरीद निर्यात के अन्तर्गत (In the course of export) समझी जाती है यदि निम्नलिखित २ शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी होती हो :—

- (१) यदि माल की बिक्री या खरीद के फलस्वरूप माल का निर्यात उत्पन्न होता हो,
- (२) इसके पश्चात् कि माल भारत की आगम शुल्क सीमाओं को पार कर चुके, उस माल की बिक्री व खरीद अधिकार-विषयों के हस्तांतरण से हुई हो। इसी प्रकार माल की बिक्री या खरीद आयात के अन्तर्गत समझी जाती है यदि निम्नलिखित २ शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी होती हो :—
- (१) यदि माल की बिक्री या खरीद के फलस्वरूप माल का आयात उत्पन्न होता हो।
- (२) इसके पूर्व कि माल भारत की आगम शुल्क सीमाओं को पार कर भारत में आ जाये, उस माल की बिक्री व खरीद अधिकार-विषयों के हस्तांतरण से हुई हो।

निर्यात एवं आयात की उपरोक्त दशाओं में यदि माल की बिक्री या खरीद अधिकार-विषयो के हस्तांतरण से होती है तो दोनों दशाओं में यह आवश्यक है कि अधिकार-विषयो का हस्तांतरण उस समय ही हो जब कि माल भारत की सीमा से बाहर ही हो। इसलिए यदि विषयो का हस्तांतरण भारतीय बन्दरगाह पर होता है तो वह बिक्री या खरीद निर्यात व आयात के अन्तर्गत नहीं समझी जायेगी।

स्टेट ऑफ ट्रावनकोर कोचीन Vs दी बाम्बे कम्पनी १९५२ के मामले में यह तय किया गया "यदि माल की यात्रा आरम्भ होने से पूर्व माल का स्वामित्व विदेशी क्रेता को मिल जाता है और इस प्रकार वह बिक्री राज्य के अन्दर ही पूर्ण हो जाती है तो वह बिक्री निर्यात के अन्तर्गत हुई ही मानी जायेगी। इसका कारण यह है कि माल की बिक्री के फलस्वरूप माल का निर्यात उत्पन्न हो गया था। माल का निर्यात उस दशा में उत्पन्न हो जाता है जबकि माल निर्यात के लिए विदेशी क्रेता अथवा उसके एजेंट यानी बाहक व निक्षेप गृहीता को बिक्री की शर्तों के अनुसार सीप दिया गया हो।



## अन्तर्राज्यीय बिक्री-कर ( Inter-State Sales Tax )

### अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर देने का दायित्व ( Liability to Tax on Inter-State Sales )

धारा ६ में अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर देने का दायित्व दिया हुआ है। अतः यह धारा बहुत महत्वपूर्ण है।

#### धारा ६ (१)

इस अधिनियम में दिये गये अन्य प्रावधानों के आधीन प्रत्येक व्यापारी ऐसी तिथि से जिसे केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट (Official Gazette) में विज्ञप्ति द्वारा नियुक्त करे परन्तु वह तिथि जो ऐसी विज्ञप्ति की तिथि से कम से कम ३० दिन बाद की हो, उन सभी बिक्रियों पर इस अधिनियम के आधीन कर देने का दायी होगा, जो कि ऐसी विज्ञप्ति तिथि से किसी वर्ष में अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत की गई हो।

इस धारा के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा जो तिथि सरकारी गजट में घोषित की जाती है उस तिथि से प्रत्येक व्यापारी प्रत्येक वर्ष में अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत की गयी। पर कर देने के लिये उत्तरदायी होगा। तिथि के बारे में इस धारा में यह कहा गया है कि ऐसी तिथि घोषणा की तिथि से कम से कम ३० दिन बाद की होनी चाहिए।

इस नियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने २६ मार्च १९५७ को सरकारी गजट में घोषणा की कि अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर देने का दायित्व १ जुलाई १९५७ से आरम्भ होगा। अतः यहाँ पर जो तिथि निश्चित की गई, वह घोषणा की तिथि से ३ माह से अधिक बाद की तिथि रही थी जो कि नियमानुसूल ही है क्योंकि धारा ६ में 'कम से कम ३० दिन बाद' शब्द प्रयोग किये गए हैं। इस धारा ६, १ जुलाई १९५७ से ही लागू हुई है।

धारा ६(१) की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :—

( १ ) प्रत्येक व्यापारी १ जुलाई १९५७ से केन्द्रीय बिक्री कर देने का दायी है।

( २ ) यह बिक्री कर उस बिक्री पर लगाया जाएगा जो कि व्यापारी ने अन्तर्राज्यीय व वाणिज्य के अन्तर्गत किसी एक वर्ष में की हो।

## धारा ६ (२)

धारा ६ (२) कुछ इस प्रकार के माल की उत्तरवर्ती बिक्री (Subsequent sale) को कर मुक्त करती है जो कि धारा ८ की उपधारा ३ में वर्णित किया हुआ है।

यदि उस प्रकार के माल की अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत बिक्री होती है और वह बिक्री —

- { (अ) एक राज्य से दूसरे राज्य को माल का गमनागमन उत्पन्न करती है, अथवा
- { (ब) एक राज्य से दूसरे राज्य के गमनागमन के बीच माल के अधिकार सम्बन्धी विपन्नो के हस्तान्तरण से होती है,

तो उस माल की किसी उत्तरवर्ती बिक्री पर इस अधिनियम के अन्तर्गत कर नहीं लगेगा बशर्ते कि वह उत्तरवर्ती बिक्री माल के अधिकार सम्बन्धी विपन्नो के हस्तान्तरण से माल के गमनागमन के बीच किसी पंजीकृत व्यापारी (Registered dealer) को की गयी हो।

इस उपधारा में आगे कहा गया है कि —

ऐसी उत्तरवर्ती बिक्री कर-मुक्त नहीं होगी जब तक कि विक्रय करने वाला व्यापारी नियत ढंग से नियत अधिकारी को एक सर्टीफिकेट प्रस्तुत न करे। वह सर्टीफिकेट उस पंजीकृत व्यापारी द्वारा भरा जाना चाहिए तथा हस्ताक्षरित होना चाहिए जिससे माल खरीदा गया या तथा उस सर्टीफिकेट में सभी नियत विवरण भी दिया जाना चाहिए।

धारा ६ (२) की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं —

- (१) इस उपधारा के प्रावधानों पर उपधारा (१) का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात् चाहे उपधारा (१) में कुछ भी दिया हो तो भी उपधारा (२) लागू होती है।
- (२) यह उपधारा जिस प्रकार के माल की उत्तरवर्ती बिक्री को कर मुक्त करती है वह माल धारा ८ की उपधारा (३) में वर्णित है।
- (३) प्रथम बिक्री के पश्चात् जो बिक्रियाँ होती हैं वे उत्तरवर्ती बिक्रियाँ कहलाती हैं।
- (४) प्रथम बिक्री अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत होनी चाहिये तथा उत्तरवर्ती बिक्रियाँ भी अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत होनी चाहिये।
- (५) कर मुक्त होने के लिये आवश्यक है कि उत्तरवर्ती बिक्री माल के अधिकार सम्बन्धी विपन्नो के हस्तान्तरण से, माल के गमनागमन के बीच अर्थात् जब माल मार्ग में ही हो तथा किसी पंजीकृत व्यापारी को ही की गई हो।
- (६) कोई उत्तरवर्ती बिक्री कर-मुक्त नहीं होगी, जब तक कि विक्रय करने वाला व्यापारी नियत ढंग से नियत अधिकारी (Prescribed Authority) को एक सर्टीफिकेट प्रस्तुत न करे।

यह सर्टीफिकेट उस पंजीकृत व्यापारी द्वारा भरा जाना चाहिये व हस्ताक्षरित होना चाहिये

\*) इससे माल खरीदा गया या।

**उदाहरण १—**‘अ’ अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत ‘ब’ को उस माल की बिक्री करता है जिस माल का वर्णन धारा ८ की उपधारा (३) में दिया हुआ है। ‘ब’ माल के निदिष्ट स्थान पर पहुँचने से पूर्व, उसके अधिकार विपन्नो का हस्तान्तरण करके ‘स’ को माल बेच देता है। यहाँ जो बिक्री ‘स’ को की गयी है वह उत्तरवर्ती बिक्री कहलायेगी। माल की बिक्री को कर-मुक्त करने के लिये यह

आवश्यक होगा कि 'ब' एक सार्टिफिकेट 'अ' से भरवा कर तथा हस्ताक्षरित करवा कर नियत अधिकारी को नियत ढग से प्रस्तुत करे। इस उदाहरण में 'अ' 'ब' 'स' को पंजीयत व्यापारी माना है।

इस सार्टिफिकेट के दो फार्म हैं—ई, प्रथम (E I) तथा ई, द्वितीय (E II) जो कि अपनी आवश्यकतानुसार प्रयोग किये जाते हैं।

ई प्रथम (E I) फार्म—यह फार्म दो प्रकार के व्यापारियों द्वारा निर्गमित किया जाता है—

(१) विक्रय करने वाले उस व्यापारी के द्वारा जिसने धारा ३ (अ) के अन्तर्गत बिक्री के हेतु माल का प्रथम बार गमनागमन आरम्भ किया हो, अथवा (२) इस व्यापारी के द्वारा जिसे कि धारा ३ (ब) के अन्तर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य को माल के गमनागमन के बीच प्रथम बार अन्तर्राज्यीय बिक्री की हो।

ई द्वितीय (E II) फार्म—यह फार्म भी दो प्रकार के व्यापारियों के द्वारा निर्गमित किया जाता है—(१) धारा ६ (२) (अ) में वर्णित बिक्री की शृङ्खला में प्रथम अथवा उत्तरवर्ती हस्तांतरण करने वाला अथवा (२) धारा ६ (२) (ब) में वर्णित बिक्री की शृङ्खला में द्वितीय अथवा उत्तरवर्ती हस्तांतरण करने वाला।

उपरोक्त उदाहरण में 'अ' ई प्रथम (E I) फार्म भरेगा तथा 'ब' ई द्वितीय (E II) फार्म भरेगा। यदि 'स' उस माल को 'द' को बेचता है तो 'स' भी द्वितीय (E II) फार्म ही भरेगा।

उत्तरवर्ती बिक्री के बारे में यह बात समझ लेनी आवश्यक है कि यह बिक्री धारा ६ (२) (अ) तथा ६ (२) (ब) दोनों के अन्तर्गत की जा सकती है परन्तु दोनों दशाओं में जब भी उत्तरवर्ती बिक्री की जायगी, वह बिक्री माल के मार्ग में, अधिकार पत्रों के हस्तांतरण द्वारा तथा पंजीयत व्यापारी को ही की जानी चाहिये ताकि वह कर-मुक्त हो सके।

✓ धारा ८—केन्द्रीय बिक्री-कर की दरें ✓ *Indu*

यह धारा अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत बिक्री पर कर की दरों का वर्णन करती है।

उपधारा (१)

धारा ८ (१) के अनुसार यदि एक व्यापारी अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत—

(अ) सरकार को किसी भी प्रकार का माल बेचता है, अथवा

(ब) सरकार के अतिरिक्त किसी पंजीयत व्यापारी को केवल वह माल बेचता है जो कि इस धारा की उपधारा (३) में वर्णित है, तो उस व्यापारी को इस अधिनियम के अधीन कर देना पड़ेगा जो कि उसकी विक्रय राशि (Turnover) का २% होगा।

इस उपधारा के अनुसार सरकार को किसी भी प्रकार का माल बेचने पर केन्द्रीय कर विक्रय राशि का केवल २% लगेगा। यदि कोई माल जो कि उपधारा (३) में वर्णित है, सरकार के अतिरिक्त किसी पंजीयत व्यापारी (Registered dealer) को बेचा जाय तो भी विक्रय करने वाले व्यापारी द्वारा २% ही केन्द्रीय बिक्री कर देना पड़ेगा।

१. E forms का प्रयोग समझने के लिये इसी अध्याय में उदाहरण सख्या २ को देखिये तथा अध्याय ७ में केन्द्रीय बिक्री कर (राजस्थान) नियम १९५७ का १७ सी नियम देखिये।

## उपधारा (४)

उपधारा (१) से ही सम्बन्धित उपधारा (५) है जिसमें कहा गया है कि —

अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत किसी बिक्री के लिये उपधारा १ के प्रावधान लागू नहीं होंगे जब तक कि माल का विवेका व्यापारी नियत अधिकारी को नियत ढंग से निम्नलिखित घोषणा-पत्र व सार्टीफिकेट प्रस्तुत न करे—

(अ) घोषणा-पत्र—यह उस पंजीयत व्यापारी द्वारा भरा गया तथा हस्ताक्षरित होना चाहिये जिसको कि माल बेचा गया है। घोषणा पत्र का नियत फार्म नियत अधिकारी से प्राप्त किया जाना चाहिये तथा उसमें नियत विवरण होना चाहिए।

(ब) सार्टीफिकेट—यदि माल सरकार को बेचा गया है ओ कि पंजीयत व्यापारी नहीं है, तो यह सरकार के अधिकृत अधिकारी द्वारा भरा गया व हस्ताक्षरित होना चाहिये। इसका फार्म भी नियत है।

उपरोक्त (अ) वाक्य के लिये 'सी' फार्म प्रयोग में आता है तथा (ब) वाक्य के लिये 'डी' फार्म प्रयोग में आता है।

## उपधारा (२)

जिस व्यापारी की विक्रय राशि (Turn over) अथवा उसका कोई भाग यदि किसी ऐसी बिक्री से सम्बन्धित है ओ कि उपधारा (१) में सम्मिलित नहीं होती परन्तु अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत की जाती है, तो उस व्यापारी को उस विक्रय राशि पर निम्नलिखित प्रकार से कट्ट देना पड़ेगा —

(अ) घोषित माल के सम्बन्ध में, यह कर उपयुक्त राज्य के अन्दर ऐसे माल की बिक्री व खरीद को लागू होने वाली दर पर निकाला जायगा, तथा

(ब) घोषित माल के अतिरिक्त अन्य माल के सम्बन्ध में, इस कर की गणना ०% की दर पर पर अथवा उस दर पर ओ कि उपयुक्त राज्य में ऐसे माल की बिक्री व खरीद को लागू होती हो, इन दोनो में ओ भी दर ऊँची हो, की जायेगी,

और ऐसी गणना करने के प्रयोजनाय प्रत्येक ऐसा व्यापारी उपयुक्त राज्य के बिक्री कर कानून के अन्तर्गत कर भुदा करने के लिये दायी समझा जायेगा चाहे वह वास्तव में उस कानून के अन्तर्गत ऐसा दायी न हो।

उपधारा २ उस बिक्री से सम्बन्धित है जो कि :—

(१) अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत की गई हो, तथा

(२) उपधारा {१} में नहीं अखी हो।

इस उपधारा के अनुसार बिक्री कर विक्रय राशि पर निम्नलिखित दरों से लगेगा —

(१) यदि बिक्री ऐसे माल की की गयी है जो कि घोषित (Declared) है तो कर की दर वही होगी जो कि उपयुक्त राज्य (Appropriate State) में ऐसे माल की बिक्री व खरीद के लिए लागू होती है। यह दर घोषित माल के लिए अलग अलग राज्य अपने नियमों में निर्धारित करते हैं परन्तु केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम की धारा १५ के अनुसार यह दर बिक्री या खरीद के मूल्य के २% से अधिक नहीं हो सकती है।

घोषित माल का अर्थ उस माल से है जो कि इस अधिनियम की धारा १५ के अन्तर्गत 'विशेष महत्व' के घोषित किये गए हैं।

( २ ) यदि बिक्री अधोषित माल से सम्बन्धित है तो कर निर्धारित दो-दो-से-से जो भी ऊँची हो, उस पर लगाया जायेगा :—

( १ ) सात-प्रतिशत, व

( २ ) वह दर जो कि उपयुक्त राज्य में ऐसे माल की बिक्री व खरीद पर लागू होती हो ।

विभिन्न राज्य अपने बिक्री कर—नियमों के अन्तर्गत अधोषित माल की दर नियत करते रहते हैं। इस प्रकार के माल की बिक्री व खरीद पर कर की दर न्यूनतम ७% है ।

उपधारा ( १ ) व उपधारा ( २ ) में चाहे कुछ भी दिया हो यदि उपयुक्त राज्य के बिक्री कर कानूनों के अन्तर्गत किसी व्यापारी द्वारा की गयी किसी भी माल की बिक्री या खरीद सामान्यतया कर मुक्त है या उस पर सामान्यतया ऐसी दर पर कर लगना है जो कि १% से कम हो (चाहे उसे कर कहा जाय अथवा फीस या कोई अन्य नाम दिया जाय) तो इस अधिनियम के अन्तर्गत उनकी विक्रय राशि पर दिये जाने वाला कर जहाँ तक कि उसको विक्रय राशि अथवा विक्रय राशि का भाग ऐसे माल की बिक्री से सम्बन्धित है, शून्य होगा अथवा अवस्थानुसार कम दर पर लगाया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ माल की बिक्री या खरीद, उपयुक्त राज्य के बिक्री-कर कानून के अन्तर्गत सामान्यतया पर कर से मुक्त नहीं समझी जायेगी यदि उस कानून के अन्तर्गत वह किसी विशिष्ट अवस्थानुसार व विशिष्ट शर्तों के अधीन मुक्त की गई है अथवा जिसके सम्बन्ध में कर विशिष्ट स्तरों (Stages) पर लगाया गया हो अथवा माल की विक्रय राशि के सम्बन्ध में कर किसी अन्य प्रकार से लगाया गया हो ।

इस उपधारा २ (अ) के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय माल की बिक्री व खरीद पर कर या तो शून्य होगा अथवा अवस्थानुसार कम दर पर लगाया जायेगा यदि—

( १ ) किसी उपयुक्त राज्य के बिक्री-कर कानूनों के अन्तर्गत एक व्यापारी द्वारा की गयी किसी भी माल की बिक्री या खरीद सामान्यतया कर-मुक्त है, अथवा

( २ ) ऐसी बिक्री या खरीद पर सामान्यतया १% से कम दर पर कर लगता हो । इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि उपरोक्त प्रकार से कर-मुक्त होना अथवा कम दर पर कर देना 'सामान्य' अवस्था में ही होना चाहिए, 'विशिष्ट' अवस्था में नहीं । यदि कोई व्यापारी कुछ विशिष्ट अवस्थानुसार, व विशिष्ट शर्तों के अन्तर्गत कर-मुक्त हो जाता है या कम दर पर कर देता है तो वह उपधारा २ (अ) के अनुसार केन्द्रीय बिक्री कर के हेतु न तो कर-मुक्त ही हो सकेगा और न उसको कम दर पर कर देने का लाभ ही मिल सकेगा ।

उपधारा २ में कहा गया है कि 'कर की गणना करने के लिये प्रत्येक व्यापारी उपयुक्त राज्य के बिक्री-कर कानून के अन्तर्गत कर अदा करने के लिये दायी समझा जायेगा चाहे वह वास्तव में उस कानून के अन्तर्गत ऐसा दायी न हो ।' इस वाक्य में तथा उपधारा ( २ अ ) के प्रावधानों में कोई मतभेद नहीं है, यह बात भली प्रकार से समझ लेनी चाहिये ।

व्यापारी का दायी होना एक दूसरी बात जबकि उस पर कम दर पर कर लगाना एक भिन्न बात है । उपधारा २ का यह वाक्य किसी व्यापारी को दायी बनाने तक ही सीमित है परन्तु उपधारा २ (अ) के अन्तर्गत यह माना जा चुका है कि वह व्यापारी दायी है लेकिन फिर भी किसी उपयुक्त राज्य के कानून के अधीन उस पर सामान्य तौर से कर कम दर से लगता है अथवा लगता ही नहीं है, तो यह नहीं समझना चाहिए कि इन दोनों उपधाराओं के प्रावधानों में मतभेद है ।

### उपधारा ३

यह उपधारा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस उपधारा के अन्तर्गत जिस माल का वर्णन किया गया है, वह माल धारा ६ (२) को तथा धारा ८ (१) (ब) को प्रभावित करता है।

इस उपधारा के अन्तर्गत जो माल दिया गया है वह निम्नलिखित है —

(अ) घोषित माल के सम्बन्ध में, उस श्रेणी या उन श्रेणियों का माल है जो कि पंजीयत व्यापारी के पंजीयन सर्टीफिकेट (Certificate of registration) में वर्णित है तथा जिसे उस पंजीयत व्यापारी ने पुनः विक्री (Resale) के हेतु खरीदा है।

(ब) घोषित माल के अतिरिक्त अन्य माल के सम्बन्ध में, उस श्रेणी या उन श्रेणियों का माल है जो कि पंजीयत व्यापारी के पंजीयन सर्टीफिकेट में वर्णित है तथा जिसे उस पंजीयत व्यापारी ने निम्नलिखित उद्देश्यों के हेतु खरीदा है —

(१) पुनः विक्रय के लिये, अथवा

(२) इस सम्बन्ध में बनाए गए केन्द्रीय सरकार के नियमों के अधीन निम्नलिखित कार्यों में अपने उपयोग के लिये :—

विक्री के लिए माल का निर्माण व विधिवत् करना (Manufacturing or Processing), या खान खोदने का कार्य, या विद्युत अथवा किसी अन्य शक्ति का उत्पन्न करना व वितरण करना।

(स) बारदाना अथवा अन्य ऐसी सामग्री जो कि माल खरीदने वाले पंजीयत व्यापारी के पंजीयन सर्टीफिकेट में वर्णित है और जो विक्री के हेतु माल के पैकिंग में काम आने के लिये हो।

(द) बारदाना अथवा अन्य ऐसी सामग्री जो कि निम्नलिखित का पैकिंग करने में प्रयोजन की गई है —

(१) किसी ऐसे माल या ऐसे माल की श्रेणियाँ जो कि वाक्य (अ) व (ब) में कही गई है तथा जो व्यापारी के पंजीयन सर्टीफिकेट में वर्णित हैं, अथवा

(२) उस बारदाने या सामग्री का ही पैकिंग करने के लिए जो कि वाक्य (स) में कही गई है और जो व्यापारी के पंजीयन सर्टीफिकेट में वर्णित है।

इस उपधारा ३ में जो माल दिया हुआ है, यदि उसे किसी पंजीयत व्यापारी को बेचा जाता है तो विक्रय करने वाले पंजीयत व्यापारी को अपनी विक्रय राशि का केवल २% विक्री कर देना पड़ेगा [धारा ८ (१) (ब)] बशर्त कि क्रय करने वाला पंजीयत व्यापारी विक्रेता को 'सी' फार्म भर कर भेजे [धारा ८ (४) (घ)]

विक्री कर अधिनियम के अनुसार, विक्रेता जो विक्री-कर देता है उसे वह श्रेता से वसूल कर लेता है। इसलिये श्रेता, विक्री कर की ऊँची दर से बचने के लिये 'सी' फार्म विक्रेता को भेजता है।

धारा ६ (२) के अधीन यदि इस माल की जो कि उपधारा (३) में दिया हुआ है, उत्तरवर्ती विक्री की जाती है तो उम उत्तरवर्ती विक्री पर कोई कर नहीं लगता बशर्त कि ई-प्रथम व ई-द्वितीय फार्म इसके प्रावधानों के अनुसार प्रयोग किये गये हों।

उदाहरण २—आगरे का 'अ' व्यापारी बम्बई के 'ब' व्यापारी को माल बेचता है, माल के बम्बई पहुँचाने से पूर्व 'ब' उस माल को देहली के 'द' को बेच देता है। माल वही है जो कि धारा ८ (३) में वर्णित है तथा ये तीनों व्यापारी पंजीयत व्यापारी हैं। यह ज्ञात करना है कि विक्री कर अधिनियम के प्रावधानों का लाभ उठाते हुए विक्री का क्या ढग होना चाहिये।

हल—ब व्यापारी अ के पास माल के आदेश के साथ 'सी फाम भेजेगा और उससे माल के साथ-साथ E I फाम भेजने की प्राप्ति करेगा क्योंकि वह उस माल की उत्तरवर्ती बिक्री करना चाहता है। अ माल भेज देगा तथा E I फाम भेज देगा। 'अ उस माल की बिक्री पर २% बिक्री कर देने का उत्तरदायी है, वह उस बिक्री कर को ब से वसूल कर लेगा। अ बिक्री कर प्राधिकारियों को सतुष्ट करने के लिये ब से प्राप्त सी फाम प्रस्तुत करेगा अब ब माल के अधिकार सम्बन्धी विपन्नो का हस्तांतरण करके माल के भाग में ही उस माल का द को बेचता है। यहा द सी' फाम ब को भेजेगा और ब E II फाम द को भेजेगा। माल बेचने पर द कोई अतिरिक्त बिक्री कर नहीं देने का उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि वह उत्तरवर्ती बिक्री है अतः द कोई अतिरिक्त बिक्री कर द से वसूल नहीं करेगा। वह द से केवल बीजक का मूल्य जिसमें 'अ द्वारा चाज किया गया २% बिक्री कर सम्मिलित है वसूल करेगा। बिक्री-कर अधिकारियों को सतुष्ट करने के लिये कि यह बिक्री धारा ५ (२) के अन्तर्गत की गई थी ब उन अधिकारियों को द से प्राप्त सी फाम तथा अ से प्राप्त E I फाम प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार यदि द किसी अन्य पंजीयत व्यापारी को नियमानुसूल माल बेचता है तो वह उससे सी फाम प्राप्त करेगा तथा उसको E II फाम भेजेगा और अपने बिक्री कर अधिकारियों के सामने ब से प्राप्त E II फाम व उस अन्य व्यापारी से प्राप्त सी फाम प्रस्तुत करेगा ताकि उस बिक्री पर धारा ६ (२) के अन्तर्गत कर न लगे।

उपधारा (३) में दिये गये माल का अध्ययन करना भी आवश्यक है। इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमुख हैं —

(१) इस माल से सम्बन्धित जो इस अधिनियम में छूट या लाभ प्राप्त है वे केवल पंजीयत व्यापारी के लिये हैं अपजंयत व्यापारी के लिये नहीं।

(२) धारा ५ (१) (ब) के आधीन इस माल के विक्रय पर केवल २% बिक्री-कर लगता है।

(३) धारा ६ (२) के आधीन की गयी इस माल की उत्तरवर्ती बिक्री कर मुक्त होती है।

(४) इस माल से सम्बन्धित छूट प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि वह माल पंजीयत व्यापारी के पंजीयत सर्टिफिकेट में अवश्य लिखा हो। यदि कोई ऐसा माल है जो भले ही उपधारा ३ के अन्तर्गत आता है परन्तु वह व्यापारी के पंजीयत सर्टिफिकेट में नहीं लिखा हुआ है तो उस व्यापारी को उस माल से सम्बन्धित छूट नहा मिलेगी।

(५) घोषित माल का अथ उस माल से है जो कि धारा १४ में विशेष महत्व का घोषित किया गया है। इस घोषित माल के सम्बन्ध में छूट प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि वह पुनः बिक्री के लिये ही खरीदा गया हो।

(६) अपोषित मान पुनः बिक्री के लिये ही हो सकता है तथा उस व्यापारी के द्वारा अपने उपयोग के लिये भी हो सकता है। परन्तु उपयोग के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि निम्नलिखित कार्यों के लिये ही उपयोग किया जाय —

बिक्री हेतु माल का निर्माण विधिवत करना खान खोदने का कार्य तथा विद्युत व किसी अन्य शक्ति का उत्पन्न व वितरण करना।

(७) वारदाने तथा पैकिंग के अन्य समान के बारे में :—

(अ) वह समान जो कि बिक्री के माल का पैकिंग करने के लिये प्रयुक्त किया गया हो, तथा

(ब) वह समान जो कि निम्नलिखित का पैकिंग करने के लिये प्रयोग किया गया हो :—

(1) वह माल जो कि उपधारा ३ अ तथा ३ ब में वर्णित है, तथा

(11) जो वारदाना या पैकिंग का सामान उपधारा ३ स के अनुसार खरीदा गया है, उनकी बिक्री उनका ही पैकिंग करने के लिए हेतु इस उपधारा में सम्मिलित किया हुआ है।

## उपधारा ५

चाहे इस धारा में कुछ भी दिया गया हो, यदि राज्य की सरकार सन्तुष्ट है कि जन हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति करके निर्देश दे सकती है कि ऐसे माल व माल को श्रेणियों के सम्बन्ध में, जो कि विज्ञप्ति में लिखे गये हैं, तथा ऐसी शर्तों के अधीन जिनको वह लगाना उचित समझे, किसी राज्य में व्यवसाय का स्थान रखने वाले व्यापारी के द्वारा उस बिक्री पर उस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर नहीं दिया जायेगा जो कि अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत उस व्यवसाय के स्थान से की गई हो, अथवा वह निर्देश दिया जा सकता है कि ऐसी बिक्री पर उपधारा १ या उपधारा २ में निर्धारित दर से ऐसी कम दर पर कर लगाया जायेगा जो कि विज्ञप्ति में वर्णित की जाय।

यह धारा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार को इस धारा के प्रावधानों के अनुसार यह अधिकार दिया गया है कि वह अन्तर्राज्यीय व्यापार में लगाने वाले कर को मुक्त करदे अथवा कर की दर को कम करदे, यदि ऐसा करना जन हित में हो।

यह अधिकार पहले केन्द्रीय सरकार को ही मिला हुआ था परन्तु इस अधिनियम में १९५७ में संशोधन करके यह अधिकार राज्य सरकारों को सौंप दिया गया। राज्य सरकार इस उपधारा के अधीन विज्ञप्ति द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर कर की दरें घटाती रहती है अथवा, उन वस्तुओं को कर मुक्त करती रहती है।



## व्यापारियों का पंजीयन (Registration of Dealers)

धारा ७ (१) के अनुसार—प्रत्येक व्यापारी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कर देने का दायी है, ऐसी अवधि के अन्दर जो इसके हेतु नियत की जाय, इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के लिये एक प्रार्थना-पत्र उपयुक्त राज्य में ऐसे प्राधिकारी को देगा जिसे केन्द्रीय सरकार सामान्य व विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, तथा प्रत्येक ऐसे प्रार्थना पत्र में वे सभी विवरण होंगे जो कि नियत किये जाय ।

इस उपनियम की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :—

(i) करदायी व्यापारी के लिये पंजीयन आवश्यक—इस धारा के अनुसार ऐसे प्रत्येक व्यापारी के लिये पंजीयन कराना आवश्यक है जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कर देने का दायी हो । इसका अर्थ यह है कि ऐसे व्यापारियों के लिये जो राज्य बिक्री-कर कानून के अन्तर्गत बिक्री-कर देने के दायी हैं परन्तु केन्द्रीय बिक्री कर के लिये दायी नहीं हैं, इस अधिनियम के अन्तर्गत अपना पंजीयन कराना आवश्यक नहीं है परन्तु यदि वे पंजीयन कराना चाहे तो वे कर सकते हैं । इस अधिनियम की धारा ६ के अनुसार, एक व्यापारी अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत की गयी बिक्री पर केन्द्रीय कर देने का दायी होता है । इसलिये ऐसे व्यापारियों के लिये जिनका दायित्व धारा ६ के अनुसार निर्धारित है, यह आवश्यक है कि वे अपना पंजीयन धारा ७ के प्रावधानों के अन्तर्गत करायें ।

(ii) पंजीयन कराने की अवधि—केन्द्रीय बिक्री-कर (पंजीयन एवं विक्रय राशि) १९५७ के नियम ४ (१) अनुसार, पंजीयन के लिये प्रार्थना-पत्र व्यापारी द्वारा उस तिथि से ३० दिन के अन्दर ही दिया जाना चाहिये जिस तिथि को वह व्यापारी इस अधिनियम के अन्तर्गत कर देने के लिये दायी हुआ था ।

इस अधिनियम के अनुसार एक व्यापारी कर देने के लिये धारा ६ के अन्तर्गत दायी होता है । धारा ६, १ जुलाई १९५७ को लागू की गयी थी । अतः उन व्यापारियों के लिये जो कि १ जुलाई १९५७ को अन्तर्राज्यीय व्यापार करते थे, पंजीयन की अन्तिम तिथि ३१ जुलाई १९५७ हुई । व्यापारियों के लिये पंजीयन कराने की कोई अवधि नियत नहीं है । [धारा ७ (२)]

(iii) उपयुक्त राज्य में प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र देना—यदि एक व्यापारी एक ही राज्य में व्यवसाय के एक या अधिक स्थान रखता है तो उसके लिये उपयुक्त राज्य वही राज्य है जहाँ कि उसके व्यवसाय स्थान हैं ।

परन्तु यदि किसी व्यापारी के व्यवसाय के स्थान एक से अधिक राज्य में हैं तो प्रत्येक अलग राज्य वाले स्थान के लिये वह उपयुक्त राज्य समझा जायेगा जिस राज्य में वह स्थान स्थित है।

केन्द्रीय बिक्री-कर नियम, १९५७ के नियम २ में यह कहा गया है यदि एक व्यापारी एक राज्य में व्यवसाय के एक से अधिक स्थान रखता है तो वह सब स्थानों के सम्बन्ध में एक ही प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें इन नियमों के प्रयोजनार्थ वह व्यवसाय का प्रमुख स्थान भी लिखेगा। व्यापारी यह प्रार्थना-पत्र अपने व्यवसाय के प्रमुख स्थान से सम्बन्धित नियत प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।” परन्तु यदि किसी व्यापारी के व्यवसाय के स्थान विभिन्न राज्यों में स्थिति है तो उसको भिन्न भिन्न राज्यों में पंजीयन कराना पड़ेगा।

प्रार्थना-पत्र ऐसे को दिया जायेगा जिसे केन्द्रीय सरकार नियत करे।

प्रार्थना-पत्र में विवरण—इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन करने के लिये ‘ए’ फार्म (A form) में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है यह फार्म निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।

व्यक्तिगत व्यवसाय के लिये व्यवसाय का स्वामी, फार्म के लिये एक साक्षीदार, हिन्दू अविभाजित परिवार के लिये भर्त्ता या प्रबन्धक, कम्पनी के लिये सचालक, प्रबन्ध अधिकर्ता अथवा कोई प्रधान पदाधिकारी, सरकार के लिये सरकार के द्वारा अधिकृत कोई पदाधिकारी, अन्य संस्थाओं के लिये व्यवसाय का प्रबन्ध करने वाला प्रधान अधिकारी।

धारा ७ (२) के अनुसार एक व्यापारी उपयुक्त राज्य के बिक्री-कर कानून के अन्तर्गत कर देने का दायी माना जायेगा चाहे उस कानून के अन्तर्गत उसके द्वारा की गई बिक्री या खरीद कर-मुक्त हो अथवा उसे कर की वापिसी व छूट स्वीकार की गयी हो।

इस उपधारा की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :—

(१) उन व्यापारियों के अतिरिक्त जो धारा ६ के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर देने के दायी हैं, निम्नलिखित व्यापारी भी इस अधिनियम के अन्तर्गत अपना पंजीयन करा सकते हैं —

(अ) कोई भी व्यापारी यदि वह उपयुक्त राज्य के बिक्री कर कानून के अन्तर्गत कर देने का दायी हो, तथा

(ब) जिस राज्य में बिक्री कर कानून लागू नहीं है तो कोई ऐसा व्यापारी जो कि उस राज्य में अपने व्यवसाय का स्थान रखता हो।

इस उपधारा में वे व्यापारी आते हैं जो कि उपधारा (१) में सम्मिलित नहीं किये गये हैं तथा उपरोक्त (अ) व (ब) में से कोई एक शर्त पूरी करते हो।

(१) इस उपधारा के व्यापारियों के लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन कराना आवश्यक नहीं है। यह उनकी इच्छा पर ही निर्भर है कि वे पंजीयन करावें अथवा नहीं। सामान्यतः पंजीयन कराना ही बहुत सी दशाओं में ठीक रहता है।

उदाहरण—एक व्यापारी ‘अ’ राजस्थान में भोजे बनाता है जिनको वह राजस्थान में ही बेचता है। अतः वह राजस्थान बिक्री-कर कानून के ही अन्तर्गत बिक्री-कर देने का दायी है, केन्द्रीय व बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत नहीं। अगर वह व्यापारी भोजे बनाने के लिये अन्य राज्यों से कच्चा माल मँगाता है तो उसके लिये अच्छा यह है कि वह केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत अपना पंजीयन करावे ताकि उसे कच्चे माल पर १% ही बिक्री कर देना पड़े। इस व्यापारी के लिये केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन कराना आवश्यक नहीं है क्योंकि वह तो

श्रेता है, विक्रेता नहीं। परन्तु यदि वह अपना पंजीयन नहीं कराता है तो कच्चे माल का विक्रेता इस व्यापारी से बजाय २% बिक्री कर के अधिक दर पर कर वसूल करेगा।

(ii) इस उपधारा के व्यापारियों के लिये पंजीयन कराने की कोई अवधि नियत नहीं है। केन्द्रीय बिक्री-कर नियम १९५७ की नियम सख्या ४ (२) में यह कहा गया है कि धारा ३ (२) के अन्तर्गत पंजीयन के लिये इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् कमी भी प्रार्थना-पत्र दिया जा सकता है।

धारा ७ (३) के अनुसार—यदि वह अधिकारी जिसको उपधारा (१) या (२) के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है, सतुष्ट हो जाता है कि प्रार्थना-पत्र इस अधिनियम के प्रावधानों के व नियमों के अनुसार ही है, तो वह प्रार्थी का पंजीयन कर लेगा तथा नियत फार्म में पंजीयन का सर्टीफिकेट उसको प्रदान कर देगा। सर्टीफिकेट में धारा ८ (१) के प्रयोजनार्थ भास की श्रेणी या श्रेणियाँ भी उल्लेखित की जायेंगी।

इस उपधारा से सम्बन्धित केन्द्रीय बिक्री-कर नियम १९५७ की नियम सख्या (५) में कहा गया है।

नियम ५ (१)—आवश्यक जाँच करने के पश्चात् जब विज्ञप्त प्राधिकारी (Notified authority) सतुष्ट हो जाता है कि प्रार्थना-पत्र में दिया गया विवरण सही व पूरा है तथा नियम ४ (३) में लिखी गई फीस चुका दी गई है तो वह उस प्रार्थी व्यापारी का पंजीयन कर लेगा तथा उसे 'बी' फार्म (Form B) में एक सर्टीफिकेट जारी कर देगा। वह प्राधिकारी व्यवसाय के प्रमुख स्थान के अतिरिक्त राज्य के अन्य प्रत्येक व्यवसाय स्थान के लिए भी ऐसे सर्टीफिकेट की एक प्रति देगा।

नियम ५ (२)—यदि विज्ञप्त अधिकारी प्रार्थना-पत्र के विवरण की सत्यता व पूर्णता के बारे में सतुष्ट नहीं है अथवा नियम ४ (३) में वर्णित फीस नहीं चुकाई गई है तो वह लिखित कारण देकर प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर देगा।

परन्तु इससे पूर्व कि प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया जाय, प्रार्थी को इस मामले में सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जायेगा और उसे इन बात का भी अवसर दिया जायेगा कि वह उक्त विवरणों को ठीक व पूरा कर सके तथा नियम ४ (३) की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

नियम ४ (३) के अनुसार प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर ५) फीस लगती है ऐसी फीस कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में प्रार्थना-पत्र पर लगाई जाती है। अधिनियम की धारा ८ (१) (ब) के अनुसार यदि वह माल जो कि धारा ८ (३) में दिया गया है, किसी पंजीयत व्यापारी को बेचा जाता है तो व्यापारी को विक्रय राशि पर २% बिक्री कर देना पड़ता है। इसके लिये धारा ७ (३) के यह आवश्यक है कि व्यापारी के पंजीयन सर्टीफिकेट में वह माल वर्णित किया जाय जिसके लिये उसका पंजीयन हुआ है। वह उसी माल के सम्बन्ध में पंजीयत व्यापारी समझा जायेगा जो माल उसके सर्टीफिकेट में दिया गया है।

धारा ७ (४) के अनुसार :

(अ) उस व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर जिसे सर्टीफिकेट प्रदान किया गया था, जहाँ कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो व्यापारी को उचित नोट देकर, उस प्राधिकारी द्वारा सर्टीफिकेट सशेषित किया जा सकता है। वह जारी किया था, यदि वह, सतुष्ट है कि पंजीयत व्यापारी द्वारा व्यवसाय के नाम, स्थान अथवा प्रकृति के बदलने के कारण, अथवा उस माल की श्रेणी

श्रेणियों को बदलने के कारण जिनमें कि वह व्यवसाय करता है, अथवा किसी अन्य कारण से, उसको जारी किये गये पजीयन सार्टीफिकेट में संशोधन की आवश्यकता है, या

(ब) उस अधिकारी द्वारा सार्टीफिकेट निरस्त किया जा सकता है जिसने इसे जारी किया था, यदि वह पजीयत व्यापारी को नोटिस देने के पश्चात् सन्तुष्ट हो जाता है कि व्यापारी ने व्यवसाय करना बन्द कर दिया है अथवा व्यापारी विद्यमान नहीं है अथवा धारा ७ (२) के अनुसार पजीयत व्यापारी उपयुक्त राज्य के बिक्री-कर कानून के अन्तर्गत कर देने के लिये दायी नहीं रहा है, अथवा कोई अन्य पर्याप्त कारण है।

पजीयन सार्टीफिकेट के संशोधन से सम्बन्धित केन्द्रीय बिक्री कर नियम १९५७ का नियम ७ (१) महत्वपूर्ण है जो कि निम्नलिखित है —

यदि एक व्यापारी यह चाहता है कि उसको जारी किये गये सार्टीफिकेट में कुछ संशोधन कर दिये जायें तो वह इस उद्देश्य के लिये विज्ञप्त प्राधिकारी को एक प्रार्थना-पत्र देगा जिसमें वह इच्छित संशोधन लिखेगा तथा ऐसा संशोधन करने के कारण भी लिखेगा। वह इस प्रार्थना-पत्र के साथ अपना सार्टीफिकेट तथा उसकी प्रतियाँ जो कि उसको प्रदान की गयी थी, नर्सी करेगा। वह प्राधिकारी कारणों से सन्तुष्ट होने पर सार्टीफिकेट तथा उसकी प्रतियों में ऐसे संशोधन कर देगा जो कि वह आवश्यक समझे।

नियम ६ के अनुसार, पजीयन सार्टीफिकेट को निरस्त करने के पूर्व विज्ञप्त प्राधिकारी व्यापारी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगा। यदि पजीयन निरस्त कर दिया जाता है तो व्यापारी विज्ञप्त प्राधिकारी को पजीयन सार्टीफिकेट व उसकी प्रतियाँ यदि उसको प्रदान की गई हैं समर्पित कर देगा।

धारा ७ (५) के अनुसार—एक पजीयत व्यापारी अपने पजीयन के निरसन के हेतु उस प्राधिकारी को जिसने कि उसे सार्टीफिकेट प्रदान किया था, एक नियत ढंग से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकता है जो कि वर्ष के अन्त होने से कम से कम ६ माह पूर्व किया जाना चाहिये, तथा यदि व्यापारी इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर अदा करने का दायी नहीं है तो प्राधिकारी पजीयन को निरस्त कर देगा और जहाँ वह ऐसा करता है वहाँ वह निरसन वर्ष के अन्त होने पर ही प्रभावशाली होगा।

इस उपधारा के अनुसार एक व्यापारी अपने पजीयन के निरसन के लिये स्वयं प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अतः पजीयन का निरसन दो प्रकार से होता है—(१) प्राधिकारी द्वारा नोटिस दिये जाने पर [उपधारा ४ (ब)] तथा (२) व्यापारी के प्रार्थना-पत्र देने पर (उपधारा ५)। यदि व्यापारी प्रार्थना-पत्र देकर अपने पजीयन का निरसन चाहता है तो उसको निश्चय अवधि में ही प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये। ऐसी अवधि सोमा पहली प्रकार के निरसन में निर्धारित नहीं है जहाँ कि प्राधिकारी द्वारा नोटिस दिये जाने से निरसन होता है।

केन्द्रीय बिक्री-कर नियम १९५७ का नियम १० इस उपधारा (५) से सम्बन्धित है। नियम १० में यही लिखा है कि व्यापारी को धारा ७ (५) में दिये गये नियत समय के अन्दर विज्ञप्त प्राधिकारी को पजीयन के निरसन के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये। प्रार्थना-पत्र के साथ सार्टीफिकेट व उसकी प्रतियाँ, यदि कोई प्रदान की गयी हो, प्रस्तुत की जानी चाहिये तथा ऐसे प्रार्थना-पत्र पर उस धारा के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जायेगा।

## पजीयन सार्टीफिकेट से सम्बन्धित अन्य नियम

केन्द्रीय बिक्री-कर नियम १९५७ की नियम सख्याये ६ व ८ निम्नलिखित हैं .—

**नियम ६—**पजीयन का सार्टीफिकेट व्यवसाय के उस प्रमुख स्थान पर रखा जायेगा जो कि सार्टीफिकेट में लिखा हुआ है तथा इस सार्टीफिकेट की एक प्रति राज्य के अन्दर प्रत्येक अन्य व्यवसाय-स्थान पर भी रखी जायेगी ।

इसी सम्बन्ध में केन्द्रीय बिक्री-कर (राजस्थान) नियम १९५७ के नियम ३ में कहा गया है कि पजीयन सार्टीफिकेट के धारक के लिये यह आवश्यक है कि वह इस सार्टीफिकेट को अपने उस व्यवसाय के भवन में एक प्रमुख स्थान पर लटका कर रहे जिस व्यवसाय के सम्बन्ध में वह सार्टीफिकेट उसको जारी किया गया है ।

**नियम ८—**यदि पजीयन सार्टीफिकेट खो जाता है, नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है अथवा उसके अक्षर मिट जाते हैं तो व्यापारी बिज्ञप्त प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर तथा २) ६० फीस देकर ऐसे सार्टीफिकेट की अनुलिपि (Duplicate) प्राप्त कर सकता है ।

यह जो फीस दी जाती है, वह कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में ही होती है ।

## कर-आरोपण, कर-वसूली तथा अर्थ-दण्ड

(Levy and Collection of Tax and Penalties)

### कर-आरोपण व कर-वसूली

कर लगाने तथा कर वसूल करने के सम्बन्ध में जो केन्द्रीय सरकार के अधिकार हैं, वे धारा ६ तथा ६ (अ) द्वारा राज्य सरकार को सौंप दिये गये हैं। इसलिये केन्द्रीय बिक्री-कर के निर्धारण की विधि व कार्यप्रणाली वही है जो कि एक राज्य में बिक्री-कर के लिये अपनायी जाती है।

धारा ६ (१) के अनुसार "अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत जो माल की बिक्री की गयी हो, चाहे ऐसी बिक्री धारा ३ के (अ) वाक्य के अन्तर्गत हुई हो अथवा (ब) वाक्य के अन्तर्गत हुई हो, ऐसी बिक्री पर कर उपधारा (३) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा ऐसे राज्य में लगाया व वसूल किया जायेगा जिस राज्य से माल का गमनागमन आरम्भ हुआ हो।

परन्तु एक राज्य से दूसरे राज्य को गमनागमन के बीच माल भी उस बिक्री के सम्बन्ध में जो कि उसी माल की प्रथम बिक्री की उत्तरवर्ती बिक्री हो तथा ऐसी उत्तरवर्ती बिक्री धारा ६ (२) के अन्तर्गत नहीं आती हो तो कर उस राज्य में लगाया या वसूल किया जायेगा जहाँ से उत्तरवर्ती बिक्री करने वाले पंजीयत व्यापारी ने ऐसे माल के क्रय करने के लिये धारा ८ (४) के (अ) वाक्य के प्रयोजनार्थ फार्म प्राप्त किया हो।"

### ६ (१) धारा की प्रमुख बातें

(१) कौन से राज्य में कर लगाया या वसूल किया जायेगा?—यह धारा इस बात को स्पष्ट करती है कि अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत जो कर लगाया जायेगा अथवा वसूल किया जायेगा वह उसी राज्य में होगा जहाँ से माल का गमनागमन आरम्भ हुआ था, चाहे उस माल की बिक्री धारा ३ (अ) के अनुसार हुई हो अथवा धारा ३ (ब) के अनुसार हुई हो।

धारा ३ के अनुसार माल की बिक्री या खरीद अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत हुई मानी जायेगी यदि बिक्री या खरीद—

(अ) एक राज्य में दूसरे राज्य को माल का गमनागमन उत्पन्न करती हो, अथवा

(ब) एक राज्य से दूसरे राज्य को माल के गमनागमन के बीच माल के अधिकार सम्बन्धी विषयों के हस्तांतरण से हुई हो।

अतः चाहे माल की बिक्री गमनागमन के बीच ही क्यों न हुई हो उस बिक्री पर उसी राज्य में कर लगाया या वसूल किया जायेगा जिस राज्य से माल का गमनागमन आरम्भ हुआ था।

**उदाहरण १—**जयपुर का 'अ' व्यापारी बम्बई के 'ब' व्यापारी को बिक्री के अनुबन्ध के अन्तर्गत माल भेजता है तो यहाँ उस बिक्री पर जो कर लगाया जायेगा, वह राज्यस्थान राज्य में लगेगा तथा उस कर की बसूली भी राजस्थान राज्य में ही होगी क्योंकि यह माल राजस्थान राज्य से चलना आरम्भ हुआ था।

**उदाहरण २—**यदि कलकत्ते का 'क' व्यापारी अपनी बम्बई ब्रांच को कुछ माल भेजता है और वह उस माल को गमनागमन के बीच ही 'ग' को माल के अधिकार सम्बन्धी विपत्रों का हस्तातरण करके बेच देता है। तो यहाँ 'ग' को की गयी बिक्री पर जो कर लगेगा वह पश्चिम बंगाल राज्य में ही लगेगा तथा वही बसूल किया जायेगा।

अब प्रश्न उत्तरवर्ती बिक्री के विषय में आता है कि उत्तरवर्ती बिक्री पर कर किस राज्य में लगेगा अथवा बसूल रिया जायेगा।

हम देख चुके हैं कि धारा ६ (२) के अनुसार उत्तरवर्ती बिक्री पर कोई कर नहीं लगता यदि उस धारा की शर्तें पूरी होती हों। धारा ६ (२) उसी माल की उत्तरवर्ती बिक्री को कर-मुक्त करती है जो कि धारा ८ (३) में वर्णित है। यदि कोई उत्तरवर्ती बिक्री ऐसे माल की की जाती है जो धारा ८ (३) में वर्णित माल से सम्बन्धित नहीं है अथवा वह बिक्री धारा ६ (२) की अन्य शर्तों को जो कि पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पूरी नहीं करती है, तो वह कर मुक्त नहीं होगी। इस दशा में ऐसी उत्तरवर्ती बिक्री पर कर उस राज्य में लगेगा अथवा बसूल किया जायेगा जिस राज्य से उत्तरवर्ती बिक्री करने वाले व्यापारी ने उस माल को क्रय करने के लिये 'सी' फार्म प्राप्त किया था।

**उदाहरण ३—**यदि कलकत्ते का 'क' व्यापारी देहली के 'द' व्यापारी को कुछ माल बिक्री के अनुबन्ध के अन्तर्गत भेजता है। यह माल ऐसा है जिसकी उत्तरवर्ती बिक्री धारा ६ (२) के अन्तर्गत कर मुक्त नहीं है। 'द' व्यापारी इस माल को उत्तर-प्रदेश के व्यापारी 'उ' को माल के सम्बन्धी अधिकार विपत्रों का हस्तातरण करके उस समय बेच देता है जबकि माल मार्ग ही में है और वह देहली नहीं पहुँचा है। यहाँ 'उ' को की गयी बिक्री पर देहली राज्य में कर ।। जायेगा क्योंकि 'द' ने 'सी' फार्म देहली से प्राप्त किया था और उसे प्राप्त करने के पश्चात् 'क' को भेजा था। यहाँ यह माना जायेगा कि 'उ' देहली बिक्रीकर के आधीन पजीयत व्यापारी नहीं है। यदि वह पजीयत होता और उसके द्वारा खरीदा गया माल उसके पजीयन सर्टीफिकेट में लिखा हुआ होता तो 'द' द्वारा जो बिक्री की गयी है वह उसके लिए धारा ६ (२) के अन्तर्गत कर मुक्त होती।

उपरोक्त उदाहरण में दो प्रकार की बिक्रिया हैं —

(अ) प्रथम बिक्री—जो कि 'क' ने 'द' को की है। यहाँ 'क' ३% बिक्री-कर देने के लिये दायी है और वह इसे 'द' से प्राप्त कर लेगा यदि (१) 'द' पजीयत व्यापारी है, तथा (२) वह माल धारा ८ (३) के अन्तर्गत है।

(ब) उत्तरवर्ती बिक्री—जो कि 'द' ने 'उ' को की है। यहाँ 'द' धारा ८ (२) के अनुसार बिक्री कर देने के लिये दायी होगा और वह उसे 'उ' से प्राप्त कर लेगा क्योंकि 'उ' पजीयत व्यापारी नहीं है।

(ii) कौन सी सरकार द्वारा यह कर लगाया व वसूल किया जावेगा ?—इस कर को लगाने व वसूल करने का अधिकार भारत सरकार को ही है परन्तु भारत सरकार ने उपधारा ३ के अन्तर्गत ये अधिकार राज्य सरकारों को सौंप दिये हैं। अतः राज्य सरकारें इस कर को भारत सरकार की ओर से व्यापारी पर लगानी हैं तथा उनसे वसूल करती हैं। उपधारा ३ का अध्ययन करने पर हम देखेंगे कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को इस कर के निर्धारण करने की कार्य प्रणाली निश्चित करने का भी अधिकार दिया है।

धारा ९ (२) के अनुसार धारा १० ए के अन्तर्गत लगाया गया अर्थ-दंड, उपधारा ३ के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित राज्य में वसूल किया जायेगा,—

(अ) धारा १० के (ब) अथवा (द) वाक्य में लिखे हुए अपराध के सम्बन्ध में वह राज्य जिसमें कि माल क्रय करने वाले व्यक्ति ने ऐसे माल के क्रय करने के सम्बन्ध में धारा ८ (४) के (अ) वाक्य के प्रयोजनार्थ कर्म प्राप्त किया या,

(ब) धारा १० के (म) वाक्य में लिखे हुए अपराध के सम्बन्ध में वह राज्य जिसमें माल क्रय करने वाले व्यक्ति द्वारा अपना पजीयन करा लेना चाहिये या यदि वह अपराध नहीं किया गया होता।”

यह उपधारा अर्थ-दंड से सम्बन्धित है जिसका अध्ययन हम आगे धारा १० तथा १० ए के अन्तर्गत करेंगे। यहाँ इस उपधारा का उद्देश्य यह ज्ञात कराना है कि यह अर्थ-दंड भारत सरकार द्वारा धारा ६ की उपधारा ३ के प्रावधानों के अनुसार किस राज्य में वसूल किया जायगा।

धारा ६ (३) के अनुसार “उपयुक्त राज्य के सामान्य विक्री-कर कानून के अन्तर्गत जो प्राधिकारी उपस्थित समय में कर के निर्धारण, कर की वसूली तथा कर की अदायगी का निष्पादन करने के लिये अधिकृत किये गये हैं, वे भारत सरकार की ओर से तथा उस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये नियमों के अधीन उसी प्रकार से उस ऐसे कर का निर्धारण, कर की वसूली तथा कर की अदायगी का निष्पादन करेंगे, जिस कर में अर्थ-दंड भी सम्मिलित है तथा जो इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा देय है, जिस प्रकार की राज्य के सामान्य विक्री-कर कानून के अन्तर्गत माल की विक्री या खरीद पर कर का निर्धारण किया जाता है तथा कर की वसूली व अदायगी की जाती है, तथा इसके प्रयोजनार्थ वे सभी तथा किमी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जो कि उनको राज्य के सामान्य विक्री-कर कानून के अन्तर्गत प्राप्त हैं, तथा ऐसे कानून के प्रावधान जिनमें विवरण-पत्र, पुनरावेदन, पर्यवेक्षण, पुनरीक्षण, सदर्भ अर्थ-दंड एवं राजीनामे वाले अपराध सम्बन्धी प्रावधान सम्मिलित हैं, तदनुसार लागू होंगे।

परन्तु यदि किसी राज्य में अथवा राज्य के किसी भाग में सामान्य विक्री-कर कानून लागू नहीं है तो केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में नियम बनाकर इस उपधारा में वर्णित सभी अथवा कुछ मामलों के लिये आवश्यक प्रावधान बना सकती है, तथा ऐसे नियमों में यह प्रावधान कर सकती है कि किन्हीं भी नियमों का भंग करना ऐसा अर्थ-दंड से दण्डनीय होगा जो कि ५००) ६० तक हो सकता है, और जहाँ अपराध लगातार चलता रहे तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये ५०) २० तक अर्थ-दंड लग सकता है। जितने दिनों तक वह अपराध चलता रहे।”

धारा ६ (३) की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं,—

(१) जो प्राधिकारी उपयुक्त राज्य में राज्य की विक्री-कर का निर्धारण (assessment), विक्री-कर की वसूली (collection) तथा अदायगी का निष्पादन (enforcement of payment) करते हैं, वे प्राधिकारी ही के केन्द्रीय विक्री-कर के सम्बन्ध में इन कार्यों को करेंगे।



- (ii) उक्त प्राधिकारी इन कार्यों को भारत सरकार की ओर से तथा केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन करेंगे।
- (iii) अर्थ-दण्ड (penalty) के निर्धारण, उसकी वसूली तथा अदायगी के निष्पादन के सम्बन्ध में भी इन प्राधिकारियों को वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जोकि उनको कर (tax) के सम्बन्ध में प्राप्त हैं।
- (iv) प्राधिकारियों को जो अधिकार व शक्तियाँ राज्य के सामान्य बिक्री कर कानून के अन्तर्गत प्राप्त हैं, उन अधिकार व शक्तियों को केन्द्रीय बिक्री-कर के सम्बन्ध में भी उनके द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।
- (v) राज्य के सामान्य बिक्री-कर कानून के प्रावधान केन्द्रीय बिक्री-कर के निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में भी लागू होंगे —

बिवरण पत्र (Returns), पुनरावेदन (appeal), पर्यवेक्षण (reviews), पुनरीक्षण (revisions), सदर्थ (referees) अर्थ-दण्ड (penalties) तथा राजीनामे वाले अपराध (compounding offences)।

- (vi) जहाँ किसी राज्य में अथवा राज्य के किसी भाग में सामान्य बिक्री-कर कानून लागू नहीं है, वहाँ केन्द्रीय सरकार इस उपधारा में वर्णित मामलों के लिये आवश्यक प्रावधान बना सकती है तथा नियम भग करने के लिये दण्ड घोषित कर सकती है जो कि अधिक से अधिक ५००) ४० तक हो सकता है तथा लगातार चलने वाले अपराधों के सम्बन्ध में प्रति अपराध के दिवस के लिये ५०) प्रति दिन तक हो सकता है।

इस उपधारा में कहा गया है कि राज्य के प्राधिकारी केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन कार्य करेंगे। ऐसे नियम दो हैं —

- (१) केन्द्रीय बिक्री-कर (पजीयन एवं विक्रय राशि) नियम १९५७, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा १३ (१) के अन्तर्गत बनाये गये हैं तथा जो पजीयन व विक्रय राशि से ही प्रमुखतः सम्बन्धित है, तथा
- (२) केन्द्रीय बिक्री-कर (राजस्थान) नियम १९५७, जो कि राजस्थान राज्य में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा १३ (३) व (४) के अन्तर्गत बनाये हैं।

ये दोनों प्रकार के नियम अध्याय ७ में दिये गये हैं तथा महत्वपूर्ण हैं। केन्द्रीय बिक्री कर (राजस्थान) १९५७ की नियम सख्या २१, २२ तथा २३ में कहा गया है कि निम्नलिखित मामलों में केन्द्रीय कर के लिये वे प्रावधान ही लागू होंगे जोकि राज्य बिक्री कर पर लागू होते हैं।

**केवल पजीयत व्यापारियों द्वारा कर की वसूली (Collection of Tax to be only by Registered Dealers)**

धारा ६ (अ) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जा कि पजीयत व्यापारी नहीं है, अन्तराज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत, माल की बिक्री के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के रूप में कोई धन राशि वसूल नहीं करेगा, तथा जो वसूली पजीयत व्यापारियों द्वारा की जायेगी, वह केवल इस अधिनियम तथा अधिनियम के अन्तर्गत बने हुए नियमों के अनुसार ही की जायेगी।

यहाँ पजीयत व्यापारियों द्वारा कर वसूल करने का अर्थ उस कर से है जिसके देने के लिये पजीयत व्यापारी, विक्रेता होने के नाते दायी होते हैं, परन्तु वे उस कर को स्वयं से वसूल कर लेते हैं। इस धारा में यह स्पष्ट किया गया है कि वे केवल पजीयत व्यापारी ही क्र्रेताओं से कर की वसूली कर सकते हैं, अपजीयत व्यापारी नहीं।

क्रोताओं से कर वसूल करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय बिक्री-कर (राजस्थान) नियम १९५७ की नियम सख्या ६ 'क्रोताओं से कर वसूल करना' प्रमुख है। इस नियम में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा माल की बिक्री के लिये कैशमीमो या क्रेडिट मीमो जारी करना चाहिये जिसमें बिक्री-मूल्य तथा बिक्री-कर अलग-अलग दिखाने चाहिये। उसे इन मीमो की नकल भी अपने पास रखनी चाहिये। ऐसे व्यापारी द्वारा एक असम हिसाब भी रखा जाना चाहिये जिसमें वह दिन प्रतिदिन की कर-वसूली दिखताये तथा साथ में कैश-मीमो व क्रेडिट मीमो का नम्बर व तिथि भी लिखे। जो कैश मीमो या क्रेडिट मीमो जारी किया जाय, वह एक बिल्द बंधी पुस्तक से होना चाहिये जिसमें उसकी नकल व मूल प्रति के पृष्ठों पर क्रम से सख्या पड़ी हो।

### अर्थ-दण्ड (Penalties)

धारा १० के अनुसार यदि कोई व्यक्ति—

- (घ) धारा ७ की आवश्यकतानुसार अपना पंजीयन नहीं कराता है, या
- (ङ) पंजीयत व्यापारी होने पर किसी श्रेणी का माल क्रय करने में झूठा प्रदर्शन करता है कि उस श्रेणी का माल उसके पंजीयन सर्टीफिकेट में लिखा हुआ है, या
- (च) पंजीयत व्यापारी न होने पर, अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत माल का क्रय करते समय झूठा प्रदर्शन करता है कि वह पंजीयत व्यापारी है, या
- (ट) धारा ८ (३) के (ब) वाक्य में लिखित प्रयोजन के लिये माल का क्रय करने के पश्चात्, बिना किसी उचित कारण के, माल का उस प्रयोजन के हेतु उपयोग नहीं करता है,
- (ड) धारा ८ की उपधारा ४ के प्रयोजनार्थ नियत किसी ऐसे फार्म को अपने अधिकार में रखता है जो कि उसने अथवा उसके नियोक्ता (Principal) अथवा उसके अभिकर्ता (Agent) ने इस अधिनियम के अथवा अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त नहीं किया है,
- (ण) धारा ६ अ में दिये गये प्रावधानों को भंग करते हुए कर के रूप में कोई धन राशि वसूल करता है, तो उसकी ६ महीने तक की साधारण कैद हो सकती है, अथवा उस पर अर्थ-दण्ड लग सकता है अथवा दोनों ही दण्ड मिल सकते हैं, तथा जब वह अपराध एक लगातार चलने वाला अपराध है तो उस पर दैनिक अर्थ-दण्ड लग सकता है जो कि अपराध के दिनों के लिए ५०) ६० प्रतिदिन तक हो सकता है।

### प्रभियोग चलाने के स्थान पर अर्थ-दंड लगाना (Imposition of Penalty in lieu of Prosecution)

धारा १० (अ) के अनुसार—“यदि कोई व्यक्ति धारा १० के (ब), (स) तथा (द) वाक्य के अन्तर्गत अपराध का दोषी है तो वह प्राधिकारी जिसने इस अधिनियम के अन्तर्गत उसकी पंजीयन सर्टीफिकेट प्रदान किया है अथवा जो ऐसा सर्टीफिकेट प्रदान करने के योग्य है, उस (व्यक्ति) को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर तथा लिखित आदेश देकर उस पर अर्थ-दंड लगा सकता है जो कि उस कर की द्वायदी धनराशि से अधिक नहीं होगा जो कर माल की बिक्री के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अन्तर्गत लगता यदि उसने कोई अपराध नहीं किया होता।”

### हस्तक्षेप अपराध (Cognizance of Offences)

धारा ११ के अनुसार—(घ) कोई भी न्यायालय किसी ऐसे अपराध के विषय में हस्तक्षेप नहीं करेगा जो कि इस अधिनियम अथवा अधिनियम के अन्तर्गत बने हुए नियमों के अनुसार दंडनीय हो

जब तक कि उस न्यायालय ने उस सरकार से पूर्व आज्ञा प्राप्त न करली हो जिसके क्षेत्र में यह अपराध किया गया है, अथवा जब तक उस न्यायालय ने उस सरकार के ऐसे अधिकारी से पूर्व आज्ञा प्राप्त न करली हो जो कि सरकार ने इस सम्बन्ध में सामान्य व विशिष्ट आदेश द्वारा नियत किया हो, तथा एक प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट व एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे का न्यायालय इन अपराधों पर कार्यवाही नहीं करेगा।

(ब) इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय सभी अपराध हस्तक्षेप्य (cognizable) तथा प्रतिभूति योग्य (bailable) होंगे।

इस धारा की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं —

- (i) एक न्यायालय उन अपराधों के सम्बन्ध में जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत अथवा इसके नियमों के अन्तर्गत दण्डनीय हैं, उस दशा में ध्यान दे सकता है जबकि न्यायालय ने सरकार से ऐसा करने की पूर्व अनुमति ले ली हो। अनुमति प्रदान करने वाली वही सरकार होती है जिसके क्षेत्र के अन्दर वह अपराध किया गया हो। अनुमति प्रदान करने का कार्य एक सरकार द्वारा किसी प्राधिकारी को सौंपा जा सकता है।
- (ii) यदि न्यायालय को उस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति मिल जाती है तो केवल वही न्यायालय इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप कर सकता है अथवा कार्यवाही कर सकता है जोकि प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट व प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे का न हो।
- (iii) जो अपराध इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है, वे सभी हस्तक्षेप्य तथा प्रतिभूति योग्य हैं। हस्तक्षेप्य अपराध वह होता है जिसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति पर अपराध का सदेह होने पर बिना किसी वारंट के उसकी गिरफ्तारी की जा सके। ऐसे अपराधों की जांच-पड़ताल करने का अधिकार सामान्यतया अधिकृत प्राधिकारी को होता है जो कि मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना ही उन अपराधों में जांच पड़ताल कर सकता है।

हस्तक्षेप्य अपराध के सम्बन्ध में जैसे ही किसी अधिकृत प्राधिकारी को कोई सूचना मिलती है अथवा वह स्वयं किसी ऐसे अपराध के किये जाने का सदेह करता है तो वह उस अपराध के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट उच्च प्राधिकारियों को भेज देता है तथा वह स्वयम् उस मामले में वही छानबीन करना प्रारम्भ कर देता है। ऐसे अपराध की छान-बीन करने के लिये उस अधिकारी को भवन में प्रवेश करने की तथा किसी सामान को अपने अधिकार में लेने की अनुमति रहती है।

केन्द्रीय बिक्री-कर (राजस्थान) नियम १९५७ को नियम सख्या ११ कर-निर्धारक-प्राधिकारियों को अधिकार देती है, जिसके अनुसार वे भवन में प्रवेश कर सकते हैं, व हिसाब-किताब की बहियों का निरीक्षण कर सकते हैं तथा उनको अपने अधिकार में ले सकते हैं। नियम सख्या १२ के अनुसार उनको पंजीयन सर्टीफिकेट का निरीक्षण करने के लिये भवन में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त है।

प्रतिभूति योग्य अपराध वे होते हैं जहाँ दोषी व्यक्ति को व्यक्तिगत अथवा रूपों की प्रतिभूति देने पर छोड़ा जा सकता है। अतः इस अधिनियम के अन्तर्गत दोषी कर दाताओं व व्यापारियों को प्रतिभूति प्रदान करने पर छोड़ा जा सकता है।

### हानि-रक्षा (Indemnity)

नियम १२ के अनुसार—“सरकार के किसी भी ऐसे अधिकारी के विरुद्ध न तो कोई अभियोग ही चलाया जा सकता है और न कोई अन्य कानूनी न्यायवाही ही की जा सकती है जिसने इस अधिनियम के अन्तर्गत अथवा उसके नियमों के अन्तर्गत सद्बिश्वास के साथ कोई न्याय किया हो अथवा वह करना चाहता हो।”

# नियम (Rule)

धारा १३ (१) के अनुसार—केन्द्रीय सरकार, सरकारों गण्ट में निम्नलिखित बातों से सम्बन्धित नियम बना सकती है —

- (a) पञ्जीयन (Registration) से सम्बन्धित नियम—प्राप्तता-पत्र देने की विधि, प्रार्थना-पत्र में दिए जाने वाला विवरण, पञ्जीयन को स्वीकार करने का विधि, अवस्थाएँ निम्न पञ्जीयन अन्वीकृत किया जा सकता है, तथा फार्म जिसमें सर्टीफिकेट प्रदान किया जाएगा ।
- (b) विक्रय राशि (Turnover) से सम्बन्धित नियम—विक्रय राशि की अवधि, अधिनियम के अन्तर्गत किसी माल की बिक्री के सम्बन्ध में विक्रय राशि निर्णय करने का दाय, तथा कटौतियाँ जो कि विक्रय राशि के निर्णय करने में का जा सकती हैं ।
- (c) पञ्जीयन को निरस्त करने (cancellation) में सम्बन्धित अवस्थाएँ व गनों जिनके अन्तर्गत पञ्जीयन निरस्त किया जा सकेगा ।
- (d) माल का क्रय करने वाले ध्यापारी द्वारा घोषणा-पत्र में दिया गया विवरण तथा उन घोषणा-पत्र का फार्म ।
- (dd) इस अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाने वाले सर्टीफिकेट व घोषणा-पत्रों के विवरण तथा उनके फार्म ।
- (e) निम्नलिखित कार्यों में प्रयोग होने वाले माल अथवा माल की थैली के सूचियन सम्बन्धी नियम —  
बिक्री के हेतु माल का निर्माण व विधिवत् करना, स्वाम्य खोदने का कार्य, तथा विद्युत या किसी अन्य शक्ति का उपयोग करना व वितरण करना ।
- (f) धारा ६ की उपधारा ३ व परन्तुक (Proviso) से सम्बन्धित बातें जिनके लिए प्रावधान किया जाय ।
- (g) इस अधिनियम के अन्तर्गत दिए जाने वाले प्रार्थना-पत्रों पर मुहर ।

धारा १३ (२) के अनुसार—उपधारा (१) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार जो नियम बनायेगी, नियम सोन सड़क की दोहा मनामा के सामन रहे जायेंगे तथा व नियम एम परिवर्तन के अधीन होंगे जो कि सनद उक्त अधिनियम में अथवा उत्तराधिकार के अधिनियम में करें ।

धारा १३ (३) के अनुसार—राज्य सरकारें इन अधिनियम के प्रयोग का पूरा करते के लिए नियम बना सकती हैं परन्तु व नियम एम होने चाहिये जो कि उपधारा (१) के अन्तर्गत बताये गए नियमों के, तथा इस अधिनियम व प्रावधानों के विपरित न पड़ें ह ।

**धारा १३ (४) के अनुसार—**उपधारा (३) में दिये गये अधिवारों के अनुसार राज्य सरकारें निम्नलिखित सभी अथवा कुछ बातों के सम्बन्ध में नियम बना सकती हैं —

- (a) पंजीयत व्यापारियों की सूची का प्रकाशन, इन सूचियों में समय-समय पर हुए संशोधन, तथा ऐसी सूचियों में दिये जाने वाला विवरण ।
- (b) अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत होने वाली विज्ञापित खातों (Accounts) के रखने के तरीके व फार्म ।
- (c) व्यापारी द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में सूचनाएँ प्रदान करना—भाल का स्टॉक, माल का खरीद, बिक्री तथा सुपुर्दगी, तथा उसके व्यवसाय से सम्बन्धित कोई अन्य बात जिसकी सूचना देना इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो ।
- (d) इस अधिनियम के अन्तर्गत रखे जाने वाला हिसाब की पुस्तकें, खाते तथा विपत्रा का निरीक्षण, ऐसी हिसाब की पुस्तकों, खातों तथा विपत्रों का तपास करने के लिये सभी उचित समय में उस भवन में प्रवेश करना जहाँ कि वे रखे हुए ह अथवा जहाँ कि उनके रखे जाने का संदेह है, तथा ऐसी पुस्तकों, खातों तथा विपत्रों की अपने अधिकार में ले लेना ।
- (e) प्राधिकारी जिनसे धारा ८ (४) के अन्तर्गत लिखे गये फार्म प्राप्त किये जा सकते हैं उन फार्मों में प्राप्त करने की शर्तें तथा उनकी फीस, उन फार्मों का लेखा रखने तथा उनको सरक्षण में रखने का तरीका, तथा ऐसे फार्मों को प्रयोग करने व घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने के तरीके ।
- (f) एक अभिभाजित हिन्दू परिवार, संस्था, क्लब, सोसायटी, फर्म या कम्पनी के मामले में अथवा ऐसे व्यक्ति के मामले में जो कि किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से एक अभिभावक प्रत्यासी आदि की तरह व्यवसाय चलाता हो, एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना जिसमें उस व्यक्ति का नाम लिखा जाय जो कि राज्य में उस व्यापारी के व्यवसाय का प्रबन्धक समझा जायेगा, तथा ऐसा फार्म नियत करना जिसमें ऐसी घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिये ।
- (g) एक व्यापारी के द्वारा चलाये गये व्यवसाय के स्वामित्व में अथवा उसके व्यवसाय के नाम, स्थान व स्वभाव में परिवर्तन की सूचना देने से सम्बन्धित समय व ढंग जिसमें यह सूचना दी जाय तथा वे प्राधिकारी जिनको यह सूचना दी जाय ।

**धारा १३ (५) के अनुसार—**धारा १३ के अन्तर्गत कोई नियम बनाने में राज्य सरकार यह निर्देश कर सकती है कि किसी नियम को भंग करने से व्यापारी अर्ध-दंड का भागी होगा जो कि ५००) तक हो सकता है और यदि वह अपराध लगातार चलता रहे, तो ५०) तक प्रतिदिन के लिए जब तक कि वह अपराध चलता रहे, अर्ध-दंड का भागी हो सकता है ।

**केन्द्रीय बिक्री-कर (पंजीयन एवं विक्रय राशि) नियम १९५७ [Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules 1957]**

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १९५६, की धारा १३ (१) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित नियम बनाये हैं —

१. ये नियम केन्द्रीय बिक्री-कर (पंजीयन एवं विक्रय राशि) नियम १९५७ कहलायेंगे ।

२. इन नियमों में — (ए) 'अधिनियम' (Act) का अर्थ केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम १९५६ से है,

- (ए) 'प्राधिकृत अधिकारी' (Authorised officer) का अर्थ उस अधिकारी से है जो कि धारा ८ (४) के 'बी' वाक्य के अन्तर्गत प्राधिकृत किया गया है,
- (बी) 'विपत्र' (form) का अर्थ उस विपत्र से है जो कि इन नियमों से साथ लगे हुए है,
- (सी) 'विज्ञप्त प्राधिकारी' (Notified authority) का अर्थ उस प्राधिकारी से है जो कि धारा ७ (१) में वर्णित है।
- (सीसी) 'नियत प्राधिकारी' (Prescribed Authority) का अर्थ उस प्राधिकारी से है जो कि धारा ८ (३) के अन्तर्गत प्राधिकृत किया हुआ है अथवा धारा १३ (४) के (ई) वाक्य के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियत किया गया है।
- (डी) 'धारा' (Section) का अर्थ अधिनियम की धारा से है।
- (डी डी) 'हस्तांतरणकर्ता' (Transferor) का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो कि धारा ८ के (बी) वाक्य के अनुसार बिक्री करता हो।
- (ई) 'संग्रहागार' (Warehouse) का अर्थ ऐसे गृहाते, भवन व जहाज से है जिसमें व्यापारी बिक्री के हेतु माल का स्टॉक रखता हो।

### पंजीयन का प्रमाण-पत्र (Certificate of Registration)

३ (१) धारा ७ के अनुसार पंजीयन का प्रार्थना पत्र व्यापारी के द्वारा 'ए' फार्म (A form) में, भरकर विज्ञप्त अधिकारी को दिया जायेगा, तथा

(ए) निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा, हस्ताक्षरित होगा —

व्यवसायी के स्वामी के द्वारा, फार्म के मामले में—किसी एक सामेदार द्वारा हिन्दू अविभाजित परिवार के मामले में—परिवार के प्रबन्धक व कर्त्ता द्वारा, एक कम्पनी के मामले में जो कि कम्पनी अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत समामेलित है—एक संचालक, प्रबन्ध अधिकर्ता या उसका कोई प्रधान अधिकारी, सरकार के मामले में—सरकार द्वारा प्राधिकृत एक पदाधिकारी, सस्था के मामले में—व्यवसाय का प्रबन्ध करने वाला एक प्रधान अधिकारी, तथा

(बी) वह प्रार्थना पत्र उक्त 'ए' फार्म में लिखे हुए ढंग से सत्यापित (Verified) किया जायेगा।

(२) यदि एक व्यापारी एक राज्य में व्यवसाय के एक से अधिक स्थान रखता है तो वह सब स्थानों के सम्बन्ध में एक ही प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें इन नियमों के प्रयोजनार्थ वह व्यवसाय का प्रमुख स्थान भी लिखेगा तथा व्यापारी यह प्रार्थना पत्र अपने व्यवसाय के प्रमुख स्थान से सम्बन्धित विज्ञप्त प्राधिकारी को ही प्रस्तुत करेगा।

यह व्यवसाय का प्रमुख स्थान यही होगा जो कि उसने राज्य के सामान्य बिक्री-कर कानून के अन्तर्गत घोषित किया है।

४. (१) धारा ७ (१) के अन्तर्गत पंजीयन के हेतु प्रार्थना-पत्र उस तिथि से ३० दिन के अन्दर ही प्रस्तुत किया जायेगा जिस तिथि को वह व्यापारी अधिनियम के अन्तर्गत नर देने के लिये दायी हुआ था।

(२) धारा ७ (२) के अन्तर्गत पंजीयन के हेतु प्रार्थना पत्र अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय दिया जा सकता है।

(३) अधिनियम (१) तथा (२) के अन्तर्गत पंजीयन कराने के लिये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर ५) ७० फीस लेवेगी। ऐसी फीस कोर्ट फीस की रटाम्य के रूप में प्रार्थना पत्र पर लगायी जायेगी।

५. (१) आवश्यक जाँच करने के पश्चात् जब विज्ञप्त प्राधिकारी सतुष्ट हो जाता है, प्रार्थना-पत्र में दिया हुआ विवरण सही व पूरा है तथा नियम ४ (३) में लिखी गयी चुका दी गयी है तो वह उस प्रार्थी व्यापारी का पंजीयन कर लेगा तथा उसे बी (B form) में एक सर्टीफिकेट जारी कर देगा। वह प्राधिकारी व्यवसाय के प्रमुख के अतिरिक्त राज्य के अन्य प्रत्येक व्यवसाय-स्थान के लिये भी ऐसे सर्टीफिकेट की प्रति देगा।

(२) यदि विज्ञप्त अधिकारी प्रार्थना-पत्र के विवरण की सत्यता व पूर्णता के बारे में सतुष्ट नहीं है अथवा नियम ४ (३) में वर्णित फीस नहीं चुकाई गयी है तो वह लिखित कारण देकर प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर देगा परन्तु इससे पूर्व कि प्रार्थना-पत्र वापस कर दिया जाता है प्रार्थी को इस मामले में सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाये और उसे इस बात का भी अवसर दिया जायेगा कि वह उक्त विवरणों को ठीक व सही कर सके तथा नियम ४ (३) की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

६ पंजीयन का सर्टीफिकेट जो कि नियम ५ (१) के अन्तर्गत प्रदान किया गया है, के उस प्रमुख स्थान पर रखा जायेगा जो कि सर्टीफिकेट में लिखा हुआ है तथा सर्टीफिकेट की एक प्रति राज्य के अन्दर प्रत्येक अन्य व्यवसाय स्थान पर भी रखा जायेगी।

७. (१) यदि एक व्यापारी यह चाहता है कि उसको प्रदान किये गये सर्टीफिकेट में कुछ संशोधन कर दिये जायें तो वह इस उद्देश्य के लिये विज्ञप्त प्राधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देगा जिसमें वह इच्छित संशोधन लिखेगा तथा ऐसा संशोधन कराने के कारण लिखेगा। वह इस प्रार्थना-पत्र के साथ अपना सर्टीफिकेट तथा उसकी प्रतियाँ जो कि उसको प्रदान की गयी थी, नत्थी करेगा। यह अधिकारी, कारणों से सतुष्ट होने पर सर्टीफिकेट तथा उसकी प्रतियों में ऐसे संशोधन कर देगा जो कि वह आवश्यक समझे।

(२) नियम ६ के प्रावधान इस संशोधित सर्टीफिकेट व प्रतियों को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे मूल सर्टीफिकेट व मूल प्रतियों को लागू होते थे।

८. (१) यदि पंजीयन सर्टीफिकेट जो कि व्यापारी को प्रदान किया गया था, खो जाता है नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है अथवा उसके अक्षर मिट जाते हैं, तो वह व्यापारी विज्ञप्त प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर तथा २) ६० की फीस देकर ऐसे सर्टीफिकेट का 'अनुलिपि' (Duplicate) प्राप्त कर सकता है।

(२) उपनियम (१) में जो फीस दी जायेगी वह कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में होगी।

### पंजीयन का निरस्तन (Cancellation of Registration)

९ (१) धारा ७ (४) के अन्तर्गत एक व्यापारी के पंजीयन सर्टीफिकेट को निरस्त करने व संशोधित करने से पूर्व विज्ञप्त-प्राधिकारी व्यापारी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगा।

(२) यदि पंजीयन सर्टीफिकेट में कुछ संशोधन किया जाना है तो व्यापारी विज्ञप्त प्राधिकारी को सर्टीफिकेट तथा उसकी प्रतियाँ जो कि उसको प्रदान की गयी थीं संशोधन के लिये प्रस्तुत करेगा।

(३) यदि पंजीयन निरस्त कर दिया जाता है तो व्यापारी विज्ञप्त प्राधिकारी को पंजीयन सर्टीफिकेट व उसकी प्रतियाँ, यदि उसको प्रदान की गयी हो, समर्पित कर देगा।

१० यदि कोई व्यापारी धारा ७ (५) के अन्तर्गत अपने पंजीयन को निरस्त कराना चाहता है तो वह उस धारा में दिये गये नियत समय के अन्दर विज्ञप्त प्राधिकारी को इस कार्य के लिये एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा। प्रार्थना-पत्र के साथ सर्टीफिकेट व उसकी प्रतियाँ यदि कोई प्रदान की गयी हो, प्रस्तुत की जावेगी तथा ऐसे प्रार्थना-पत्र पर उस धारा के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जायेगा।

### विक्रय राशि का निर्णय (Determination of Turnover)

११. (१) इस अधिनियम के अन्तर्गत कर देने वाले व्यापारी के सम्बन्ध में विक्रय राशि की भवधि वही होगी जिसके लिये उपयुक्त राज्य के सामान्य विक्री-कर कानून के अन्तर्गत वह विवरण पत्र प्रस्तुत करने के लिये दायी है।

परन्तु एक ऐसे व्यापारी के सम्बन्ध में जो कि उपयुक्त राज्य के विक्री-कर कानून के अन्तर्गत विवरण-पत्र प्रस्तुत करने का दायी नहीं है, विक्रय राशि की भवधि तिमाही होगी जो कि वित्तीय वर्ष में ३० जून, ३० सितम्बर, ३१ दिसम्बर तथा ३१ मार्च को समाप्त होगी।

(२) धारा ८ के प्रयोजनार्थ एक व्यापारी की विक्रय राशि निर्णय करने में विक्री-मूल्यों के योग (Aggregate of sale-prices) में निम्नलिखित घन राशि घटायी जायेगी:—

(अ) निम्नलिखित सूत्र के हिसाब से जो घन राशि निकलती हो

$$\frac{\text{कर की दर} \times \text{विक्रय मूल्यों का योग}}{100 + \text{कर की दर}}$$

$$\frac{\text{Rate of tax} \times \text{Aggregate of sale prices}}{100 + \text{rate of tax}}$$

परन्तु उपरोक्त सूत्र के आधार पर कोई कटौती (Deductions) नहीं की जायेगी अगर विक्रय मूल्यों के योग में से वह कर राशि घटा दी गयी है जो कि पंजीयत व्यापारी ने धारा १ ए के प्रावधानों के अनुसार घसूल की थी।

**स्पष्टीकरण—(अ)** जहाँ एक व्यापारी की विक्रय राशि पर विभिन्न दरों से कर लगता है तो यह सूत्र विभिन्न दरों की विभिन्न विक्रय-राशियों के लिये अलग-अलग लागू किया जायेगा।

(ब) व्यापारी को क्लेताओं द्वारा वापिस किये माल का विक्रय मूल्य यदि वह माल गुप्तदुर्गो की तिथि से ३ माह के अन्दर ही वापिस किया गया हो।

वर्तते माल को वापिस करने का उपाय माल की घन राशि को नकद लौटाने अथवा हिसाब में समावेश करने का प्रमाण नियत प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया हो।

**उदाहरण १**—मान लीजिये एक व्यापारी १०० रु० की वस्तुएँ बेचता है और वह २% विक्री-कर लगाता है। विक्रय राशि का विवरण-पत्र भेजते समय वह विक्रय मूल्य का योग १०२ रु० दिखाता है, तो यहाँ धारा ८ के लिये विक्रय राशि (Turnover) ज्ञात करनी है:—



$$\text{विक्रय राशि} = \text{विक्रय मूल्य का योग} - \frac{\text{कर की दर} \times \text{विक्रय मूल्य का योग}}{100 + \text{कर की दर}}$$

$$= 102 - \frac{2 \times 102}{100 + 2}$$

$$= 100 \text{ रु०}$$

परन्तु यदि व्यापारी ने विवरण-पत्र में शुद्ध विक्रय राशि ही लिख दी है अर्थात् बजाय १०२) रु० के १००) रु० ही लिखे हैं तो वहाँ यह सूत्र लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

**उदाहरण २**—एक व्यापारी के विक्रय मूल्यों की धन राशि ४०८) रु० है जिसमें २% बिक्री कर सम्मिलित है। एक ग्राहक १००) रु० की एक वस्तु को ३ माह के भन्दर वापिस कर देता है तो धारा ८ के लिये विक्रय राशि ज्ञात करनी है :—

विक्रय राशि = विक्रय मूल्य का योग — (सूत्र के हिसाब से ज्ञात धन राशि + वापिस किये गये माल का विक्रय मूल्य)

$$= 408 - \left( \frac{2 \times 408}{100 + 2} + 100 \text{ रु०} \right)$$

$$= 300 \text{ रु०}$$

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि वापिस किये गये माल के १००) रु० ही घटाये जायेंगे न कि १०२) रु० (१०० + २% बिक्री कर)। व्यापारी ने ग्राहक को १०२) रु० ही लौटाये होंगे, इस प्रकार उसके पास ४०८ — १०२ = ३०६ रु० ही हैं जिनमें ६) बिक्री-कर है तथा ३००) विक्रय मूल्य। यहाँ कर निर्धारक प्राधिकारी भी धारा ८ के हेतु ३००) रु० पर २% बिक्री कर की ही गणना करेगा।

१२ (१) धारा ८ की उपधारा ४ में घोषणा-पत्र तथा सार्टीफिकेट कहे गये हैं, वे क्रमशः 'सी' फार्म तथा 'डी' फार्म में हैं।

फार्म 'सी' में दो गई घोषणा जो कि १ अक्टूबर १९५८ के तत्काल पूर्व लागू थी, ३० सितम्बर १९६२ तक आवश्यक सशोधनों के साथ प्रयोग की जा सकती है।

धारा ६ की उपधारा (२) में जो सार्टीफिकेट कहे गए हैं, वे अवस्थानुसार ई प्रपम (E I) या ई द्वितीय (E II) फार्म हैं।

**कतिपय प्रयोजनों के हेतु माल का निर्दिष्ट करना (Prescription of Goods for Certain Purposes)**

१३. धारा ८ की उपधारा ३ के (ब) वाक्य में जो माल कहे गए हैं जिनको एक पंजीयत व्यापारी बिक्री हेतु माल का निर्माण व विधिवत् करने में, खान खोदने में, तथा विद्युत या अन्य शक्ति के उत्पादन व वितरण करने के कार्यों में उपयोग कर सकता है, निम्नलिखित प्रकार के होंगे जैसे कि :—

कच्चा माल, मशीनरी, प्लाट, उपस्कार (equipments) औजार, स्टोर्स, मशीन के अतिरिक्त पुर्जें (spare parts), उपसाधन (accessories), ई घन तथा स्नेहक द्रव्य (lubricants)।

## केन्द्रीय बिक्री-कर (राजस्थान) नियम १९५७

धारा १३ की उपधारा ३ व ४ के अन्तर्गत राज्य की सरकारो को केन्द्रीय बिक्री-कर से सम्बन्धित नियम बनाने के अधिकार मिले हुए हैं। इन अधिकारो के फलस्वरूप राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाये हैं। उन्हें केन्द्रीय बिक्री-कर (राजस्थान) नियम १९५७ कहते हैं। ये नियम राजस्थान राज-पत्र में ४ मार्च १९५७ को प्रकाशित हुए तथा इसी तिथि से लागू हुए माने गये।

इन नियमो से सम्बन्धित प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :—

### पंजीयन-सर्टीफिकेट (Registration Certificate)

नियम ३—पंजीयन सर्टीफिकेट के धारक के लिये यह आवश्यक है कि वह इस सर्टीफिकेट को अपने उस व्यवसाय के भवन में एक प्रमुख स्थान पर लटका कर रखे जिस व्यवसाय के सम्बन्ध में वह सर्टीफिकेट उसको निर्गमित किया गया है।

पंजीयन की विधि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमो में दी हुई है।

### विक्रय-राशि का विवरण पत्र तथा अन्य विवरण पत्र व लेखे (Return of Turnover and other Returns and Statements)

नियम ४ विक्रय-राशि का विवरण पत्र—प्रत्येक व्यापारी जो केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत कर देने का दायी है, सी० एस० टी० १ (C S. T I) कार्य में अपनी विक्रय राशि का विवरण कर-निर्धारक-प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यह विवरण उसके द्वारा अथवा उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित व प्रमाणित होना चाहिये।

यह विवरण पत्र व्यापारी के द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा डाक द्वारा भेजा जा सकता है।

यह विवरण-पत्र प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के प्रति तिमाही समय के लिये जोकि जून, सितम्बर, दिसम्बर व मार्च की अन्तिम तिथि को समाप्त होता हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिये। ये तिथियाँ उस व्यापारी के लिये हैं जिसका लेखा वर्ष (Accounting year) ३१ मार्च को समाप्त होता हो, अन्य अवस्थाओं में तिमाही की तिथियाँ उनके लेखा वर्ष के अनुसार होती हैं। यह विवरण पत्र तिमाही की तिथि समाप्त होने के पश्चात्, अगले वाले ३० दिनों के अन्दर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

जहाँ किसी तिमाही काल में व्यवसाय बन्द व हस्तांतरित कर दिया जाता है तो ऐसी बन्द व हस्तांतरित होने की तिथि के अगले ३० दिनों के अन्दर ही विवरण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये जो कि इस तिमाही के आरम्भ की तिथि से व्यवसाय के बन्द व हस्तांतरित होने की तिथि तक का होना चाहिये।

व्यापारी के लिए यह आवश्यक है कि वह विवरण पत्र के साथ 'कर के जमा करने की रसीद' भी नयी करे। जब तक यह रसीद नयी नहीं की जायेगी, यह समझा जायगा कि विवरण-पत्र प्रस्तुत ही नहीं किया गया। यदि कर जमा नहीं किया गया है तो कर अधिकारी व्यापारी को एक सप्ताह के अन्दर कर के जमा कराने का तथा उसको रसीद भेजने का आदेश देगा।

नियम ६—एक व्यापारी को अपने विक्रय राशि के विवरण-पत्र में अपने व्यवसाय की सभी ब्राचों की विक्रय राशि का विवरण सम्मिलित करना चाहिये। यह अपने व्यवसाय के प्रमुख स्थान का विवरण पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें सभी ब्राचों की विक्रय राशि दी जायेगी। यह व्यापारी इस बात की सूचना कि सभी ब्राचों की विक्रय राशि विवरण-पत्र में सम्मिलित करली गयी है, प्रत्येक ऐसे कर निर्धारक-प्राधिकारी को देगा जिसका सम्बन्ध उसकी ब्राचों से पड़ता हो।

**नियम ६ ए—**यदि व्यापारी प्रस्तुत किये गये विवरण-पत्र में कोई गलती महसूस करता है तो वह दूसरा पत्र प्रस्तुत कर सकता है परन्तु ऐसा दूसरा विवरण-पत्र, अगली तिमाही के विवरण-पत्र के प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये, बाद में नहीं।

**नियम ६ बी—**केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत जो रुपया सरकारी कोषालयों (Treasuries) में जमा कराना होगा, वह सी. एस. टी. ५ (C. S. T. 5) फार्म के चालान द्वारा ही जमा किया जा सकेगा। यह फार्म सरकारी कोषालय से तथा बिक्री-कर-अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

**व्यापारियों द्वारा हिसाब के खातों का रखा जाना (Accounts to be Maintained by Dealers)**

**नियम ७ :** हिसाब कैसे रखा जाय—प्रत्येक कर देने वाला व्यापारी सी. एस. टी. ६ (C.S.T.6) फार्म में अपने क्रय, विक्रय तथा स्टॉक का ठीक हिसाब रखेगा।

प्रत्येक कर दायी निर्माणाकर्ता (Manufacturer) कच्चे व पक्के माल के सम्बन्ध में एक स्टॉक-बही रखेगा।

**नियम ८ :** बिभिन्न दरों पर कर लगाने वाले माल का अलग-अलग हिसाब—निम्नलिखित माल के सम्बन्ध में प्रत्येक करदायी व्यापारी अलग-अलग हिसाब रखेगा—

(अ) वह माल जिस पर धारा ८ (१) के अनुसार २% की दर से कर लगता हो, तथा

(ब) वह माल जिस पर धारा ८ (२) के अनुसार अन्य दरों पर कर लगता हो।

**नियम ९ :** क्रेताओं से कर वसूल करना—एक कर-देय व्यापारी द्वारा जो कि क्रेताओं से बिक्री मूल्य के अतिरिक्त बिक्री कर वसूल करता हो, कैशमीरो या क्रेडिट मीमो निर्गमित किया जाना चाहिये जिसमें बिक्री-मूल्य तथा बिक्री-कर अलग-अलग दिखाये गये हों। उसे इन मीमो की नकल भी अपने पास भ्रवश्य रखनी चाहिये। ऐसे व्यापारी द्वारा एक अलग हिसाब भी रखा जाना चाहिये जिसमें वह दिन प्रति दिन की कर-वसूली दिखाये तथा साथ में कैश मीमो व क्रेडिट मीमो का नम्बर व तिथि भी लिखे। जो कैश मीमो या क्रेडिट मीमो निर्गमित किया जाय, वह एक जिल्द बंधी पुस्तक से होना चाहिये जिसमें उसकी नकल व मूल प्रति के पृष्ठों पर क्रम से सफा पड़ी हो।

**नियम १० :** हिसाब किताब-को सुरक्षित रखना—जिस लेखा वर्ष (Accounting Year) से हिसाब-किताब सम्बन्धित है, उस वर्ष से अगले पांच वर्षों तक यह हिसाब-किताब करदेय व्यापारी द्वारा सुरक्षित रखा जाना चाहिये। हिसाब-किताब में वे सभी कैश मीमो, क्रेडिट मीमो तथा वाउचर सम्मिलित हैं जो कि माल के उत्पादन, स्टॉक, क्रय, विक्रय तथा सुपूर्दगी से सम्बन्ध रखते हैं।

**अधिकारियों की शक्तियाँ (Powers of Officers)**

**नियम ११ :** हिसाब की बहियों व विपत्रों का निरीक्षण करने, उन पर कब्जा करने तथा भवन में प्रवेश करने की शक्ति—कर-निर्धारक प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत बिक्री कर विभाग का कोई भी निरीक्षक निम्नलिखित का निरीक्षण कर सकता है—

व्यापारी के व्यवसाय से सम्बन्धित सभी खाते, रजिस्टर तथा अन्य विपत्र, उसके अधिकार में उपस्थित माल तथा उसका कार्यालय, गोदाम, कारखाना, जहाज व गाड़ी अथवा कोई भी स्थान जहाँ उसका व्यवसाय चलता हो।

कोई कर निर्धारक अधिकारी अथवा कोई ऐसा निरीक्षक उपरोक्त बातों के लिये किसी ऐसे कारखाने, गोदाम, कार्यालय, दुकान अथवा किसी ऐसे अन्य स्थान में प्रवेश पाने की शक्ति रखता है जहाँ वह हिसाब की बहियाँ व विपत्र रखे हो। वह हिसाब की बहियों व विपत्रों को अपने अधिकार में ले सकता है। यदि वह उनको अधिकारी में लेता है तो वह उन पुस्तकों व विपत्रों की सूची बनाकर व्यापारी को देगा जो कि उसने अपने अधिकार में ली है।

कोई भी अधिकारी किसी व्यापारी को पुस्तको व उसके विपणो को अपने अधिकार में उस समय तक नहीं ले सकता जब तक कि उसने बिक्री कर कमिश्नर से अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी से ऐसा करने की लिखित आज्ञा न प्राप्त करली हो ।

**नियम १२ पंजीयत सर्टीफिकेट को देखने की शक्ति**—यदि कोई भी कर-निर्धारक-अधिकारी अथवा बिक्री-कर विभाग का निरोधक सभी उचित समय में धारक से पंजीयत सर्टीफिकेट दिखाने की मांग करता है तो धारक को वह सर्टीफिकेट दिखलाना पड़ेगा और यह सर्टीफिकेट देखने के लिये उस अधिकारी को व्यापारी के कारखाने, गोदाम, कार्यालय, दुकान तथा ऐसे अन्य स्थान में प्रवेश पाने का अधिकार होगा जहाँ कि वह सर्टीफिकेट सामान्यतया रखा जाता है अथवा रखा जाना चाहिये । निरोधक का प्रवेश पाने का अधिकार उसी अवस्था में होता है जबकि लिखित वारणों पर किसी विशेष मामले में कर-निर्धारक-अधिकारी ने उसे ऐसा करने का अधिकार दे दिया हो ।

**व्यवसाय के परिवर्तन से सम्बन्धित सूचना प्रदान करना (Information to be Furnished regarding Change of Business)**

**नियम १३ व्यवसाय के परिवर्तन से सम्बन्धित सूचना प्रदान करना**—यदि कोई कर देय व्यापारी—

- (अ) अपने व्यवसाय को अथवा व्यवसाय के किसी भाग को अथवा अपने व्यवसाय के स्थान को बेच देता है या समाप्त कर देता है, अथवा उसे व्यवसाय के स्वामित्व में परिवर्तन का ज्ञान हो जाता है, अथवा
- (ब) अपने व्यवसाय को बन्द कर देता है या अपने व्यवसाय का स्थान बदल देता है अथवा व्यवसाय का एक नया स्थान खोलता है, अथवा
- (स) अपने व्यवसाय का नाम व स्वभाव बदल देता है अथवा जिस प्रकार के माल में वह व्यापार करता है, उस प्रकार के माल में परिवर्तन कर देता है, तो

वह ऐसे परिवर्तन के २५ दिनों के अन्दर उस कर-निर्धारक अधिकारी को सूचना देगा जिसके क्षेत्र में व्यवसाय का वह स्थान स्थित है, और अगर कोई ऐसे व्यापारी को मृत्यु हो जाती है तो उसका वैधानिक प्रतिनिधि उस अधिकारी को सूचना देगा ।

**पंजीयत व्यापारियों की सूची का प्रकाशन (Publication of List of Registered Dealers)**

**नियम १४ पंजीयत व्यापारियों की सूची**—राज्य के बिक्री कर कानून के अन्तर्गत जो ऐसी सूची रखी जाती है, उस सूची के अतिरिक्त केन्द्रीय अधिनियम की धारा ७ (१) के अन्तर्गत एक अन्य सूची रखी जायेगी, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत करने वाला अधिकारी रखेगा ।

उक्त सूची वर्णमाला क्रम में रखी जायेगी तथा उसमें जो भी संशोधन होंगे, तुरन्त ही लिख दिये जायेंगे ।

ऐसी सूची में दिये जाने वाले विवरण वही होंगे जो कि राज्य बिक्री-कर कानून के प्रयोजनार्थ सामान्य विषय-तालिका रजिस्टर (General Index Register) में दिये गये होने हैं ।

**नियम १५ सूची का प्रकाशन**—पंजीयन करने वाला अधिकारी, प्रति ६ माह के परचाव, अपने क्षेत्र के पंजीयत व्यापारियों की सूची राजस्थान गजट में प्रकाशित करेगा तथा जहाँ ऐसा प्रकाशन व्यवहार्य नहीं है यहाँ वह सूची किसी ऐसे अन्य दफ से प्रकाशित की जायेगी जैसा कि बिक्री-कर-कमिश्नर, राजस्थान निर्देश दे ।

धारा ८ (४) के अन्तर्गत घोषणा-पत्र की प्रति भेजना [Sending Copy of Declaration under Section 8 (4)]

नियम १६ : धारा ८ (४) के अन्तर्गत घोषणा-पत्र की प्रति भेजना—अधिनियम की धारा ८ (४) के अन्तर्गत जिस घोषणा-पत्र के बारे में कहा गया है, वह 'सी' फार्म से सम्बन्धित है। इस नियम के अनुसार पंजीयत व्यापारी द्वारा अपनी विक्रय राशि का विवरण-पत्र भेजने के साथ-साथ क्रेताओं से प्राप्त 'सी' फार्म भी कर-निर्धारक-प्राधिकारी को भेजना चाहिये जो कि उसी अवधि से सम्बन्धित हो जिस अवधि का विवरण-पत्र भेजा गया है।

नियम १७ : घोषणा-पत्र से सम्बन्धित नियम—(१) जब एक पंजीयत व्यापारी दूसरे पंजीयत व्यापारी से कोई ऐसा माल खरीदना चाहता है जो कि उसके पंजीयन सर्टीफिकेट में वर्णित है तथा वह कर उस दर से देना चाहता है जो कि केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे माल से सम्बन्धित है (अर्थात् २%) तो वह कर-निर्धारक-प्राधिकारी में खाली घोषणा-पत्र जो कि 'केन्द्रीय विक्री-कर (पंजीयन एवं विक्रय राशि) नियम १९५७' के नियम १२ में दिया हुआ है (अर्थात् 'सी' फार्म), एक ऐसा शुल्क देने पर जो कि राज्य सरकार ने नियत किया हो, प्राप्त कर सकता है। पंजीयत विक्रेता को भेजने से पूर्व यह आवश्यक है कि यह फार्म क्रेता-व्यापारी द्वारा अथवा उसके किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा जो कि उत्तरदायी व्यक्ति हो, भरा जाना चाहिये तथा हस्ताक्षरित होना चाहिये। इसके पश्चात् क्रेता व्यापारी फार्म की पणिका (Counterfoil) को अपने पास रख लेता है तथा इसके शेष दोनों भागों को जो कि 'मूल-प्रति' (Original) तथा 'अनुलिपि' (Duplicate) कहलाते हैं, विक्रेता-व्यापारी के पास भेज देता है।

५०००) २० के मूल तक के कई सौदे एक एक घोषणा-पत्र में लिखे जाते हैं। यह धन-राशि राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई या घटाई जा सकती है बर्ना सामान्यतया प्रति सौदे के लिये एक अलग पत्र प्रयोग किया जाना चाहिये।

(२) एक पंजीयत व्यापारी जो कि दूसरे पंजीयत व्यापारी को माल देता है, क्रेता से प्राप्त 'सी' फार्म की 'मूल प्रति' को C. S. T. 1 फार्म के साथ नवीन कर-निर्धारक प्राधिकारी के पास भेजता है तथा 'अनुलिपि' को अपने पास रख लेता है। C. S. T. 1 फार्म विक्रय राशि का विवरण-पत्र है। यदि कर-निर्धारक अधिकारी चाहे तो वह 'अनुलिपि' को भी देख सकता है।

(३) एक क्रेता व्यापारी न तो कोई ऐसा घोषणा-पत्र विक्रेता को भेजेगा और न विक्रेता व्यापारी ही ऐसा कोई घोषणा-पत्र स्वीकार ही करेगा जो कि कर-निर्धारण-प्राधिकारी द्वारा व्यर्थ व प्रतिलिपि प्रेषित कर दिया गया हो।

(४) प्रत्येक पंजीयत व्यापारी ऐसे घोषणा-पत्रों की सुरक्षा के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा। यदि उन पत्रों के खो जाने से अथवा चोरी हो जाने से सरकार को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक हानि उठानी पड़ती है तो उस हानि को पूरा करने का दायित्व उसी व्यापारी पर होगा।

(५) इन घोषित पत्रों को रखने वाला प्रत्येक पंजीयत व्यापारी C. S. T. 3, फार्म के अनुसार एक रजिस्टर रखेगा जिसमें कर-निर्धारक-प्राधिकारी से प्राप्त प्रत्येक फार्म का सत्य व पूर्ण हिसाब रखा जायेगा। किसी फार्म के खो जाने व चोरी जाने पर, व्यापारी तुरन्त ही कर-निर्धारक प्राधिकारी को सूचना देगा तथा वह ऐसे कदम उठायेगा जिनका आदेश इस सम्बन्ध में कर-निर्धारक-प्राधिकारी देगा जैसे कि सार्वजनिक नोटिस देना आदि। फार्म के खो जाने, नष्ट हो जाने व चोरी चले जाने का हवाला उस रजिस्टर के 'टिप्पणी स्तंभ' (Remark column) में दिया जाना आवश्यक है।

(६) यदि किसी पंजीयत व्यापारी का पंजीयन सर्टीफिकेट निरस्त कर दिया गया हो तो वह व्यापारी उन घोषणा-पत्रों को कर-निर्धारक प्राधिकारी को वापिस कर देगा जो कि उसके द्वारा प्रयोग नहीं किये गये हैं।

(७) एक पजीयत व्यापारी इन घोषणा-पत्रों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे व्यापारी को हस्तांतरित नहीं करेगा। वह उनको केवल उपनियम १ के अनुसार ही वैधानिक ढंग से विक्रेता व्यापारी को भेज सकता है।

(८) एक घोषणा-पत्र जिसकी उपनियम ५ के अन्तर्गत किसी कर-निर्धारक-प्राधिकारी को रिपोर्ट की गई है उपनियम १ के प्रयोजनार्थ वैध नहीं समझा जायेगा।

(९) जिन घोषणा पत्रों की रिपोर्ट उपनियम ५ के अन्तर्गत कर-निर्धारक-प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त हुई है, उनकी सूची प्राधिकारियों द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगी।

(१०) राज्य सरकार एक विज्ञप्ति द्वारा घोषित कर सकती है कि एक किसी विशेष क्रम, डिजाइन व रंग के घोषणा-पत्र एक अमुक तिथि से व्यर्थ व अवैध समझे जायें। इस विज्ञप्ति की प्रतियाँ अन्य राज्यों को भी भेजी जाती हैं ताकि वे राज्य भी अपने सरकारी गजटों में यह विज्ञप्ति प्रकाशित कर दें। इसी प्रकार यदि अन्य राज्यों से ऐसी विज्ञप्ति राजस्थान राज्य को प्राप्त होती है तो वह राजस्थान गजट में प्रकाशित की जानी चाहिये।

(११) जब उपनियम १० के अनुसार कुछ घोषणा-पत्र व्यर्थ या अवैध घोषित कर दिये जाते हैं तो घोषणा-पत्रों के व्यर्थ होने की घोषित तिथि से पूर्व सभी पजीयत व्यापारी उन व्यर्थ व अवैध पत्रों को कर-निर्धारक-प्राधिकारियों को वापिस कर देंगे तथा उनके बदले में नये फार्म प्राप्त कर लेंगे।

एक व्यापारी को नये फार्म उस समय तक निर्गमित नहीं किये जायेंगे जब तक कि वह पुराने का हिसाब-किताब प्रस्तुत न करे तथा शेष फार्मों को न सौदा दे।

**नियम १७ ए खोये हुए घोषणा-पत्रों के दुुरुपयोग को रोकने की विधि (Procedure to guard against Misuse of Declaration Forms Lost)**—घोषणा-पत्रों के खोये जाने व चोरी जाने आदि के सम्बन्ध में नियम १७ के अन्तर भी कुछ प्रावधान दिये गये हैं। उन प्रावधानों के अतिरिक्त इस नियम १७ ए के अन्तर्गत ऐसे निम्नलिखित प्रावधान दिये गये हैं जो कि ऐसे घोषणा-पत्र के दुुरुपयोग को रोक सकते हैं —

(१) जो व्यापारी किसी रिक्त अथवा भरे हुए फार्म के खोये जाने, चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने की रिपोर्ट करता है उसे क्षतिपूरक-बन्ध (Indemnity Bond) के रूप में प्रतिभूति देनी होगी। जहाँ ऐसे फार्म की हानि मार्ग में ही (in transit) हुई हो जबकि क्रेता ने उसे विक्रेता को भेजा हो अथवा विक्रेता ने कर-निर्धारक-प्राधिकारी को भेजा हो तो अवस्था के अनुसार क्रेता अथवा विक्रेता ऐसी प्रतिभूति प्रदान करेगा।

(२) यदि क्रेता द्वारा यह प्रतिभूति दी जाती है तो वह उस अधिकारी को तथा वह धन राशि प्रतिभूति के रूप में देगा जिसके लिये कर निष्पत्तिक प्राधिकारी आदेश दे। यहाँ वही कर-निर्धारक-प्राधिकारी आदेश देगा जिससे कि फार्म प्राप्त किये गये थे। यह प्राधिकारी आदेश देते समय सभी अवस्थाओं की ध्यान में रखेगा तथा वह अवधि भी नियुक्त करेगा जिसमें यह प्रतिभूति जमा करनी चाहिये।

(३) यदि विक्रेता द्वारा यह प्रतिभूति दी जाती है तो यहाँ आदेश देने वाला कर-निर्धारक प्राधिकारी वह होगा जिसको कि विक्रेता द्वारा विक्रय राशि के सामयिक विवरण-पत्र प्रस्तुत किये जाते हों। यहाँ पर भी यह प्राधिकारी उस मामले की सभी बातों को ध्यान में रखकर प्रतिभूति की धनराशि व अवधि तय करेगा तथा उस अधिकारी के बारे में भी तय करेगा जिसे कि वह प्रतिभूति दी जायगी।

(४) खोये हुए, चोरी गये, अथवा नष्ट हुए प्रत्येक फार्म के लिये अलग-अलग प्रतिभूति दी जायगी।

(५) यदि फार्म की हानि विक्रेता द्वारा होती है जबकि वह फार्म में अथवा उसकी सुरक्षा में खोया गया हो, चोरी गया हो तथा नष्ट हुआ हो तो वह उस व्यापारी से इस फार्म की अनुलिपि (Duplicate form) प्राप्त करेगा जिसको कि माल बेचा गया था। यदि वह ऐसी अनुलिपि प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह उस फार्म से सम्बन्धित वह बिक्री धारा ८ (१) से बाहर की गयी समझी जायगी।

(६) एक क्रोता व्यापारी जो कि अनुलिपि फार्म निर्गमित करेगा, उस फार्म के तीनों भागों के पृष्ठों के ऊपर लाल स्पाही से निम्नलिखित वाक्य लिखेगा तथा वाक्य के मोच तिथि डालकर अपने हस्ताक्षर करेगा —

"I hereby declare that this is the duplicate of the declaration form No. .... signed on .. .. and issued to ..... who is registered dealer of .... (state) and whose registration certificate number is .... .."

"मैं घोषित करता हूँ कि यह घोषणा-पत्र सख्या ..... की अनुलिपि है जो कि ..... तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था तथा ..... को जो कि ..... (राज्य) का पंजीयत ..... है और जिसकी पंजीयन सर्टीफिकेट सख्या ..... है निर्गमित किया गया था।"

नियम १७ बी. क्रय करने वाले उन सरकारी विभागों के द्वारा 'डी' फार्म में निर्गमित करना जो कि व्यापारी की तरह पंजीयत नहीं है (Certificate in Form D to be Issued by Purchasing Government Departments not Registered as Dealers)

(१) धारा ८ की उपधारा (१) का लाभ उठाने के लिये केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार का विभाग जो कि एक व्यापारी की तरह पंजीयत नहीं है, विक्रेता व्यापारी को 'डी' फार्म में भेजेगा। यह 'डी' फार्म केन्द्रीय बिक्री-कर (पंजीयन एवं विक्रय-राशि) नियम, १९५७ के नियम १२ (१), में वर्णित किया हुआ है।

एक फार्म एक ही सौदे के लिये प्रयुक्त किया जायगा परन्तु अहाँ विभिन्न सौदे ५००० रु० तक की धन राशि के हैं, वहाँ उन सबके लिये एक ही फार्म प्रयुक्त किया जा सकेगा।

(२) यह सर्टीफिकेट उन अधिकारियों द्वारा निर्गमित किया जायगा जो कि अधिनियम धारा ८ (४) ब में बतलाये गये हैं [अर्थात् सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी (Authorised officer)]।

(३) इस सर्टीफिकेट को विक्रेता के पास भेजने से पूर्व अधिकृत अधिकारी फार्म को तपास करेगा तथा फार्म में निश्चित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(४) अधिकृत अधिकारी की ओर से कोई अन्य अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को फार्म हस्ताक्षर करने व इसे निर्गमन करने का अधिकार हा देगा।

(५) इस सर्टीफिकेट को निर्गमन करने वाला अधिकारी इसकी पर्तिका (counterfoil) को पाँच साल तक अथवा किसी अधिक समय तक जो कि बिक्री-कर कमिश्नर ने निर्धारित किया हो, अपने अधिकार में रखेगा तथा शेष दोनों 'मूल प्रति' तथा 'अनुलिपि' को विक्रेता के पास भेज देगा।

(६) विक्रेता 'मूल प्रति' को कर निर्धारक अधिकारी के पास भेज देगा। इसकी विधि वही है जो कि नियम १७ में घोषणा-पत्र के सम्बन्ध में बतलायी गयी है। कर-निर्धारक अधिकारी, यदि चाहे, तो अनुलिपि भी देख सकता है।

(७) यदि कोई सर्टीफिकेट का फार्म खो जाता है, चोरी चला जाता है अथवा नष्ट हो जाता है तो इस सम्बन्ध में वही कार्यवाही करनी होगी जो कि नियम १७ तथा १७ ए में घोषणा-पत्र के सम्बन्ध में दी हुई है।

परन्तु एक सर्टीफिकेट के खो जाने, नष्ट हो जाने व चोरी हो जाने पर कोई प्रतिभूति देने की आवश्यकता नहीं होगी।

**नियम १७ सी : धारा ६ (२) के अन्तर्गत सर्टीफिकेट प्रस्तुत करना** [*Certificates to be Furnished under Section 6 (2)*]**—**(१) यदि धारा ६ (२) (अ) के अनुसार प्रथम बिक्री की जाती है अथवा माल सम्बन्धी अधिकार विपन्नो का हस्तांतरण करके धारा ६ (२) (ब) के अन्तर्गत प्रथम बिक्री की जाती है तो धारा ६ (२) (अ) के मामले में विक्रेता व्यापारी, तथा धारा ६ (२) (ब) में हस्तांतरणकर्ता ई प्रथम (E I) फार्म उस पंजीयत व्यापारी को निर्गमित करेगा जिसको कि माल बेचा गया है। ऐसा फार्म निर्गमित करने से पूर्व वह अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति उस फार्म को पूरी तरह से भरेगा तथा फार्म में नियत स्थान पर अपने हस्ताक्षर करेगा। वह इस फार्म की पणिका (counterfoil) को अपने पास रख लेगा तथा शेष दोनो भागो 'मूल प्रति' तथा 'अनुलिपि' को उस पंजीयत क्रेता व्यापारी के पास भेज देगा जिसको कि ऐसी बिक्री की गयी है।

धारा ६ (२) के अन्तर्गत उत्तरवर्ती बिक्री पर कर की छूट प्राप्त करने के लिये, क्रेता व्यापारी, जो कि किसी दूसरे पंजीयत व्यापारी को विपन्नो के हस्तांतरण द्वारा उत्तरवर्ती बिक्री करता है, कर-निर्धारक-प्राधिकारी को निम्नलिखित फार्म प्रस्तुत करेगा—

(१) 'ई प्रथम' (E I) फार्म की 'मूलप्रति' (original) जो कि उसे विक्रेता व्यापारी से प्राप्त हुई है, तथा

(२) 'सी' फार्म की मूलप्रति जो कि उस व्यापारी से प्राप्त हुई है जिसको कि माल बेचा गया है।

(२) यदि धारा ६ (२) (घ) की एक बिक्री की शृङ्खला में कोई प्रथम व उत्तरवर्ती बिक्री माल से सम्बन्धित अधिकार-विपन्नो का हस्तांतरण करके की जाती है अथवा धारा ६ (२) (ब) की बिक्रियो की शृङ्खला में कोई द्वितीय व उत्तरवर्ती बिक्री माल से सम्बन्धित अधिकार विपन्नो का हस्तांतरण करके की जाती है तो फार्म ई द्वितीय (E II) प्रयोग किया जायेगा। हस्तांतरणकर्ता उस फार्म को भरेगा तथा फार्म में नियत स्थान पर अपने हस्ताक्षर करेगा। वह फार्म की पणिका (Counterfoil) को अपने पास रख लेगा तथा शेष दोनो भागो 'मूलप्रति' तथा 'अनुलिपि' को उस पंजीयत क्रेता व्यापारी के पास भेज देगा जिसको कि ऐसी बिक्री की गयी है।

एक फार्म एक ही सौदे के लिय प्रयुक्त किया जायेगा परन्तु जहाँ विभिन्न सौदे ५०००) ४० तक की धन राशि के हैं, वहाँ उन सब के लिये एक ही फार्म प्रयुक्त किया जा सकेगा।

**नोट—**धारा ६ (२) (अ) के अन्तर्गत जो अधिकार विपन्नो का हस्तांतरण करके बिक्री की जायेगी, वह उत्तरवर्ती ही हो सकती है क्योंकि इस धारा में मूल बिक्री विपन्नो के हस्तांतरण से नहीं होती। विपन्नो के हस्तांतरण से जो मूल बिक्री होती है वह धारा ६ (२) (ब) के अन्तर्गत होती है। अतः धारा ६ (२) (ब) में मूल बिक्री के बाद जो उत्तरवर्ती बिक्री होती है, उसमें विपन्नो का द्वितीय बार हस्तांतरण होता है जबकि धारा ६ (२) (अ) के अन्तर्गत ऐसी उत्तरवर्ती बिक्री में प्रथम बार ही विपन्नो का हस्तांतरण होता है। इसी सदर्भ में E II फार्म के अन्दर 'प्रथम हस्तांतरणकर्ता' व 'द्वितीय हस्तांतरणकर्ता' शब्द प्रयोग किये गये हैं।

(३) उन सभी दस्तावेजो में जिनमें E I या E II फार्म के सर्टीफिकेट का आदान-प्रदान किया जाता है, प्रत्येक उस फार्म के साथ क्रेता व्यापारी से प्राप्त 'सी' फार्म नली किया जायेगा।



(४) जहाँ व्यापारी द्वारा धारा ६ (२) के अन्तर्गत बिक्री कर से छूट ली जाती है, वहाँ वह E I या E II फार्म को अपने अन्तिम कर-निर्धारण के पूर्व किसी भी समय कर-निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।

(५) उपनियम १ तथा २ के प्रयोजनार्थ एक पंजीयत व्यापारी अपनी आवश्यकतानुसार कर निर्धारक प्राधिकारी से E I तथा E II फार्म प्राप्त कर सकता है। उसे इन फार्मों का लेखा सी० एस० टी—४ (C. S. T.—4) फार्म के अनुसार सत्य व पूर्ण रूप से रजिस्टर में रखना पड़ेगा।

(६) पंजीयत बिक्रेता व्यापारी इन फार्मों की परिणामों को पाँच वर्ष तक अथवा ऐसे अन्य अधिक समय तक जो कि बिक्री-कर कमिश्नर ने निर्धारित किया हो, अपने पास रखेगा।

(७) यदि कर-निर्धारक प्राधिकारी चाहे तो वह E I तथा E II फार्मों की 'अनुलिपि' (Duplicate form) को निरीक्षण के लिये पंजीयत बिक्रेता व्यापारी से माँग सकता है।

(८) एक पंजीयत व्यापारी न तो किसी ऐसे E I व E II फार्मों में सर्टीफिकेट देगा और न वह स्वीकार ही करेगा जोकि कर-निर्धारक-प्राधिकारी से प्रार्थना-पत्र देकर न प्राप्त किये गये हों, अथवा जो बिक्री-कर कमिश्नर के द्वारा अवैध घोषित कर दिये गये हों।

(९) नियम १७ तथा १७ ए में जो नियम फार्मों की सुरक्षा, अनुरक्षण, हानि से बचाव, तथा नियत अधिकारी को प्रस्तुत के सम्बन्ध में दिये गये हैं, वे नियम इन सर्टीफिकेटों को भी लागू होंगे।

**परिवार, फर्म, संस्थाओं आदि के सम्बन्ध में घोषणा (Declaration in Case of Families, Firms, Associations etc)**

**नियम १८—**एक हिन्दू अविभाजित परिवार, संस्था, क्लब, सोसायटी, फर्म अथवा कम्पनी जो कि केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत कर देने की दायी है, तथा एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे व्यक्ति की ओर से एक अविभाजक अथवा प्रत्यासी की तरह व्यवसाय चलाता है तथा ऐसे व्यवसाय के सम्बन्ध में कर दायी है, कर-निर्धारक-प्राधिकारी को सी० एस० टी—२ (C. S. T.—2) फार्म में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा।

**अर्थ-दण्ड (Penalties)**

**नियम १९ :** कतिपय नियमों का उल्लंघन किया जाने पर अर्थ-दण्ड—जो कोई बिना उचित कारण के, तथा इन नियमों का उल्लंघन करते हुए, कोई हिसाब नहीं रखेगा, नवशा या १९८, प्रस्तुत नहीं करेगा, पंजीयन प्रमाण-पत्र को लटकाये नहीं रखेगा, कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा, या क्रेडिट नोट जारी नहीं करेगा, या उक्त अधिनियम या इन नियमों द्वारा यथाविधि प्राधिकृत निपदाधिकारी को प्रवेश या निरीक्षण नहीं करने देगा या हिसाब की किसी पुस्तक को सुरक्षित नहीं रखे तो वह, मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी सिद्ध किये जाने पर, ऐसे अर्थ-दण्ड से दंडनीय होगा जो ५००) ५० अधिक न हो और जब अपराध ऐसा हो जो लगातार किया जाता रहे तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जबकि ऐसा अपराध जारी रखा गया हो, ऐसे अर्थ-दण्ड से दंडनीय होगा जो कि ५० ५० से अधिक न हो।

**बिक्री-कर-प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति (Persons authorised to Appear before Sales Tax Authorities)**

**नियम २० :** कौन उपस्थित हो सकता है ?—कोई ऐसा व्यक्ति जो कि राज्य बिक्री-कर के अन्तर्गत किसी व्यापारी की ओर से बिक्री-कर प्राधिकारियों के समक्ष मुकद्दमे में उपस्थित होने के लिये

प्राधिकृत है, वह केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत भी उन प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने के लिये प्राधिकृत है।

### अन्य प्रावधान (Other Provisions)

**नियम २१ : कर का निर्धारण, उसकी वसूली तथा अदायगी (Assessment, collection and enforcement of payment of tax)**—यदि केन्द्रीय अधिनियम में तथा इन नियमों में कोई अन्य प्रावधान नहीं है तो केन्द्रीय कर का निर्धारण, कर की वसूली तथा कर की अदायगी को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में धारा ६ (२) के अनुसार वही तरीका होगा जो कि राज्य के बिक्री-कर-कानून में दिया हुआ है।

**नियम २२ : अपील, पर्यवेक्षण, पुनरीक्षण, सदर्थ आदि (Appeals, reviews, revisions, references etc.)**—केन्द्रीय कर के निर्धारण, उसकी वसूली तथा अदायगी से सम्बन्धित अपील, पर्यवेक्षण, पुनरीक्षण, सदर्थ आदि के बारे में धारा ६ (२) के अनुसार वही प्रावधान लागू होंगे जो कि राज्य-बिक्री-कर-कानून में दिये हुए हैं।

**नियम २३ : अपराधों पर अर्थ-दंड तथा राजीनामा (Penalties and Compounding of Offences)**—केन्द्रीय कर के निर्धारण, उसकी वसूली व अदायगी से सम्बन्धित जो अर्थ-दंड व राजीनामे के नियम हैं, वे धारा ६ (२) के अनुसार वही होंगे जो कि राज्य बिक्री-कर कानून में दिये हुए हैं।

## अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य में विशेष महत्व का माल

(Goods of Special Importance in Inter-State Trade or Commerce)

हम प्रथम अध्याय में पढ़ चुके हैं कि केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम १९५६ के बनाने का एक उद्देश्य यह भी था कि अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य में प्रयोग होने वाले कुछ प्रकार के माल को 'विशेष महत्व' का घोषित किया जाय तथा उन 'विशेष महत्व' वाले माल के सम्बन्ध में वे शर्तें तथा प्रतिबन्ध निर्धारित किये जाय जिनके अनुसार एक राज्य ऐसे माल की बिक्री व खरीद पर कर लगाने के लिए अपने नियम बना सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये धारा १४ के अन्तर्गत निम्न माल अन्तर्राज्यीय व व्यापार व वाणिज्य में विशेष महत्व का घोषित किया गया है —

(१) कोयला जिसमें सभी प्रकार का पत्थर का कोयला ( कोक ) सम्मिलित है।

(२) कपास, अर्थात् सभी प्रकार की कपास ( देशी या आयात की हुई ) जो कि अनिर्मित रूप में हो, चाहे बिनीले निकली हो अथवा नहीं, गांठों में बँधी हो अथवा नहीं, परन्तु इसमें कपास क्षय ( Cotton waste ) सम्मिलित नहीं है।

(२ अ) सूती बना हुआ कपड़ा ( Cotton fabrics ) जो कि केन्द्रीय एक्साइज एवं नमक अधिनियम १९४४ की प्रथम सूची की १२ वीं मद में वर्णित है

(२ ब) कपास का सूत, परन्तु उसमें सूत-क्षय ( yarn waste ) सम्मिलित नहीं है।

(३) पशु चर्म व खाल ( hides and skins ), चाहे कच्ची दशा में हो अथवा परिष्कृत ( dressed ) दशा में।

(४) लोहा एवं इस्पात, अर्थात्—

(अ) पिग आयरन व आयरन स्कैप।

(ब) रोलिंग मिल द्वारा जिस रूप में उत्पादित की गयी हैं, उसी रूप में बेची गई आयरन प्लेट्स

(स) स्टील स्कैप, स्टील इनगाट्स, स्टील बिलेट्स, स्टीन की छड़े व सरीये।

(द) १—स्टील प्लेट्स।

२—स्टील बील्स

३—स्टील बार तथा टिन बार ( छड़े )

४—रोल्लेड स्टील सेक्शन्स ( Rolled steel sections )

५—टूल एलॉय स्टील ( Tool Alloy steel )

{ रोलिंग मिल द्वारा जिस रूप में उत्पादित की गयी हैं, उसी रूप में बेची गयी।

(५) जूट, अर्थात् उन पौधों से निकाला गया छिलका जोकि *corchorus capsularis* एवं *corchorus obitoricns* विस्म के हो, तथा वे छिलके जो कि *inesta* व *himu* कहलाते हैं तथा *hibiscus cannabinus* व *hibiscus sabdariffa-varaltissima* विस्म के पौधों से निकाले गये हैं, चाहे वह जूट गाँठों में हो अथवा अन्य प्रकार से हो ।

(६) तेल के बीज अर्थात् वे बीज जो वाष्पशीलता रहित ऐसा तेल पैदा करते हो जो कि खाने के काम आता हो, अथवा उद्योग में, या वाणिज्य साधन आदि बनाने में अथवा चिकनाई के लिये काम आता हो, तथा वाष्पशील तेल जो कि दवाइयों में सुगन्धियों में, शृङ्गार-सामग्रियों आदि में काम आता हो ।

(७) रेयान ( Rayons ) अथवा कृत्रिम रेयान का कपड़ा जो कि केन्द्रीय एक्साइज एवं नमक अधिनियम १९४४ की प्रथम सूची की १२ ए ( 12 A ) मद में वर्णित है ।

(८) चीनी जो कि केन्द्रीय एक्साइज एवं नमक अधिनियम १९४४ की प्रथम सूची की ८ की मद में वर्णित है,

(९) तम्बाकू जो कि केन्द्रीय एक्साइज एवं नमक अधिनियम १९४४ की प्रथम सूची की ९ की मद में वर्णित है ।

(१०) ऊनी कपड़ा जो कि केन्द्रीय एक्साइज एवं नमक अधिनियम १९४४ की प्रथम सूची की १२ की मद में वर्णित है ।

धारा १५ के अनुसार—एक राज्य का प्रत्येक बिक्री-कर कानून, जहाँ तक कि वह घोषित माल की बिक्री व खरीद पर कर लगाता है अथवा कर का लगाना अधिकृत करता है, निम्नलिखित प्रतिबन्धों व शर्तों के आधीन होगा —

(अ) राज्य के अन्दर ऐसे माल की बिक्री व खरीद से सम्बन्धित उस कानून के अन्तर्गत दिया जाने वाला कर उस माल की बिक्री व खरीद के मूल्य के २% से अधिक नहीं होगा, तथा ऐसा कर एक स्थल ( stage ) से अधिक स्थलों पर नहीं लगाया जायेगा ।

(ब) जहाँ एक राज्य के अन्दर किसी घोषित माल की बिक्री व खरीद से सम्बन्धित उस कानून के अन्तर्गत एक कर लगाया गया है और ऐसा माल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत बेचा जाता है, तो वह कर जो कि लगाया जा चुका है उस व्यक्ति को ऐसे ढाँचे से तथा ऐसी शर्तों के आधीन लौटा दिया जायगा जो कि उस राज्य में लागू कानून के प्रावधानों में वर्णित हो ।

इस धारा की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं —

( i ) यह धारा उन शर्तों व प्रतिबन्धों को निर्धारित करने के लिए बनाई गयी है जिनके अनुसार एक राज्य ऐसे माल की बिक्री व खरीद पर कर लगाने के लिए अपने नियम बना सके ।

( ii ) एक राज्य सरकार इन घोषित माल की बिक्री व खरीद पर कर लगा सकती है यदि उस माल का क्रय व विक्रय राज्य के अन्दर ही हुआ हो । परन्तु शर्त यह है कि जो कर लगाया जाय, वह बिक्री या खरीद के मूल्य के २% से अधिक नहीं होना चाहिये, तथा वह कर एक ही स्थल पर लगाना चाहिये ।

- (iii) यदि किसी राज्य ने घोषित माल की बिक्री या खरीद पर कर लगा दिया है परन्तु बाद में वह माल अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत बेचा जाता है तो ऐसे माल पर दोहरा कर लग जायगा, अर्थात् एक कर राज्य बिक्री-कर कानून के अन्तर्गत तथा दूसरा कर केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत। इसीलिए धारा १५ (क) में कहा गया है कि उपरोक्त दशा में जो कर राज्य सरकार ने लगाया है वह कर राज्य सरकार द्वारा लौटा दिया जायेगा यदि वह माल बाद में अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत बेचा गया हो।
- (iv) निष्कर्ष यह है कि राज्य सरकार घोषित माल की बिक्री या खरीद पर २ प्रतिशत की दर अथवा उससे कम दर पर ही कर लगा सकती है बशर्ते माल की बिक्री राज्य के अन्दर ही हुई हो और वह माल राज्य में उपभोग के लिये काम आये।

### QUESTIONS

- 1 The enactment of the Central Sales Tax Act, 1956 has a historical background. Trace its history and state the causes of its enactment.
- 2 What are the objects of the Central Sales Tax Act? State the factors which led to the determination of those objects.
- 3 Define and discuss the following terms —  
(a) Dealer, (b) Goods, (c) Sale, (d) Turnover, (e) Year, (f) Declared Goods, (g) Appropriate State.
- 4 State the principles which have to be observed in deciding whether a sale of goods is effected outside the State or inside the State by a dealer. Is there any difference between the rates of tax paid on sales effected in the State and those on sales effected outside the State? (*Univ. of Raj. T. D. C. Com., 1962*)
- 5 Examine the provisions of Central Sales Tax Act, 1956 in regard to the rates of tax on sales in the course of inter-state trade and commerce. What principles are to be observed in deciding whether a sale of goods is effected outside the State or inside? (*Univ. of Raj. T. D. C. Com., 1961*)
- 6 When is a sale or purchase of goods said to take place in the course of import or export? Does such a sale attract Sales Tax? Give your views.
- 7 What is subsequent sale under sec. 6 (2)? Under what circumstances is such a sale exempt from Tax?
- 8 How can the dealers be registered under the Central Sales Tax Act? Is it compulsory for all the dealers to be registered under the Act? What benefits do the registered dealers obtain over the unregistered dealers? Explain.
- 9 Under what circumstances may the registration of a dealer be cancelled? Explain.
- 10 How do you decide the rates of tax on the sales effected in the course of inter-State trade and commerce? Discuss fully.
- 11 State the use of 'C' and 'D' forms in the inter-State and commerce.
- 12 Enumerate the goods mentioned under section 3 (3). What is the importance of these goods from the view point of sales tax levy?
- 13 How is the Central Sales Tax levied, assessed and collected? Mention the Sales Tax Authorities engaged in the above work.

14 Explain—

- (a) in which State the Central Sales Tax is levied and collected ?
- (b) which Government has the power to levy assess, enforce the payment of this tax ?

15 What are the rules adopted in Rajasthan for the enforcement of the Central Sales Tax Act in respect of the following —

- (a) Submission of Return of turnover by a dealer
- (b) Powers of the Officers
- (c) Loss of Declaration forms and the procedure to safeguard against the misuse of Declaration forms so lost
- (d) Certificates to be furnished under Section 6 (2)
- (d) Penalties

16 What goods are considered to be of special importance in the course of Inter State trade and Commerce ? Are there any restrictions in regard to tax on the sales or purchase of these goods within a State ?

## APPENDIX

### The Central Sales Tax (Registration & Turnover) Rules, 1957

#### FORM A

(See rule 3)

*Application for registration under Sect on 7 (1)/7 (2) of the Central Sales Tax Act, 1956*

To

\*I                      son of                      , on behalf of the dealer carrying on the business known as                      \*\*                      within the State of †                      hereby apply for a certificate of registration under Section 7 (1)/7 (2) of the Central Sales Tax Act 1956 and give the following particulars for this purpose

1. Name of the person deemed to be the manager in relation to the business of the dealer in the said State
2. Status or relationship of the person who makes this application (e.g. manager, partner proprietor, director, officer in charge of the Government business)
3. Name of the principal place of business in the said State and address thereof
4. Name(s) of the other place(s) in the said State in which business is carried on and address of every such place
5. Complete list of the warehouses in the said State in which the goods relating to the business are warehoused and address of every such warehouse
6. List of the places of business in each of the other States together with the address of every such place (if separate application for registration has been made or separate registration obtained under the Central Sales Tax Act, 1956, in respect of any such place of business, particulars thereof should be given in detail)

---

\* Here enter the authority specified in the general or special order issued by the Central Government under Section 7 (1) of the Act

\*\* Here enter the name and style under which the business is carried on

† Here enter the name of the State in which the application for registration is made

- 7 The business is—  
wholly  
mainly  
partly  
partly  
partly
- 8 Particulars relating to registration, licence, permission etc., issued under any law for the time being in force, of the dealer
- 9 We are members of<sup>2</sup>
- 10 We keep our accounts in \_\_\_\_\_ language and script
- 11 Name(s) and address(es) of the proprietor of the business/partners of the business—all persons having any interest in the business together with their age, father's name, etc

S No	Name in full	Father's/ husband's name	Age	Extent of interest in the business	Present address	Perma- nent address	Signature <sup>4</sup>	Signature and address of witness attesting signature in col II
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 12 Business in respect of which this application is made, was first started on \_\_\_\_\_
- 13 The first sale in the course of inter State trade was effected on \_\_\_\_\_
- 14 We observe the<sup>5</sup> \_\_\_\_\_ calendar and for purposes of accounts our  
year runs from the (English date)<sup>6</sup> \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ (Indian  
date)<sup>6</sup> \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ to the (English date/Indian

- Enter here whether business is wholly agriculture, horticulture, mining manu-  
facturing whole-sale distribution, retail distribution, contracting or catering, etc.,  
or any combination of two or more of them
- Here enter the name of the Chamber of Commerce, Trade Association or  
commercial body, of which the dealer is a member
- To be filled in if the applicant is not a company incorporated under the Companies  
Act, 1956 [1 of 1956] or under any other law
- Signature of each of the persons concerned should be obtained and attested
- Enter here English, Bengali, Faali, Hyja Marwari or other calendar followed
- In filling up these entries dealers who do not observe the English calendar, should  
give the dates according to their own calendar and the corresponding date of the  
English calendar Strike out portion or paragraph whichever is not applicable



- 15 We make up our accounts of sales to date at the end of every month/ quarter/ half year/year.
- 16 The following goods or classes of goods are purchased by the dealer in the course of inter State trade or commerce for—
- (a) resale
  - (b) use in the manufacture of processing of goods for sale .
  - (c) use in mining
  - (d) use in the generation or distribution of electricity or any other form of power
  - (e) use in packing of goods for sale/re-sale ]
- 17 We manufacture the following classes of goods, namely —
- 18 The above statements are true to the best of my knowledge and belief
- Name of the applicant in full  
Signature  
Status in relation to the dealer

Date

## THE CENTRAL SALES TAX (REGISTRATION AND TURNOVER)

RULES, 1957

FORM B

(See rule 5)

Certificate of Registration

No (Central)

This is to certify that<sup>1</sup> whose principal place of business within the State of ■ situated at ■ has been registered as a dealer under Section 7 (1)/7(2) of the Central Sales Tax Act, 1956

The business is—  
wholly<sup>2</sup>  
mainly  
partly  
partly  
partly

<sup>1</sup>[The class(es) of goods specified for the purposes of sub-sections (1) and (3) of Section 8 of the said Act is/are as follows and the sales of these goods in the course of inter State trade to the dealer shall be taxable at the rate specified in that sub-section subject to the provisions of sub-section (4) of the said section

- (a) for resale
- (b) for use in the manufacture of processing of goods for sale .
- (c) for use in mining

1 Subs by G S R 896, dated 23rd September, 1958

2 Here enter the name and style under which the business is carried on

3 Enter here whether business is wholly agriculture, horticulture, mining, manufacturing, wholesale distribution, contracting, or catering, etc., or any combination of two or more of them

Strike out whichever is not applicable

(d) for use in the generation or distribution of electricity or any other form of power

(e) for use in the packing of goods for sale/retale

The dealer manufactures processes, or extracts in mining the following classes of goods or generates or distributes the following form of power, namely—

The dealer's year for the purpose of accounts runs from \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ to the \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_

The dealer has no additional place of business/has additional place(s) of business as stated below

(a) in the State of registration

(b) in other States

The dealer keeps warehouses at the following place within the State of registration

(1)

(2)

(3)

The certificate is valid from \_\_\_\_\_ until cancelled

Signed

(Notified authority)

Date

(Seal)

\_\_\_\_\_

COUNTERFOIL	FORM C: The Central Sales Tax (REGISTRATION AND TURNOVER) RULES, 1957 Form 'C'	DUPLICATE	ORIGINAL
<p><b>The Central Sales Tax (REGISTRATION AND TURNOVER) RULES, 1957 Form 'C'</b></p> <p><i>Form of declaration [See Rule 12(1)]</i></p> <p>Name of issuing State Office of issue Date of issue</p> <p>Name of the purchasing dealer to whom issued along with his Registration Certificate No Date from which registration is valid</p> <p>Serial No</p> <p>To Seal of issuing authority</p> <p>Certified that the goods ordered for in our purchase order No dated</p> <p>purchased from you as per bill/cash memo stated below<sup>4</sup></p> <p>supplied under your chalan No dt are for resale</p> <p>use in manufacture/processing of goods for sale</p> <p>use in mining</p> <p>use in generation/distribution of power packing of goods for sale/resale and are covered by my/our registration certificate</p>	<p><b>The Central Sales Tax (REGISTRATION AND TURNOVER) RULES, 1957 Form 'C'</b></p> <p><i>Form of declaration [See Rule 12(1)]</i></p> <p>Name of issuing State Office of issue Date of issue</p> <p>Name of the purchasing dealer to whom issued along with his Registration Certificate No Date from which registration is valid</p> <p>Serial No</p> <p>To Seal of issuing authority</p> <p>Certified that the goods ordered for in our purchase order No dated</p> <p>purchased from you as per bill/cash memo stated below<sup>4</sup></p> <p>supplied under your chalan No dt are for resale</p> <p>use in manufacture/processing of goods for sale</p> <p>use in mining</p> <p>use in generation/distribution of power packing of goods for sale/resale and are covered by my/our registration certificate</p>	<p><b>The Central Sales Tax (REGISTRATION AND TURNOVER) RULES, 1957 Form 'C'</b></p> <p><i>Form of declaration [See Rule 12(1)]</i></p> <p>Name of issuing state Office of issue Date of issue</p> <p>Name of the purchasing dealer to whom issued along with his Registration Certificate No Date from which registration is valid</p> <p>Serial No</p> <p>To Seal of issuing authority</p> <p>Certified that the goods ordered for in our purchase order No dated</p> <p>purchased from you as per bill/cash memo stated below<sup>4</sup></p> <p>supplied under your chalan No dt are for resale</p> <p>use in manufacture/processing of goods for sale</p> <p>use in mining</p> <p>use in generation/distribution of power packing of goods for sale/resale and are covered by my/our registration certificate</p>	<p><b>The Central Sales Tax (REGISTRATION AND TURNOVER) RULES, 1957 Form 'C'</b></p> <p><i>Form of declaration [See Rule 12(1)]</i></p> <p>Name of issuing state Office of issue Date of issue</p> <p>Name of the purchasing dealer to whom issued along with his Registration Certificate No Date from which registration is valid</p> <p>Serial No</p> <p>To Seal of issuing authority</p> <p>Certified that the goods ordered for in our purchase order No dated</p> <p>purchased from you as per bill/cash memo stated below<sup>4</sup></p> <p>supplied under your chalan No dt are for resale</p> <p>use in manufacture/processing of goods for sale</p> <p>use in mining</p> <p>use in generation/distribution of power packing of goods for sale/resale and are covered by my/our registration certificate</p>

the Central Sales Tax Act, 1956 Name and address of the purchasing dealer in full Date	(Signature and status of the person signing the declaration)	Particulars of Bill/Cash Memo Date No Amount	3 Name and address of the seller with name of the State	4 Strike out whichever is not applicable (Note—To be retained by the purchasing dealer)
the Central Sales Tax Act, 1956 Name and address of the purchasing dealer in full Date	(Signature and status of the person signing the declaration)	2 Particulars of Bill/Cash Memo Date No Amount	3 Name and address of the seller with name of the State	4 Strike out whichever is not applicable (Note—To be retained by the selling dealer)
the Central Sales Tax Act, 1956 Name and address of the purchasing dealer in full Date	(Signature and status of the person signing the declaration)	2 Particulars of Bill/Cash Memo Date No Amount	3 Name and address of the seller with name of the State	4 Strike out whichever is not applicable (Note—To be retained by the selling dealer)

issued under  
the Central Sales Tax Act, 1956  
Name and address of the purchasing  
dealer in full  
Date

(Signature and status of the person  
signing the declaration)

2 Particulars of Bill/Cash Memo  
Date No Amount

3 Name and address of the seller with  
name of the State

4 Strike out whichever is not applicable  
(Note—To be furnished to the prescribed  
authority in accordance with the  
rules framed under section 13 (4)  
(c) by the appropriate State  
Government)

# FORM D'

**COUNTERFOIL**  
The Central Sales Tax  
(REGISTRATION AND TURNOVER)  
RULES 1957

**Form 'D'**  
*Form of Certificate for making Government purchases*  
[See (Rule 12 (1))]

(To be used when making purchases by Government not being a registered dealer)  
Central Government/Name of the State Government  
Name of the Issuing Ministry/Department  
Name and address of Office of Issue

To  
\*(Seller)

Certified that the goods  
\*ordered for in our purchase order No  
dated

purchased from you as per bill/cash  
memo stated below\*  
supplied under your chalan No  
dated are purchased by or on behalf  
of the Government of

Date  
Signature  
Designation of the  
authorised officer  
ment

**DUPLICATE**  
The Central Sales Tax  
(REGISTRATION AND TURNOVER)  
RULES, 1957

**Form D'**  
*Form of Certificate for making Government purchases*  
[See (Rule 12 (1))]

(To be used when making purchases by Government not being a registered dealer)  
Central Government/Name of the State Government  
Name of the Issuing Ministry/Department  
Name and address of Office of Issue

To  
\*(Seller)

Certified that the goods  
\*ordered for in our purchase order No  
dated

purchased from you as per bill/cash  
memo stated below\*  
supplied under your chalan No  
dated are purchased by or on behalf  
of the Government of

Date  
Signature  
Designation of the  
authorised officer  
ment

**ORIGINAL**  
The Central Sales Tax  
(REGISTRATION AND TURNOVER)  
RULES, 1957

**Form 'D'**  
*Form of Certificate for making Government purchases*  
[See Rule 12(1)]

(To be used when making purchases by Government not being a registered dealer)  
Central Government/Name of the State Government  
Name of the Issuing Ministry/Department  
Name and address of office of Issue

To  
\*(Seller)

Certified that the goods  
\*ordered for in our purchase order No  
dated

purchased from you as per bill/cash memo  
stated below\*

supplied under your chalan No  
dated are purchased by or on behalf  
of the Government of

Date  
Signature  
Designation of the  
authorised officer

of the Government of State of

of the Government	of the Government	of the Government
1 Name and address of the seller with name of the State	1 Name and address of the seller with name of the State	1 Name and address of the seller with name of the State
2 Strike out whichever is not applicable	2 Strike out whichever is not applicable	2 Strike out whichever is not applicable
3 Particulars of Bill/Cash Memo Date No Amount	3 Particulars of Bill/Cash Memo Date No Amount	3 Particulars of Bill/Cash Memo Date No Amount
(Note—To be retained by the authorised officer)	(Note—To be retained by the selling dealer)	(Note—To be furnished to the prescribed authority in accordance with the rules framed under section 13(3) by the appropriate State Government)

# FORM E-I

## COUNTERFOIL The Central Sales Tax (REGISTRATION AND TURNOVER) RULES 1957 Form E-I

### NAME OF STATE

Serial No

*Certificate under sub section (2) of Sec 6  
[See rule 12 (2)]*

[To be issued (in duplicate) (i) by the selling dealer who first moved the goods in the case of a sale falling under Section 3 (a) or (u) by the dealer who makes the first inter State sale during the movement of the goods from one State to another in the case of a sale falling under section 3 (b)]

- A Name of the selling dealer  
B (i) Name of the purchasing dealer  
(ii) Address (with name of State)

- C (i) Name of place and State in which movement commenced  
(ii) Name of place and State to which the goods have been consigned by the signatory

- D (i) Invoice No and date  
(ii) Description quantity and value of goods  
(iii) No and date of the declaration  
Form C received from purchasing dealer with name of State of issue

## DUPLICATE The Central Sales Tax (REGISTRATION AND TURNOVER) RULES 1957 Form E-I

### NAME OF STATE

Serial No

*Certificate under sub section (2) of Sec 6  
[See rule 12 (2)]*

[To be issued (in duplicate) (i) by the selling dealer who first moved the goods in the case of a sale falling under Section 3 (a) or (u) by the dealer who makes the first inter State sale during the movement of the goods from one State to another in the case of a sale falling under Section 3 (b)]

- A Name of the selling dealer  
B (i) Name of the purchasing dealer  
(ii) Address (with name of State)

- C (i) Name of place and State in which movement commenced  
(ii) Name of place and State to which the goods have been consigned by the signatory

- D (i) Invoice No and date  
(ii) Description, quantity and value of goods  
(iii) No and date of the declaration  
Form C received from purchasing dealer with name of State of

## ORIGINAL The Central Sales Tax (REGISTRATION AND TURNOVER) RULES 1957 Form E-I

### NAME OF STATE

Serial No

*Certificate under sub section (2) of Sec 6  
[See rule 12 (2)]*

[To be issued (in duplicate) (i) by the selling dealer who first moved the goods in the case of a sale falling under Section 3 (a) or (u) by the dealer who makes the first inter State sale during the movement of the goods from one State to another in the case of a sale falling under Section 3 (b)]

- A Name of the selling dealer  
B (i) Name of the purchasing dealer  
(ii) Address (with name of State)

- C (i) Name of place and State in which movement commenced  
(ii) Name of place and State to which the goods have been consigned by the signatory

- D (i) Invoice No and date  
(ii) Description quantity and value of goods  
(iii) No and date of the declaration  
Form C received from purchasing dealer with name of State of

(iv) No and date of the Railway  
Receipt/Trip sheet of lorry/for any  
other document or other means of  
transport

I/We the selling dealer(s) mentioned above  
do certify that I/we am/are registered  
under the Act and am/are holding re-  
gistration certificate No dated  
in the State of

I/We further certify that (i) I/we  
will pay/have paid tax under the Act,  
or (ii) no tax was payable under the  
Act in view of the general exemption  
referred to in sub section (2A) of  
Section 8, on the sale of the goods  
covered by document whose parti-  
culars are given above, to the appro-  
priate Sales Tax Authority of the  
State of

Signature

Place Status or relationship of the  
person (e.g., manager, part-  
ner, proprietor, director,  
officer-in charge of the Gov-  
ernment business)

Dated

Address  
(with name of the State)

N III --To be retained by the dealer issu-  
ing the certificate

(v) No and date of the Railway  
Receipt/Trip sheet of lorry/for any  
other document or other means of  
transport

I/We the selling dealer(s) mentioned above  
do certify that I/we am/are registered  
under the Act and am/are holding  
registration certificate No dated  
in the State of

I/We further certify that (i) I/we  
will pay/have paid tax under the Act,  
or (ii) no tax was payable under the  
Act in view of the general exemption  
referred to in sub section (2A) of  
Section 8, on the sale of the goods  
covered by documents whose parti-  
culars are given above, to the appro-  
priate Sales Tax Authority of the  
State of

Signature

Place Status or relationship of the  
person (e.g., manager, part-  
ner, proprietor, director,  
officer-in charge of the Gov-  
ernment business)

Dated

Address  
(with name of the State)

N B --To be retained by the dealer rece-  
iving the certificate

(vi) No and date of the Railway

Receipt/Trip sheet of lorry/for any  
other document or other means of  
transport

I/We the selling dealer(s) mentioned above  
do certify that I/we am/are registered  
under the Act and am/are holding  
registration certificate No dated  
in the State of

I/We further certify that (i) I/we will  
pay/have paid tax under the Act, or  
(ii) no tax was payable under the Act  
in view of the general exemption  
referred to in sub section (2A) of  
Section 8, on the sale of the goods  
covered by documents whose parti-  
culars are given above, to the appro-  
priate Sales Tax Authority of the  
State of

Signature

Place Status or relationship of the  
person (e.g., manager, part-  
ner, proprietor, director,  
officer in charge of the Gov-  
ernment business)

Dated

Address  
(with name of the State)

[Note--To be furnished to the prescribed  
authority in accordance with  
the rules framed under Section  
13 (3) by the appropriate State  
Government]



ORIGINAL

**The Central Sales Tax  
(REGISTRATION AND TURNOVER)  
RULES, 1957  
NAME OF STATE.**

**Form E-II**

*Serial No*  
*Certificate under sub section 2) of section 6*  
[See rule 12 (2)]

[To be issued (in duplicate) by the first or subsequent transfer in the series of sales referred to in Section 6 (2) (a) or second or subsequent transfer in the series of sales referred to in Section 6 (2) (b)]

**A** Name of the dealer effecting a sale by transfer of the documents of title to the goods

**B (i)** Name of the purchasing dealer

**(ii)** Address (with name of State)

**C (i)** Name of place and State in which movement commenced

**(ii)** Name of place and State to which the goods have been consigned

**D (i)** Invoice No and Date

**(ii)** Description, quantity and value of goods

**(iii)** No and date of the declaration Form 'C' received from purchasing dealer with name of State of issue

**(iv)** No and date of Railway Receipt/Trip sheet of lorry/or any other document

DUPLICATE

**FORM E II  
The Central Sales Tax  
(REGISTRATION AND TURNOVER)  
RULES, 1957  
NAME OF STATE.**

**Form E-II**

*Serial No*  
*Certificate under sub section 2) of Section 6*  
[See rule 12 (2)]

[To be issued (in duplicate) by the first or subsequent transfer in the series of sales referred to in Section 6 (2) (a) or second or subsequent transfer in the series of sales referred to in Section 6 (2) (b)]

**A** Name of the dealer effecting a sale by transfer of the documents of title to the goods

**B (i)** Name of the purchasing dealer

**(ii)** Address (with name of State)

**C (i)** Name of place and State in which movement commenced

**(ii)** Name of place and State to which the goods have been consigned

**D (i)** Invoice No and date

**(ii)** Description, quantity and value of goods

**(iii)** No and date of the declaration Form 'C' received from purchasing dealer with name of State of issue

**(iv)** No and date of the Railway Receipt/Trip sheet of lorry/or any other document

COUNTERFOIL

**The Central Sales Tax  
(REGISTRATION AND TURNOVER)  
RULES, 1957  
NAME OF STATE.**

**Form E-II**

*Serial No*  
*Certificate under sub section (2) of Section 6*  
[See rule 12 (2)]

[To be issued (in duplicate) by the first or subsequent transfer in the series of sales referred to in Section (2) a) or second or subsequent transfer in the series of sales referred to in Section 6 (2) (b)]

**A** Name of the dealer effecting a sale by transfer of the documents of title to the goods

**B (i)** Name of the purchasing dealer

**(ii)** Address (with name of State)

**C (i)** Name of place and State in which movement commenced

**(ii)** Name of place and State to which the goods have been consigned

**D. (i)** Invoice No and date

**(ii)** Depreciation, quantity and value of goods

**(iii)** No and date of the declaration Form 'C' received from purchasing dealer with name of State of issue

**(iv)** No and date of the Railway Receipt/Trip sheet of lorry/or any other document

<p>and am/are holding registration certificate No dated in the State of</p> <p>(b) I/we, having purchased the documents of title to the goods during their movement from one State to another referred to in item C above against a certificate No in Form E I/E-II, have now effected a subsequent sale during such movement by transferring the same in favour of the purchasing dealer whose address is given in the certificate</p> <p>*(c) [The dealer from whom I/we purchased the documents of title to the goods during the movement referred to in (b) above has certified (i) that he has paid/will pay the tax, or (ii) that the tax has been/will be paid by any of the preceding transferees of documents of title to goods or (iii) that no tax was payable under the Act in view of the general exemption referred to in sub section (2A) of Section 8]</p>	<p>Signature</p> <p>Status or relationship of the person (e.g., manager, partner proprietor, director, officer in charge of the Government business)</p> <p>Dated</p> <p>Address (with name of the State)</p> <p>Note—To be retained by the prescribed authority in accordance with the rules framed under Section 13(3) by the appropriate State Government</p>
<p>and am/are holding registration certificate No dated in the State of</p> <p>(b) I/we, having purchased the documents of title to the goods during their movement from one State to another referred to in item C above against a certificate No in Form E I/E-II, have now effected a subsequent sale during such movement by transferring the same in favour of the purchasing dealer whose address is given in the certificate</p> <p>*(c) [The dealer from whom I/we purchased the documents of title to the goods during the movement referred to in (b) above, has certified (i) that he has paid/will pay the tax, or (ii) that the tax has been/will be paid by any of the preceding transferees of documents of title to goods or (iii) that no tax was payable under the Act in view of the general exemption referred to in sub section (2A) of Section 8]</p>	<p>Signature</p> <p>Status or relationship of the person (e.g., manager, partner proprietor, director, officer in charge of the Government business)</p> <p>Dated</p> <p>Address (with name of the State)</p> <p>N II — To be retained by the dealer receiving the certificate</p>
<p>and am/are holding registration certificate No dated in the State of</p> <p>(b) I/we, having purchased the documents of title to the goods during their movement from one State to another referred to in item C above against a certificate No in Form E I/E-II, have now effected a subsequent sale during such movement by transferring the same in favour of the purchasing dealer whose address is given in the certificate</p> <p>*(c) [The dealer from whom I/we purchased the documents of title to the goods during the movement referred to in (b) above has certified (i) that he has paid/will pay the tax, or (ii) that the tax has been/will be paid by any of the preceding transferees of documents of title to goods or (iii) that no tax was payable under the Act in view of the general exemption referred to in sub section (2A) of Section 8]</p>	<p>Signature</p> <p>Status or relationship of the person (e.g., manager, partner proprietor, director, officer in charge of the government business)</p> <p>Dated</p> <p>Address (with name of the State)</p> <p>N II — To be retained by the dealer issuing certificate</p>

FROM C 5 T 1

(See Rule 4)

Form of return of Turnover under the Central Sales Tax Act, 1956

Return for the period from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ Registration  
Mark and No \_\_\_\_\_ (Central) Name of the dealer  
Status \_\_\_\_\_

(Whether individual Hindu  
undivided family, associa  
tion club firm company  
guardian or trustee )

Style of the business \_\_\_\_\_

1 Gross amount received or receivable Rs n P  
by the dealer during the period in  
respect of sales of goods

DEDUCT— Rs nP

(i) Sales of goods outside the State  
(as defined in section 4 of the  
Central Act

(u) Sales of goods in course of export  
outside India (as defined in  
section 5 of the Central Act)

2 Balance—turnover on inter-State  
sales and sales within the State

DEDUCT Turnover on sales within the  
State

3 Balance—Turnover on inter State  
sales

DEDUCT—Cost of freight delivery or  
installation when such cost  
is separately charged

4 Balance—Total turnover on inter- Rs n P  
State sales

DEDUCT—Subsequent sales not taxable  
under sec 6 (2) of the Act

5 Goodswise break up of above

A Declared goods—

(i) sold to registered dealers on pres  
cribed declaration (vide declara  
tion attached)

(u) sold otherwise

**B Other goods—**

(i) sold to registered dealers on prescribed declarations (vide declarations attached)

(ii) sold others etc

Total —

6	(i) Taxable at	% Rs	on which tax amounts to Rs
	(ii) ,	% Rs	Rs
	(iii) ,,	% Rs	Rs
	(iv) ,,	% Rs	Rs
	(v) ,	% Rs	Rs
	(vi)	% Rs	Rs

7 Total tax payable on Rs amounts to Rs

8 Tax paid, if any, by means of Treasury }  
challan / M O No dated Rs nP

9 Balance due excess paid if any Rs nP

**10 Declaration —**

(1) I, enclose with this return the original copy of each of the declarations received by me in respect of sales made to registered dealers together with a signed list of such declarations

(2) I declare that the statements made and particulars furnished in and with this return are true and complete

*Place*

*Signature*

*Date*

*Status*

**ACKNOWLEDGEMENT**

Received from  
tion Certificate No  
the period from  
mentioned therein

a dealer possessing Registra  
a return of Sales Tax payable by him for  
to with enclosures

*Receiving Officer*

*Place*

*Date*

**FORM C T T 2**

(See Rule 18)

**Declaration in case of Families, Associations, Firms etc**

With reference to rule 18 of the Central Sales Tax (Rajasthan) Rule 1957, it is hereby declared that Shri \_\_\_\_\_ shall be declared to be the Manager in relation to the business in the State of Rajasthan of the dealer mentioned below —

- 1 Name of the dealer
- 2 Nature of business
- 3 Address
- 4 The dealer is a

Hindu Undivided Family\*  
 Association\*  
 Firm\*  
 Club\*  
 Society\*  
 Company\*

Concern in which business is carried on by Shri  
 ■ a guardian or trustee or otherwise on behalf of Shri

\*Strike off the portion  
 inapplicable

*Signature and Status of the person  
 signing the declaration*

*Date*      ..

**Note** —The declaration is to be signed —

- (i) in the case of a Hindu undivided family, by all the adult members thereof
- (ii) in the case of an association by all members of its governing body,
- (iii) in the case of a club, by all members of its governing body
- (iv) in the case of a society, by all members of its governing body,
- (v) in the case of a firm by all its partners,
- (vi) in the case of a company, by its managing director or managing agent,
- (vii) in other cases, by the guardian or trustee or other person, carrying on business on behalf of another person, and also by the person on whose behalf the business is carried on, if not under disability

**Register of Declaration Forms maintained under Rule 17 of the Central Sales Tax (Rajasthan) Rules, 1957**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Remarks
Date of receipt.	Authority from whom received	Book No	Serial No to	Date of issue	Book No	Serial No	Name and address of seller to whom issued	No and date of order in respect of which issued	Description of goods in respect of which issued	Value of the goods	Seller's cash memo/ challan No in reference to which issued	No and date of railway receipt or other carriers challan for the goods	Surrendered to (Sales Tax Authority)		

1057

Register of Certificate in form EI/T-II maintained under Rules 17(c) of the

[illegible]

## Particulars to be maintained in Inter State Sales Register

Serial No	Seller's invoice No and date	Name of the State from which goods have been despatched	Name of the State to which the goods have been despatched	Name address and Registration No of the purchasing dealer with name of the State	Name and date of the order of the purchas- ing dealer	Description of the goods sold quantity etc	Goods sold to registered dealers					Goods sold to unregi- stered dealer or for other purpose	Sales Price	Amount of Sales Tax collected		Remarks
							For resale	For use in manu- facturing or processing of goods for resale	For mining	For generation and distribution of power	with Form C			without form C		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	



les Tax Department

Form C S. T 5

RECEIPT—(to be given  
to the depositor for  
retention by him)

## S TAX CHALLAN

Sales Tax (a) Taxes under  
the Central Sales Tax Act

Na the sum of Rs (in words)

of the following —

Rs nP

on Fee

h Fee

on Money

revision

period

on/Licence No

llan No

19

Treasurer

ury/Bank  
stamp

surey Officer,  
Treasury

ank of Ltd

O for instructions )

Sales Tax Department

Form C S T 5

Part IV—RECEIPT—(to be given  
to the depositor for  
transmission to the Sales  
Tax Officer/Asstt Sales  
Tax Officer )

## SALES TAX CHALLAN

XII—A Sales Tax (a) Taxes under  
the Central Sales Tax Act

Treasury

Sub Treasury

Received the sum of Rs (in words)

on account of the following —

Rs nP

Registration Fee

Exemption Fee

Tax

Penalty

Composition Money

Fee for Revision

for the period

due from

Registration/Licence No

Vide Challan No

Date 19

Date

Treasurer

Treasury/Bank  
Stamp

Treasury Officer,  
Sub-Treasury

Agent, Bank of Ltd